कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 64 अंक : 2 पृष्ठ : 52 दिसंबर 2017 मूल्य : ₹ 22

ग्रामीण पर्यटन

प्रधानमंत्री ने उमंग एप शुरू किया

डिजिटल तकनीक के जरिए कुशल सेवाएं देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 नवंबर, 2017 को उमंग एप लांच किया। इसका उद्देश्य एक ही मोबाइल एप पर 162 सरकारी सेवाओं को लाना है, ताकि देश के नागरिकों की मोबाइल फोन के जरिए सरकार तक पहुंच सुलभ हो।

उमंग (UMANG यूनिफाइड मोबाइल एप फॉर न्यू–ऐज गर्वमेंट) एक नजर में –

- सभी सरकारी सेवाओं में एकरूप यूजर सहज इंटरफेस
- 33 विभागों तथा चार राज्यों की 162 सेवाएं/एप्लीकेशन
- 13 भारतीय भाषाओं में समर्थित और मांग पर उपलब्ध
- यूएसएसडी के माध्यम से बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले फीचर फोनों पर भी जल्द उपलब्ध होगा
- कई ग्राहक केंद्रित सेवाओं जैसे आधार और डिजीलॉकर के साथ जुड़ाव की सुविधा
- स्मार्ट फोन, डेस्कटॉप और टेबलेट जैसे अनेक चैनलों पर उपलब्ध
- उमंग के लिए सप्ताह के सभी दिन सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक कस्टमर सपोर्ट सेवा उपलब्ध।

प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में साइबर स्पेस पर आयोजित पांचवें वैश्विक सम्मेलन के दौरान उमंग एप लांच किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री रानिल विक्रमसिंघे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस पांचवे सम्मेलन का थीम **सभी के लिए साइबर : सतत विकास के लिए सुरक्षित और समावेशी साइबर स्पेस** था। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय नीति–निर्धारकों, उद्योग विशेषज्ञों, विचारकों तथा साइबर विशेषज्ञों ने साइबर स्पेस से संबंधित विषयों और चुनौतियों पर विचार–विमर्श किया।

प्रधानमंत्री ने वैश्विक साइबर चुनौती **'पीस–ए–थॉन'** के विजेताओं को भी सम्मानित किया। 'पीस–ए–थॉन' में भारत, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया तथा अल्जीरिया की सैंकड़ों टीमों ने हिस्सा लिया। ❑

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 64★ मासिक अंक : 2★ पृष्ठ : 52 ★ अग्रहायण–पौष 1939★ दिसंबर 2017

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 0 03
दूरभाष : 011–24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना
सज्जा
मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति	:	22 रुपये
विशेषांक	:	30 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	230 रुपये
द्विवार्षिक	:	430 रुपये
त्रिवार्षिक	:	610 रुपये

इस अंक में

भारत में ग्रामीण पर्यटन में संभावनाएं — रश्मि वर्मा — 5
ग्रामीण पर्यटन : विकास और विस्तार की ओर — मधुरा रॉय — 8
समग्र विकास के साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत संजोता ग्रामीण पर्यटन — भुवन भास्कर — 12
राष्ट्रीय पर्यटन नीति और ग्रामीण पर्यटन — ऋषभ कृष्ण सक्सेना — 16
ग्रामीण पर्यटन : बुनियादी संरचना और क्षमता निर्माण — डॉ. सुयश यादव — 21
ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के प्रयास — हेना नक़वी — 25
ग्रामीण पर्यटन में रोजगार के अवसर — हरिकिशन शर्मा — 29
भारत में ग्रामीण पर्यटन संसाधनों का विकास जरूरी — शिशिर सिन्हा — 32
कृषि पर्यटन : गांवों में पर्यटन का नया आकर्षण — सुरेंद्र प्रसाद सिंह — 36
पूर्वोत्तर में समुदाय-आधारित ईको पर्यटन — डॉ. प्रदीप कुमार मुखर्जी — 40
ग्रामीण पर्यटन और स्वच्छता — धीप्रज्ञ द्विवेदी — 45
पर्यटन पर्व 2017 — --- — 49
विश्व शौचालय दिवस (19 नवंबर, 2017) — --- — 50

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

भारत की विविधता, अनेकता और परिपूर्णता इसे एक ऐसा गुलदस्ता बनाते हैं जोकि हर प्रकार के रंग–बिरंगे पुष्पों से सुशोभित है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां इतनी भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता देखने को मिले। हरे–भरे खेत, हिमखंड, मरुभूमि, सागर के लहरों की अठखेलियां, प्राकृतिक परिवेश सब कुछ तो है जोकि पर्यटकों को आकर्षित करता है। देश के सुदूर गांवों में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है।

भारत के गांव हमेशा से अपनी लोककलाओं और हस्तशिल्पों के लिए विख्यात रहे हैं। यहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्रकृति के सानिध्य में खुला वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर खींचने के लिए पर्याप्त है। यही सब कारक भारत में ग्रामीण पर्यटन को विपुल संभावनाओं वाला क्षेत्र बना देते हैं।

गांवों के देश भारत में ग्रामीण पर्यटन संपन्नता के द्वार खोल सकता है। जहां एक तरफ यह ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार का एक उत्तम माध्यम बनेगा, वहीं दूसरी ओर विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और जीवनशैली के लोगों को एक–दूसरे के करीब लाकर हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा।

लेकिन ग्रामीण पर्यटन के विकास में कई चुनौतियां भी हैं। पहली यह कि पर्यटकों में (और खुद ग्रामीणों में) इसके बारे में जागरूकता की कमी है। किसी गांव में बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल हो सकता है, पर गांव वालों को खुद आभास नहीं होता कि वह स्थल पर्यटन का केंद्र बनकर उनके आर्थिक–सामाजिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है।

ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए सबसे जरूरी है, ग्रामीणों के बीच जागरूकता बढ़ाना और देश–विदेश में ग्रामीण पर्यटन की कुशल मार्केटिंग। सफल मार्केटिंग रणनीति से ग्रामीण पर्यटन की मांग तेजी से बढ़ेगी। साथ ही, हमें अपना आधारभूत ढांचा भी विकसित करना होगा। ताकि जब पर्यटक भारत के गांवों में जाएं, तो उनके लिए सड़कें हो; ठहरने का साफ–सुंदर स्थान हो, स्थानीय टूरिस्ट गाइड हों जो उन्हें वहां के दर्शनीय स्थल दिखा सकें।

भारत सरकार इस ओर पूरी तरह से सजग है। प्रधानमंत्री स्वयं अपने भाषणों में अकसर पर्यटन विकास के महत्व पर बोलते हैं। इसी हेतु 'स्वदेश–दर्शन' योजना प्रारम्भ की गई है जिसमें थीम–आधारित तेरह पर्यटन सर्किट विकसित किए जाएंगे– ग्रामीण सर्किट भी इन तेरह सर्किटों में से एक है।

पर्यटन को पूर्ण विकसित करने के लिए केवल भौतिक अवसंरचना काफी नहीं है बल्कि इसके लिए सक्षम मानव संसाधन भी उतने ही जरूरी हैं। इसके लिए ग्रामीण युवकों को आचार–व्यवहार के बारे में प्रशिक्षित करना होगा ताकि वे पर्यटकों से प्रभावी संवाद कर सकें। साथ ही, अपने आतिथ्य के लिए मशहूर भारतीय ग्रामीणों को यह प्रशिक्षण देना होगा कि वे कैसे एक पर्यटक द्वारा उनके गांव में बिताए पलों को यादगार बना सकें ताकि वह पर्यटक न केवल खुद फिर लौट कर आए, बल्कि औरों को भी साथ लाए।

एक गांव को एक सुरक्षित और आनंदमयी पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने के लिए वहां के स्थानीय समुदायों की भागीदारी अति आवश्यक है। इसके लिए सरकार, एनजीओ, पंचायत, सामुदायिक संगठन सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। गांव में स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) के जरिए भी स्थानीय कलाओं, शिल्पों का विकास किया जा सकता है।

अंत में हम कह सकते हैं कि विश्व में तेजी से बढ़ती शहरी आबादी शहरों के कोलाहल और थकान भरे माहौल से कुछ पल गांवों के शांत और सुरभित वातावरण में जरूर बिताना चाहेगी– यही ग्रामीण पर्यटन के लिए सबसे बड़ी संभावना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रामीण पर्यटन से स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और गांवों का चहुंमुखी विकास होगा।

भारत में ग्रामीण पर्यटन में संभावनाएं

–रश्मि वर्मा

प्रेम के शाश्वत प्रतीक ताजमहल से लेकर दक्षिण भारत के मंदिरों और राजस्थान के भव्य किलों जैसे स्मारक देश भर में फैले हुए हैं। इसी तरह बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, घने जंगल, सुनहरे तट और रेतीले मरुस्थल भारत को पर्यटकों के लिए सही मायने में 'अतुल्य' गंतव्य बनाते हैं। चिकित्सा, आरोग्य और गोल्फ जैसे खेलों के खास मकसद से यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए भी भारत के पास देने को बहुत कुछ है।

समूचे विश्व में आज पर्यटन उद्योग विचार और मान्यताओं की दृष्टि से बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। लोगों की क्रयशक्ति में भारी बढ़ोतरी और यात्रा के तेज व सस्ते साधनों के उपलब्ध हो जाने से अब लोग अधिक संख्या में देश–विदेश की यात्राएं करने लगे हैं। इस तरह की यात्राओं का उद्देश्य आमतौर पर फुर्सत के पलों का आनंद उठाना होता है। वैसे अब ऐसे लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है जो नई–नई बातें जानने–समझने और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों, खानपान के तौर–तरीकों, परम्पराओं आदि का अनुभव प्राप्त करने के लिए सैर–सपाटे पर निकलते हैं। इस तरह की यात्राओं को 'अनुभवमूलक यात्राओं' के रूप में जाना जाता है। आज के विचारशील पर्यटक पूरी जांच–पड़ताल के बाद सैर–सपाटे के लिए दूरदराज की अनजान जगहों की यात्राएं करने को उत्सुक रहते हैं ताकि उन्हें अनोखा यात्रा अनुभव हासिल हो। अब पर्यटक ज्यादा जिम्मेदार भी हो गए हैं और जहां की यात्रा पर जाते हैं वहां के जन समुदाय को अपने सुखद अनुभवों के बदले में कुछ लौटाना चाहते हैं। वे मेजबान समुदाय से संवाद स्थापित करना चाहते हैं ताकि उस क्षेत्र के विकास में कुछ भागीदारी निभा सकें।

जैसाकि हम सब जानते ही हैं, भारत में पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण के केन्द्र दूर–दूर तक फैले हैं और उनमें व्यापक विविधताएं हैं। हमारी अति प्राचीन सामासिक संस्कृति ही पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। हमारे देश में पर्यटन स्थलों की कोई कमी नहीं है। प्रेम के शाश्वत प्रतीक ताजमहल से लेकर दक्षिण भारत के मंदिरों और राजस्थान के भव्य किलों जैसे स्मारक देश भर में फैले हुए हैं। इसी तरह बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, घने जंगल, सुनहरे तट और रेतीले मरुस्थल भारत को पर्यटकों के लिए सही मायने में 'अतुल्य' गंतव्य बनाते हैं। चिकित्सा, आरोग्य और गोल्फ जैसे खेलों के खास मकसद से यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए भी भारत के पास देने को बहुत कुछ है।

महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत गांवों में बसता है। भारत का ग्राम्य जीवन 'असली भारत' की तस्वीर प्रस्तुत करता है। हमारे गांव देश की संस्कृति और परम्पराओं का खजाना हैं। महानगरों की गहमा–गहमी से दूर गांवों में जीवन को अपेक्षाकृत सहज गति से जीने का अनुभव मन में नई स्फूर्ति का संचार करता है। हमारी अनोखी कलाओं और शिल्प के सिद्धहस्त कलाकार और

दस्तकार गांवों में ही निवास करते हैं और कलाओं व शिल्प को अपने मूल रूप में अब तक सहेज कर रखे हुए हैं। ये कलाएं व शिल्प शहरों में मुश्किल से ही दिखाई पड़ती हैं। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आमतौर पर कृषक समाज के लोग हैं और कई बार उनकी आमदनी शहरों में रहने वालों की तुलना में कम होती है। गांवों में पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं और बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों को पलायन करने वाले युवक–युवतियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नतीजा यह हुआ है कि गांवों की कुछ परम्परागत कलाएं और शिल्प धीरे–धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं।

ग्रामीण पर्यटन एक ऐसा समाधान है जो ऊपर उठाए गए सभी सवालों के उत्तर दे सकता है। इस तरह के पर्यटन में पर्यटक ग्रामीण जीवनशैली में सक्रिय होकर भागीदारी निभाते हैं। वे किसी ग्रामीण स्थान तक पहुंचते हैं और गांव की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में भाग लेते हुए वहां के जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। इससे उन्हें उस क्षेत्र की परंपराओं और संस्कृति को आत्मसात करने का अवसर भी प्राप्त होता है। ग्रामीण पर्यटन में पर्यटक रात को गांव में ठहरता है जिससे उसे गांव की अनोखी जीवनशैली की झलक बहुत नजदीक से देखने को मिलती है। इससे ग्रामीण समाज को भी फायदा होता है क्योंकि आमतौर पर खेती या कम कौशल वाले व्यवसायों पर निर्भर इन लोगों को पर्यटन से अपनी आमदनी बढ़ाने का अवसर मिलता है। ग्रामीण पर्यटन से गांव के लोग मेहमानों की संस्कृति के संपर्क में आते हैं जिससे उनकी जानकारियों के दायरे का विस्तार होता है और वे पर्यटक की संस्कृति की भी कुछ बातों को ग्रहण कर सकते हैं। ग्रामीण पर्यटन के कई मामलों में स्वैच्छिक सेवा का पुट भी रहता है और पर्यटक स्थानीय स्कूल में पढ़ाकर या खेती–बाड़ी में हाथ बंटाकर स्थानीय लोगों की मदद भी करते हैं।

पर्यटकों को नए तरह का अनुभव दिलाने के लिहाज से पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन बड़ा उपयोगी पाया है। इसके अलावा पर्यटन उत्पादों में विविधता लाने, ग्रामीण समुदाय की आमदनी बढ़ाने और लुप्त होती जा रही ग्रामीण कला विधाओं के संरक्षण में भी ग्रामीण पर्यटन से बड़ी मदद मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से 2003–04 में देशभर के 31 गांवों में परीक्षण परियोजना के तौर पर एंडोजीनस टूरिज्म प्रोजेक्ट यानी अंतर्जात पर्यटन परियोजना शुरू की गई। इसके लिए गांवों का चयन सुस्थापित टूरिस्ट सर्किटों से उनकी निकटता और किसी अनोखी कला/शिल्प या संस्कृति की उपस्थिति को ध्यान में रखकर किया गया ताकि उस जगह की विशिष्टता के रूप में बाजार में उसका लाभ उठाया जा सके। बाद में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के परियोजना से अलग हो जाने पर भी पर्यटन मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धन देना जारी रखा और उत्पाद अवसंरचना विकास तथा स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के जरिए परियोजना चलती रही।

ग्रामीण पर्यटन मॉडल की कई गौरव गाथाएं सामने आई हैं और इसके अंतर्गत कई परियोजनाएं वित्तीय दृष्टि से व्यावहारिक साबित हो रही हैं। इनमें से उल्लेखनीय हैंः गुजरात में होडका गांव में शाम–ए–सरहद परियोजना। शाम–ए–सरहद एक पर्यटक शिविर का नाम है जिसका निर्माण, स्वामित्व और प्रबंधन होडका समुदाय के पास है। पर्यटन जन समुदायों को अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में सक्षम बनाता है। ऐसा आजीविका के और अधिक विकल्प मिलने से होता है और साथ ही इससे स्थानीय समुदाय को अपनी अनोखी संस्कृति के विकास और संरक्षण का भी अवसर प्राप्त होता है।

कई अन्य राज्यों ने भी अब इस अवधारणा को अपना लिया है। ग्रामीण पर्यटन के मॉडल के विकास में केरल हमेशा अग्रणी रहा है और राज्य में 'उत्तरदायी पर्यटन' के वृहत्तर दायरे में ग्रामीण पर्यटन का विकास किया गया है। केरल में कुमारकोम, वायनाड और अन्य स्थानों पर उत्तरदायी पर्यटन की पुरस्कृत परियोजनाएं एक अनोखे मॉडल के रूप में उभर कर सामने आई हैं। इनमें आगंतुकों को ग्रामीण जीवन का आनंद लेने का मौका मिलता है और पर्यटन से जुड़े स्थानीय लोग कथा सुनाने वाले सूत्रधार की भूमिका में रहते हैं। इससे गांव के लोगों में ग्रामीण जीवन के अपने तौर–तरीकों के बारे में गौरव की भावना पैदा होती है। यही भावना उन्हें अपने परम्परागत तौर–तरीकों पर कायम रहने और शहरी जीवनशैली की नकल करने से रोकती है।

एक अन्य प्रेरक कथा सिक्किम से है जहां कई ग्रामीण समुदायों को सशक्त

बनाकर होम स्टे यानी पर्यटकों को घर में ठहराने के कार्यक्रमों के जरिए पर्यटक उत्पादों का परम्परागत पर्यटन स्थलों से हटकर अन्य स्थानों पर भी समान रूप से विस्तार करने का प्रयास किया गया है। इससे पर्यटन उत्पादों की क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिली है। भारत के पहले आर्गेनिक राज्य के रूप में ख्याति अर्जित करने के बाद सिक्किम अपनी ग्रामीण पर्यटन क्षमताओं का भी भरपूर फायदा उठा रहा है। विकास के इस तरह के मॉडलों में समाज के सबसे निचले स्तर पर सामुदायिक भागीदारी होती है और हर एक व्यक्ति को समूची प्रक्रिया में बराबरी का अवसर मिलता है।

सरकारी प्रयासों की सफलता के बाद निजी क्षेत्र की तरफ से भी कुछ उल्लेखनीय पहल की गई हैं। समोद और मंडावा सहित राजस्थान में सार्वजनिक–निजी भागीदारी के मॉडल पर आधारित कुछ परियोजनाएं सामने आयी हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में गोवर्धन इको–विलेज भी उल्लेखनीय है जिसने पिछले साल नवसृजन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन का यूलीसीज पुरस्कार जीता। इस संगठन ने गांव को एक ऐसे समुदाय के रूप में विकसित किया है जिसका पर्यटकों के साथ एक–दूसरे पर आश्रित सहजीवी संबंध है। इसने सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाया है और एक जमाने में पिछड़े हुए इस इलाके के लोगों की आमदनी और शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने में मदद की है।

इसलिए देशभर में ग्रामीण पर्यटन और ग्राम जीवन के अनुभव की अवधारणा के विकास के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। फिर भी, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं और सबसे बड़ी चुनौती तो मार्केटिंग यानी विपणन की है। ग्रामीण समुदायों के पास स्वाभाविक रूप से उत्पादों की देश–विदेश में मार्केटिंग के लिए बहुत कम अवसर होते हैं। इसलिए विपणन का पर्याप्त आधारभूत ढांचा न होने से जो परियोजनाएं पारम्परिक पर्यटन सर्किट से जुड़ी नहीं हैं, वे बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पायी हैं। पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन–स्थलों को अपनी वेबसाइट में प्रमुखता से स्थान देकर ग्रामीण पर्यटन के विपणन के प्रयासों में अपना योगदान किया है। केरल का ग्रामीण पर्यटन मिशन राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे सफल विपणन प्रयासों का एक अन्य उदाहरण है। टूर आपरेटरों को अंततः ग्रामीण पर्यटन स्थलों को संरक्षण देना ही होगा और उन्हें वित्तीय दृष्टि से सफल बनाने के लिए अपनी यात्रा–सूची में शामिल करना होगा। इसलिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर इस तरह के और प्रयास करने की आवश्यकता है।

महात्मा गांधी का एक और उद्धरण है : ''अगर गांव नष्ट हो गए तो भारत नष्ट हो जाएगा''। इसलिए हमारे लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि गांवों का संरक्षण किया जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए गांवों की सरल जीवनशैली को संभाल कर रखा जाए। ग्रामीण और उत्तरदायी पर्यटन से इस परम्परा को बचाए रखने में बड़ी मदद मिल सकती है।

(लेखिका भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय में सचिव हैं।)
ई–मेल : sectour@nic.in

ग्रामीण पर्यटन : विकास और विस्तार की ओर

–मधुरा रॉय

ग्रामीण भारत के पास लोगों को देने के लिए बहुत कुछ है। इन क्षेत्रों की पहचान करने और इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं खोजने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के एकजुट प्रयासों की आवश्यकता है। देश में ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने पर ही ग्रामीण पर्यटन का विस्तार और विकास हो सकता है।

रोजमर्रा की नीरस जिंदगी से फुर्सत के कुछ क्षण हमेशा मूड बेहतर बनाने का काम करते हैं। आमतौर पर लोग इस फुर्सत का इस्तेमाल यात्राएं और नए स्थान खोजने के लिए करते हैं। परंतु, लक्ष्य का चयन करने में समय और खर्च की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यस्त पर्यटक मौसम के दौरान परंपरागत पर्यटक स्थलों पर आमतौर पर भारी भीड़ होती है। आज अधिकतर समाज शहरीकृत हो चुका है। ऐसे में ग्रामीण पर्यटन शहरी आबादी के बीच निरंतर लोकप्रिय हो रहा है।

दुनिया की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही है। यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह अनुपात 2050 तक बढ़कर 66 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। संयुक्त राष्ट्र डीईएसए की जनसंख्या डिवीजन द्वारा व्यक्त की गई 'विश्व शहरीकरण संभावनाएं' (2014) के अनुसार शहरीकरण में सर्वाधिक बढ़ोतरी भारत, चीन और नाइजीरिया में होगी। वर्ष 2014 से 2050 के दौरान विश्व की शहरी आबादी में होने वाली अनुमानित वृद्धि में 37 प्रतिशत हिस्सेदारी इन तीन देशों की होगी। अनुमान है कि 2050 तक भारत में शहरी निवासियों में 40.4 करोड़, चीन में 29.2 करोड़ और नाइजीरिया में 21.2 करोड़ की बढ़ोतरी होगी।

ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा

भारत सरकार ने ग्रामीण पर्यटन की परिभाषा में स्पष्ट किया है कि ''कोई भी ऐसा पर्यटन, जो ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और ग्रामीण स्थलों की धरोहर को दर्शाता हो, जिससे स्थानीय समुदाय को आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचता हो, साथ ही, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच संवाद से पर्यटन अनुभव के अधिक समृद्ध बनने की संभावना हो, तो उसे 'ग्रामीण पर्यटन' कहा जा सकता है। ग्रामीण पर्यटन अनिवार्यतः एक ऐसी गतिविधि है, जो देश के देहाती इलाकों में संचालित होती है। यह बहु–आयामी है, जिसमें खेत/कृषि पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, प्रकृति पर्यटन, साहसिक पर्यटन और पर्यावरण पर्यटन शामिल हैं। परंपरागत पर्यटन के विपरीत, ग्रामीण पर्यटन की कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे यह अनुभव–उन्मुखी होता है, इसके पर्यटक स्थलों पर आबादी बिखरी हुई होती है, इसमें प्राकृतिक वातावरण की प्रमुखता होती है, यह त्योहारों और स्थानीय उत्सवों से सराबोर होता है और संस्कृति, धरोहर और परंपरा के संरक्षण पर आधारित होता है।'' भारत में पर्यटन मंत्रालय ने ऐसे ग्रामीण पर्यटक स्थलों के विकास पर विशेष बल दिया है, जो समृद्ध कला, संस्कृति, हथकरघा, धरोहर और शिल्प की दृष्टि से गौरवशाली हों। ये गांव प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक वैभव दोनों ही दृष्टियों से समृद्ध हैं। ग्रामीण पर्यटन से यह उम्मीद की जाती है कि ग्रामीण उत्पादकता, ग्रामीण पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण, स्थानीय लोगों की भागीदारी की दृष्टि से ग्रामीण इलाकों के लाभ में वृद्धि हो और परंपरागत विश्वासों और आधुनिक मूल्यों के बीच उपयुक्त अनुकूलन में मदद मिले।

भारत में ग्रामीण पर्यटन के प्रमुख प्रकार

कृषि पर्यटनः कृषि उद्योग और फसलें उगाने के लिए किसान कैसे काम करते हैं, के बारे में अधिक जाानकारी प्राप्त करना।

संस्कृति पर्यटनः पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति विषयक गतिविधियों जैसे अनुष्ठानों और उत्सवों में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान करना।

प्रकृति पर्यटनः ऐसे प्राकृतिक स्थलों की जिम्मेदारी के साथ यात्रा करना, जो पर्यावरण का संरक्षण करते हैं और स्थानीय लोगों के कल्याण में सुधार लाते हैं।

साहसिक पर्यटनः कोई भी ऐसी रचनात्मक गतिविधि साहसिक पर्यटन के अंतर्गत शामिल है, जो किसी व्यक्ति की क्षमता और अंतिम सीमा तक उसकी तैयारी का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करती है।

भोजन पर्यटनः जहां पर्यटकों को हमारे व्यंजनों की विविधता का आनंद लेने का अवसर मिलता है। इस तरह का पर्यटन भोजन और विभिन्न स्थानों के प्रमुख भोजनों की जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है।

समुदाय पारिस्थितिकी पर्यटनः यह ऐसा पर्यटन है, जो किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। यह वास्तव में ऐसे प्राकृतिक स्थलों की जिम्मेदारीपूर्ण यात्रा है, जो पर्यावरण संरक्षण करते हैं और स्थानीय लोगों की खुशहाली में सुधार लाते हैं।

नृजातीय पर्यटनः इसका उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों के क्षितिजों का विस्तार करना है। इसका अनिवार्य लक्ष्य विभिन्न जातीय और सांस्कृतिक जीवनशैलियों और विश्वासों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है।

ग्रामीण पर्यटन में बढ़ती रूचि

ग्रामीण पर्यटन कृषि, खेती, स्थानीय शासन आदि के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद करता है। ग्रामीण पर्यटन ग्रामीण जीवनशैली के बारे में ऐसे भ्रम दूर करने में सहायक है, जो सामान्यतः शहरी लोगों को होते हैं, जैसे ग्रामीण लोगों का अस्वास्थ्यकर वातावरण में रहना, या ग्रामीण जीवन असुरक्षित होना आदि।

ग्रामीण पर्यटन किसी व्यक्ति को भारत के सुदूर भागों में व्याप्त विविधता की खोज करने का अवसर प्रदान करता है।

भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रम

पर्यटन मंत्रालय ने ऐसे अनेक स्थानों की पहचान की है, जिसका विकास ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटक लक्ष्यों के रूप में किया जा रहा है। ये ऐसे स्थान हैं, जो अभी तक पर्यटन की दृष्टि से अज्ञात रहे हैं। ऐसे पर्यटक स्थलों के समग्र विकास में मदद करने के लिए मंत्रालय ने विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

विषय–आधारित सर्किटों के समेकित विकास के लिए स्वदेश दर्शन कार्यक्रम

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर पर्यटन और रोजगार सृजन के विकास के व्यापक अवसर प्रदान करती है। इस क्षमता की समुचित पहचान के लिए केंद्र सरकार ने 2014–15 के बजट में खास विषयों के बारे में पर्यटक सर्किटों का निर्माण करने का ऐलान किया।

प्रसाद : यानी पिल्ग्रिमेज रिज्यूवनेशन फॉर स्प्रिचुअल ओगमेंटेशन ड्राइव अर्थात् आध्यात्मिक संवर्धन के लिए तीर्थयात्रा नवीनीकरण अभियान

तीर्थाटन पर्यटन का एक ऐसा रूप है, जो आंशिक या पूर्ण रूप में धार्मिक भावनाओं को प्रेरित करता है। भारत अनेक धर्मों का देश है, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इसाई धर्म, जैन धर्म और सूफी धर्म। इन सभी धर्मों के देश के विभिन्न भागों में प्रमुख तीर्थस्थल हैं। धर्म और आध्यात्मिकता यात्रा के लिए समान रूप से प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि प्रमुख पर्यटक लक्ष्यों का विकास उनके धार्मिक स्थलों, व्यक्तियों और घटनाओं से जुड़े होने के कारण हुआ है।

विशेष पर्यटन अंचल

वर्ष 2017–18 के आम बजट में 5 विशेष पर्यटन अंचलों की घोषणा की गई, जहां राज्यों की भागीदारी के साथ विशेष प्रयोजन उद्यमों की स्थापना की जाएगी। इससे दूसरे वैश्विक अतुल्य भारत अभियान की शुरुआत करने में मदद मिलेगी, ताकि आकर्षक पर्यटन लक्ष्य के रूप में भारत की स्थिति सुदृढ़ की जा सके।

ई–पर्यटक वीजा सुविधा

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ मिल कर काम कर रहा है ताकि देश में एक निश्चित अवधि के दौरान वीजा व्यवस्था को आसान बनाया जा सके। ग्रामीण पर्यटन को आकर्षक बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय एक विशेष उत्पाद के रूप में फार्म पर्यटन को प्रोत्साहित कर रहा है। मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में ठहरने की व्यवस्था 'होम स्टे' को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

ग्रामीण पर्यटन का प्रभाव

रचनात्मक प्रभाव

बढ़ते ग्रामीण पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ग्रामीण भारत में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ लोगों के बीच व्यापार का स्तर बढ़ने से उनकी आय का स्तर भी बढ़ेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

किसी भी स्थान के परंपरागत हथकरघा और हस्तशिल्प स्थानीय लोगों के लिए गौरव का विषय होते हैं। पर्यटन के माध्यम से पर्यटकों को स्थानीय लोगों से तैयार उत्पाद सीधे खरीदने का लाभ प्राप्त होता है। इसका समूची अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्यटकों के साथ विचारों के आदान–प्रदान से ग्रामीण लोगों में नए विचार सृजित होंगे। इससे शिक्षा, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, आधुनिक उपकरणों आदि के प्रति लोगों की रूचि बढ़ेगी। इससे साक्षरता का सर्वत्र प्रसार करने में भी मदद मिलेगी।

अधिकाधिक पर्यटकों द्वारा गांवों की यात्रा करने से सड़कों के माध्यम से संपर्क में सुधार आएगा और सार्वजनिक परिवहन में बढ़ोतरी होगी। अभ्यारण्यों और सुरक्षित उद्यानों के निकट रहने वाले ग्रामीण अपने शहरी सहभागियों को प्रकृति के संरक्षण की

शिक्षा दे सकते हैं। सदियों से प्रकृति की शरण में रहने के कारण उन्हें प्रकृति के संरक्षण के तौर–तरीकों की जानकारी निश्चित रूप से अधिक होती है।

पर्यटक स्थानीय धार्मिक और परंपरागत अनुष्ठानों में रूचि विकसित कर सकते हैं, जो सामाजिक सद्भाव के प्रेरक के रूप में काम कर सकती है।

नकारात्मक प्रभाव

परंतु, ग्रामीण पर्यटन पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। पर्यटन के लिए सुविधाएं जुटाने से देहात में बुनियादी ढांचे के विकास में बढ़ोतरी होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में कंकरीट बढ़ेगा, जिससे उनका प्राकृतिक सौंदर्य कम हो सकता है। इसके अलावा, पर्यटकों की बढ़ती संख्या से प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी हो सकती है।

पर्यटन का लोगों की परंपरागत जीविका पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ग्रामीण आबादी कृषि और अन्य परंपरागत जीविका माध्यमों की बजाए पर्यटन से संबद्ध आकर्षक जीविका माध्यमों में स्थानांतरित हो सकती है। इससे ग्रामीण पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

सुधार की संभावनाएं

जीवन के प्रत्येक पहलू के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। स्थायी विकास के लिए यह जरूरी है कि रचनात्मक प्रभाव अधिक हों और नकारात्मक प्रभाव कम पड़ें। यही बात ग्रामीण पर्यटन पर भी लागू होती है।

पर्यटक ग्रामीण क्षेत्रों में सहज महसूस करें, इसके लिए उन्हें उनके गंतव्य स्थान के बारे में पहले से ही विस्तृत जानकारी प्रदान की जा सकती है। उन्हें किसी क्षेत्र में प्रचलित विशेष रीति–रिवाजों की भी जानकारी दी जा सकती है ताकि वे तदनुरूप अपने को तैयार कर सकें।

गांवों में बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन या राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़कों की व्यवस्था से गांवों तक पहुंच में सुधार किया जा सकता है। इससे पर्यटकों के साथ–साथ ग्रामवासियों को भी लाभ पहुंचेगा, परंतु यह बेहतर होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा संख्या में होटल या गेस्ट हाउस बनाने की बजाए होम–स्टे (घरों में ठहरने की सुविधा) को तरजीह दी जाए। इससे पर्यटकों को ग्रामीण भारत में प्रचलित स्थानीय व्यंजनों के साथ–साथ परंपरागत पद्धतियों का भी जायका मिलेगा। इससे पर्यटकों को कम समय में ग्रामवासियों के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां और जीव–जंतु विद्यार्थियों के लिए सीखने का अच्छा स्रोत हो सकते हैं। विद्यार्थियों को भ्रमण की अनुमति सक्षम प्राधिकारियों की समुचित मंजूरी के बाद दी जा सकती है। इस तरह विद्यार्थी प्रकृति को महत्व देना सीखेंगे।

पर्यटन के मामले में भाषा एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। अतः कठिनाई होने की स्थिति में पर्यटकों को दुभाषिए रखने का विकल्प दिया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए दुभाषियों को प्रशिक्षित और योग्य बनाने की आवश्यकता है।

भारत के अधिकतर गांवों की पारंपरिक पहचान है, जो उन्हें बेजोड़ बनाती है। ऐसे अनेक परंपरागत उत्पादों को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान करते हुए मान्यता दी गई है। इनमें कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, वस्त्र उत्पाद, मिठाइयां, प्राकृतिक वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं, पवित्र वस्तुएं आदि शामिल हैं। इन सभी जीआई टैगयुक्त उत्पादों को हमेशा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित किया जाता है और उनकी बाजार में भारी मांग रहती है। सरकार यह सुनिश्चित करने के उपाय कर सकती है कि पर्यटक इन उत्पादों के बनने, पैक किए जाने और प्रदर्शित किए जाने की समूची प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें। इससे पर्यटकों में रूचि और बढ़ेगी और अंततः ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। भारत के अनेक राज्य जड़ी–बूटियों और अन्य आयुर्वेदिक उत्पादों की दृष्टि से संपन्न हैं, जो चिकित्सा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सरकार ऐसे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त ढांचे का विकास कर सकती है, जो भारत के गांवों में उपचार सुविधाएं पाने के इच्छुक हों।

जहां तक ग्रामीण पर्यटन का प्रश्न है, राज्य सरकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राज्य सरकार की पर्यटकों को आकर्षित करने की पृथक क्षमता है। अतः यह जरूरी है कि राज्य सरकारें अपनी इस क्षमता की पहचान करें और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करें। इससे समूचे देश को पर्यटन क्षेत्र में लाभ पहुंचेगा।

पर्यटकों को इस बात की अग्रिम जानकारी दी जा सकती है कि वे ऐसे स्थानीय मुद्दों में न उलझें, जिनसे कानून–व्यवस्था की समस्याएं पैदा होने की आशंका हो। सरकार पर्यटकों के बीच सर्वेक्षण करा सकती है और उनके लक्षित पर्यटक–स्थल के बारे में उनकी भावनाएं जान सकती है। उनके फीडबैक के आधार पर पर्यटन में सुधार लाने के उपाय किए जा सकते हैं।

कुछ लोकप्रिय ग्रामीण पर्यटक स्थल

कच्छ एडवेंचर्स इंडिया : कच्छ में सामुदायिक पर्यटनः गुजरात में कच्छ के रण की यात्रा से पर्यटकों को कारीगरों के गांव और साल्ट डेजर्ट देखने के अवसर मिलेंगे।

इत्मिनान लॉजेज़ पंजाबियत : ग्रामीण पंजाब में खेतीः पर्यटक विभिन्न खेती गतिविधियों का जायजा ले सकते हैं।

इकोस्फीयर स्पीति : उच्च तुंगता ग्रामीण पर्यटनः बौद्ध मठों की यात्राएं, याक सफारी, गांवों की यात्राएं, ग्रामीण पारिवारिक शैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि संभावित गतिविधियां हो सकती हैं।

लाचेन, सिक्किमः यह बर्फ से ढकी चोटियों, हिम नदियों

और रॉक क्लिप्स के बीच 8500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके चारों ओर मिश्रित शंकु वृक्षों और बुरुंश (एक प्रकार का फल) के जंगल हैं। यह स्थल पर्यटकों के लिए कुछ वर्ष पहले ही सुगम हुआ है। अतः अपनी अदोहित ताजगी बनाए हुए है।

बल्लभपुर डांगा, पश्चिम बंगालः बल्लभपुर डांगा शांति निकेतन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह संथाल आदिवासी जनजातीय समुदाय से संबद्ध है, जो ग्रामीण बंगाल के चारागाही सौंदर्य को दर्शाता है। इसके पूर्व में सोनाझुरी वन है और दक्षिण में बल्लभपुर अभयारण्य वन क्षेत्र तथा पक्षी अभयारण्य हैं। संथाली कला, शिल्प और संस्कृति समुदाय के जीवन का हिस्सा हैं।

सुंदरबन विलेज लाइफः यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जहां दुनिया में सबसे अधिक मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है। यह पर्यटकों के लिए अत्यंत आकर्षक स्थल है।

असम में माझुलीः असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना सबसे बड़ा माझुली नदी द्वीप अत्यंत लोकप्रिय पर्यटक स्थल है।

पोचमपल्ली, तेलंगानाः पर्यटक इसी नाम से जानी जाने वाली रेशम की मशहूर साड़ियों के बुनने की प्रक्रिया देख सकते हैं।

ऐसे अनेक और भी स्थल हैं, जिन्हें सूची में शामिल किया जा सकता है, जो अभी तक पर्यटकों के लिए अज्ञात हैं।

निष्कर्ष

मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, ''अन्य देशों में मैं एक पर्यटक के रूप में जा सकता हूं, परंतु भारत में मैं एक तीर्थयात्री हूं।'' उनका यह कथन महात्मा गांधी के इस कथन से मिलता–जुलता है, ''हम एक ग्रामीण सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। हमारे देश की विशालता, जनसंख्या का विस्तार, देश की अवस्थिति और जलवायु, मेरे विचार में ये सभी इसे एक ग्रामीण सभ्यता बनाते हैं।'' ग्रामीण भारत के पास लोगों को देने के लिए बहुत कुछ है। इन क्षेत्रों की पहचान करने और इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं खोजने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के एकजुट प्रयासों की आवश्यकता है। देश में ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने पर ही ग्रामीण पर्यटन का विस्तार और विकास हो सकता है।

(लेखिका भारतीय सांख्यिकी सेवा से संबद्ध हैं और वर्तमान में नीति आयोग, नई दिल्ली में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी हैं।)
ईमेल : madhuraroy@gmail.com

स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2018

प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत के विज़न पर काम करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, (एआईसीटीई) इंटर–इंस्टीट्यूशनल इनक्लुसिव इनोवेशन सेंटर (आई4सी) और पर्सिस्टेंट सिस्टम ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 का आयोजन किया है। हमारे देश के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए नए और क्रांतिकारी डिजिटल प्रौद्योगिकी नवाचारों की पहचान करने के लिए यह अनूठी पहल की गई है। 2017 में आयोजित पहले हैकाथॉन को मिली अपार सफलता को देखते हुए इस प्रयास को दोहराते हुए दूसरा स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2018 प्रस्तावित किया गया है।

स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2018 में 2 उप–संस्करण होंगे–

सॉफ्टवेयर के साथ–साथ हार्डवेयर भी

- सॉफ्टवेयर संस्करण में 36 घंटे का सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रतिस्पर्धा होगी जोकि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 की अवधारणा पर ही आधारित होगी।
- नया हार्डवेयर संस्करण एक ऐसा हैकाथॉन होगा जहां टीमें 5 दिनों के लिए काम करेंगी और अपने हार्डवेयर समाधान प्रस्तुत करेंगी। यह प्रतियोगिता केवल 5 नोडल केंद्रों तक सीमित होगी जहां प्रत्येक केंद्र में 20–25 टीमें भाग लेंगी।
- भाग लेने के लिए https://innovate.mygov.in/sih2018/ पर लॉग–इन करें।

भाग लेने के लिए अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2017 है।

समग्र विकास के साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत संजोता ग्रामीण पर्यटन

– भुवन भास्कर

पर्यटन की यह नई शाखा, जिसे ग्रामीण पर्यटन कहते हैं, धीरे–धीरे अपना खास स्थान बना रही है। न केवल सरकारों के लिए, बल्कि निजी क्षेत्र के लिए भी। दरअसल ग्रामीण पर्यटन भले ही टूरिज्म सेक्टर की एक शाखा भर मालूम देता हो, लेकिन इसके फायदों को यदि बारीकी से समझा जाए, तो इसका असर कहीं ज्यादा व्यापक और गहरा होता है। ग्रामीण पर्यटन का फलक हिल स्टेशनों और धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के केंद्रों के पर्यटन से कहीं ज्यादा जटिल, प्रभावकारी और व्यापक है। आइए देखते हैं कि ग्रामीण पर्यटन क्यों केवल आमदनी बढ़ाने के तौर पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी समग्र विकास का एक प्रभावी माध्यम हो सकता है।

ग्रामीण पर्यटन या रूरल टूरिज्म का दौर देश के लिए बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अब यह तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। पर्यटन एक उद्योग के तौर पर वैसे भी देश और विभिन्न राज्य सरकारों के लिए प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर है क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा योगदान हासिल होता है।

ग्रामीण पर्यटन दरअसल अपने आप में भी एक विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें कई प्रकार का पर्यटन शामिल होता है। मोटे तौर पर इसके तहत दो तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं, पहला फार्म टूरिज्म यानी वह सेटअप जिसमें पर्यटकों को खेती के तौर–तरीकों का अनुभव कराया जाता है और दूसरा, रूरल टूरिज्म यानी वह व्यवस्था जिसमें पर्यटक ग्रामीण जनजीवन को महसूस करते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कई सारे थीम हो सकते हैं। जैसे, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में नग्गर गांव महिला सशक्तीकरण के एक आदर्श पोस्टर के तौर पर चर्चित हुआ है, वहीं गुजरात के कच्छ में होडका गांव को पर्यटन से आय बढ़ाने के एक मॉडल की पहचान मिली है। पंजाब में अमृतसर से दो घंटे की दूरी पर विकसित एक केंद्र ग्रामीण पर्यटन का ऐसा स्वरूप पेश करता है, जहां पर्यटकों को ट्रैक्टर की सवारी से लेकर, हल चलाने और गाय का दूध दुहने तक का अनुभव समेटने का मौका मिलता है। तो जाहिर है कि ग्रामीण पर्यटन का फलक हिल स्टेशनों और धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के केंद्रों के पर्यटन से कहीं ज्यादा जटिल, प्रभावकारी और व्यापक है। आइए देखते हैं कि ग्रामीण पर्यटन क्यों केवल आमदनी बढ़ाने के तौर पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी समग्र विकास का एक प्रभावी माध्यम हो सकता है:

1. सामाजिक प्रभावः ग्रामीण पर्यटन गांव के लोगों को बाहरी दुनिया से जोड़ने का एक बहुत ही सरल और सशक्त माध्यम है। जब शहरी और विदेशी पर्यटक गांवों में आते हैं, तब वे अपने साथ अलग–अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों, सोच और नजरियों की छाप भी लेकर आते हैं। इनसे संपर्क में आने के कारण न केवल ग्रामीणों का सामाजिक–सांस्कृतिक दायरा फैलता है, बल्कि पर्यटक भी उस स्थान की लोकभाषा, लोक संस्कृति, रहन–सहन और सोच का प्रभाव अपने साथ लेकर लौटते हैं। किसी देश की सांस्कृतिक विरासत को फैलाने के लिए ग्रामीण पर्यटन से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता।

जब विदेशी पर्यटक किसी गांव में पर्यटक के तौर पर जाते हैं और आरती के साथ लोकनृत्य के जरिए उनका स्वागत होता है, आग्रहपूर्वक उन्हें एक पंक्ति में बिठाकर खिलाया जाता है, तो उस अनुभव को वे विदेशी ताउम्र अपने मन में संजोकर हमेशा के लिए देश के सांस्कृतिक राजदूत का काम करते हैं। इसलिए

ग्रामीण पर्यटन सोच और समझ को व्यापक बनाने में दोतरफा तौर पर काम करता है।

2. बुनियादी ढांचागत विकासः जब हम ग्रामीण पर्यटन की बात करते हैं, तो दरअसल हम स्थान और परिवेश की बात करते हैं। क्योंकि इन दोनों के अलावा व्यवस्था और प्रबंधन के लिहाज से ग्रामीण पर्यटन में शहरों की ही तरह पर्यटकों की सुविधा और सुख का ख्याल रखना होता है। इसके लिए ग्रामीण पर्यटन का केंद्र बनाने वाले गांव में एक स्वस्थ और सुविधायुक्त जीवन के लिहाज से बुनियादी ढांचा विकसित करना होता है। वहां तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें तैयार करनी होती हैं। पीने का शुद्ध पानी और बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करनी होती है। इन व्यवस्थाओं को तैयार करने के सिलसिले में न केवल पर्यटन का केंद्र बनने वाला गांव, बल्कि नजदीक के बड़े शहर से वहां तक के बीच में पड़ने वाले सारे भू–भाग को इसका फायदा होता है। अच्छी सड़कें बनने से वह इलाका शहरों से सीधे जुड़ता है और बिजली की आपूर्ति बेहतर होने से छोटे–छोटे कई उद्योग–धंधे भी विकसित होते हैं।

3. आर्थिक प्रभावः यह किसी भी पर्यटन का सबसे दृश्य प्रभाव है। ग्रामीण पर्यटन में इसका सीमांत महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि वहां लोगों के पास आय को बढ़ाने के साधन सीमित होते हैं। यह प्रभाव सबसे अहम रोजगार के क्षेत्र में नजर आता है क्योंकि इसमें सेवा क्षेत्र से जुड़े कई रोजगार पैदा होते हैं। साथ ही, ग्रामीण उद्यमियों के लिए कम निवेश में अपना कारोबार खड़ा करने का भी यह शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। शहर से पर्यटन केंद्र बने गांव तक पर्यटकों को लाने–ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तैयार करने से लेकर उनके भोजन, निवास और मनोरंजन तक के प्रबंध में कई छोटे–बड़े ऐसे मौके खड़े होते हैं, जहां जुड़कर गांववासी अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इनके अलावा, जहां बड़े निवेश की जरूरत होती है, वहां बाहर से भी पूंजी, नए आइडिया और नए व्यवसायी आते हैं, जिससे रोजगार के मौके पैदा होते हैं।

नए कारोबार और नए रोजगार के साथ ग्रामीण पर्यटन नई दक्षताएं भी विकसित करता है। प्रशिक्षण और जागरूकता के कारण ग्रामीणों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) जैसी कुलीन क्षमताएं भी पैदा करता है। इससे कुल मिलाकर वहां के समाज की योग्यता में बढ़ोतरी होती है और उसकी आजीविका का दायरा बढ़ता है। साथ ही पर्यटन–जनित रोजगार में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के बराबर या कई जगहों पर कहीं ज्यादा होती है। इससे भी एक ओर तो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ने से उनके सशक्तीकरण को काफी बल मिलता है, वहीं उन्हें सामाजिक सम्मान भी हासिल होता है।

4. सांस्कृतिक प्रभावः पर्यटकों के लिए ग्रामीण पर्यटन का सबसे बड़ा आकर्षण गांवपना होता है। गांव में एक कुम्हार का काम देखने का इच्छुक पर्यटक मोटर से चल रही चक्की पर बन रहे बर्तनों के लिए शायद एक ढेला भी खर्च न करे। उसे लुभाने के लिए एक कुम्हार की कला का सजीव प्रदर्शन चाहिए। इसी तरह अलग–अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक विशेषता को जाहिर करने वाली वेशभूषा, केश–सज्जा, आभूषण इत्यादि जो अब धीरे–धीरे आधुनिकता की चमक में गंवारपन की निशानी करार देकर धीरे–धीरे लुप्तप्राय हो रहे थे, अब एकाएक सजीव होने लगे हैं। पूरा राजस्थान ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जहां सांस्कृतिक विरासत की धरोहरों की उधड़ती परतों को पर्यटन की गोंद ने फिर से चिपकाया है और पर्यटकों की रुचियों ने जिन पर रंग–रोगन किया है। इस सांस्कृतिक संरक्षण का एक अभिन्न हिस्सा गांववासियों में उनकी ऐतिहासक विरासत को लेकर पैदा होने वाला गौरव–भाव है, जो पर्यटकों के लिए उनके 'गांवपन' को और ज्यादा नैसर्गिक और आकर्षक बनाता है।

इनके अलावा पर्यावरण संरक्षण जैसे कुछ वे फायदे भी हैं, जो सीधे तौर पर कम दिखते हैं, लेकिन जिनकी अहमियत काफी है। गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक माहौल कायम रखने की कोशिश की जाती है। हरियाली और पेड़–पौधों का संरक्षण किया जाता है और जंगल कायम कर पर्यटकों को प्रकृति से करीबी अनुभव कराया जाता है। ये सारी कोशिशें आखिरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

अब एक नजर डालते हैं देश में मौजूद ग्रामीण पर्यटन के कुछ नामचीन केंद्रों पर और ऊपर बात किए गए फायदों और असर को व्यावहारिक अर्थों में समझने की कोशिश करते हैं:

- गुजरात के कच्छ के रण में 'कच्छ एडवेंचर्स इंडिया' ग्रामीण पर्यटन का एक शानदार नमूना है। साल में लगभग साढ़े तीन महीने तक चलने वाले 'रण उत्सव' के नाम से विख्यात इस पर्यटन मेले में देश–विदेश से आने वाले पर्यटकों को एक ही जगह गुजरात के तमाम कलाकारों की जीवंत कलात्मकता देखने को मिल जाती है। दूर–दूर तक फैले श्वेत मरुस्थल के एक कोने पर बसे मिट्टी के घरों में रहने और तारों से भरी रात में साफ आसमान के नीचे चारपाई पर सोने का अनुभव यहां आने वाले पर्यटकों के दिल में गुजरात को हमेशा जिंदा रखता है। खास बात यह है कि ये पूरा आयोजन होडका गांव की ग्राम पर्यटन समिति द्वारा ही चलाया जाता है।
- हिमाचल प्रदेश की स्पिति घाटी अपने यहां आने वाले पर्यटकों को बौद्ध मठों, विलेज ट्रेकिंग, याक सफारी, विलेज होमस्टे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार सौगात देती है। यहां के पर्यटन कार्यक्रमों का आयोजन करने वाला इकोस्फेयर स्पिति संगठन यहां के स्थानीय समुदायों के साथ काफी गहराई से जुड़ा है और उनके साथ मिलकर ही सारी व्यवस्था करता है। इससे न केवल पर्यटकों को हिमाचल और लद्दाख की एक समन्वित संस्कृति का अनूठा अनुभव होता है, बल्कि स्थानीय समुदायों की आर्थिक–सामाजिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव संभव हुआ है।
- पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय विरासत

सुंदरबन, पश्चिम बंगाल

वाली जगह घोषित किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव जंगल है, जहां के बाघ अपने आकार और भव्यता के लिए खास जाने जाते हैं। सुंदरबन के भारतीय हिस्से में 102 द्वीप हैं, जिनमें से केवल आधे से कुछ ज्यादा ही आबाद हैं। यहां का ग्रामीण जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहां न तो पीने के पानी की उपलब्धता है, न बिजली, रोड और गाड़ियां हैं। लोग मिट्टी और फूस के बने घरों में रहते हैं और निरंतर बाघों के हमले के साये में जीते हैं। सुंदरबन के ऐसे जंगलों में कई इको रिसॉर्ट हैं, जो स्थानीय समुदायों द्वारा चलाए जाते हैं। इस विशेष रिसॉर्ट में स्थानीय स्टाइल में बनी छह झोपड़ियां हैं, जो धान के खेतों से घिरी हैं। यहां रहने वाले पर्यटक ग्रामीण गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं और देसी नावों में बैठकर पतले घुमावदार जलमार्गों में अद्भुत अनुभव ले सकते हैं।

- ग्रामीण पर्यटन का किसी जगह की कला पर असर देखना हो, तो कांगड़ा घाटी के गुनेहर गांव में देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के इस गांव में जर्मन मूल के भारतीय कला प्रेमी फ्रैंक श्लिष्टमैन ने एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसने देखते–देखते हुए इस भूले–बिसरे गांव को एक प्रसिद्ध कला केंद्र में बदल दिया। इस गांव में आज एक आर्ट गैलरी, कारोबारियों के 70 पुराने घरों का जीर्णोद्धार कर बनाया गया इकोलॉजिकल बूटिक, गेस्टहाउस और एक फ्यूजन रेस्टोरेंट है। यहां अक्सर कला समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस गांव में मूलतः गद्दी और बारा भंगाली जनजाति के लोग रहते हैं जो दरअसल भेड़ चराने वाली प्रजाति है। पर्यटकों को उनके बीच रहने और उनकी जीवनशैली देखने का मौका मिलता है।
- जोधपुर से 40 मिनट की दूरी पर स्थित बिश्नोई गांव ग्रामीण राजस्थान का वो बेहतरीन अनुभव पर्यटकों को देता है, जो वैसे महसूस कर पाना नामुमकिन है। बिश्नोई समाज इस हद तक प्रकृति प्रेमी है कि हिंदू होने के बावूजद केवल पेड़ों के संरक्षण की दृष्टि से अपने मृतकों को जलाने की जगह दफनाना पसंद करता है। यहां पाश्चात्य जीवनशैली की सुविधाओं से युक्त पारंपरिक निवास हैं जहां पर्यटकों को बुनकर समाज के साथ रहने और उनके जीवन को निकट से देखने का मौका मिलता है। यहां आने वाले पर्यटकों को राजस्थान का विख्यात आतिथ्य और घर में बना हुआ शानदार भोजन मिलता है। लोकनृत्य से उनका स्वागत होता है, बिश्नोई गांव की जीप सफारी, ऊंट सफारी और विलेज ट्रेकिंग के अलावा पर्यटकों के लिए यहां खास अफीम उत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जो यहां के ग्राम्य जीवन का सहज पारंपरिक हिस्सा है।
- पंजाब में लुधियाना के निकट आयोजित होने वाला सालाना किला रायपुर खेल उत्सव पंजाबी लोक परंपराओं और लोक–संस्कृति को समझने–जीने का एक अद्भुत अवसर देता है। 1933 से चल रहे उत्सव में ग्राम्य जीवन में शारीरिक शक्ति का महत्व दर्शाने वाली कई प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं, जैसे दांतों से मोटरसाइकिल उठाना, बालों से ट्रैक्टर खींचना इत्यादि। बैलगाड़ी की दौड़ यहां का एक प्रमुख आकर्षण होता है और भांगड़ा सहित लोकगीतों की महफिल के साथ पंजाबी थाली का स्वाद पर्यटकों को भारतीय संस्कृति के एक समृद्ध स्वरूप का दर्शन कराता जाता है।
- पूर्वोत्तर भारत का जिक्र इस संदर्भ में खासतौर पर किया जा सकता है, जहां हाल ही में सरकारों ने इको टूरिज्म पर विशेष जोर देना शुरू किया है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्य शेष दुनिया के लोगों के लिए कमोबेश अनजाने और अछूते ही रहे हैं। यहां की स्थानीय जनजातियां पर्यटकों के लिए एक बिलकुल ही अनछुए परिवेश, जीवनशैली और संस्कृति का दरवाजा खोलती हैं।

ग्रामीण पर्यटन के ऐसे ही व्यापक महत्व को समझते हुए न केवल भारत की केंद्र और तमाम राज्य सरकारों ने हालिया वर्षों में ग्रामीण पर्यटन पर खास ध्यान देना शुरू किया है, बल्कि इसकी कारोबारी क्षमता ने निजी क्षेत्र को भी इस ओर आकर्षित किया है। वर्ष 2005 में शुरू हुए ग्रासरूट्स ने ग्रामीण भारत में आजीविका के 10 लाख मौके पैदा करने के लक्ष्य के साथ रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम शुरू किया। तब से संस्था ने 3 राज्यों के 12 गांवों में 500 परिवारों के साथ ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम शुरू किए हैं, जहां प्रकृति, खेती, ग्रामीण जीवनशैली, ग्रामीण खेल और कार्यशालाओं के माध्यम से पर्यटकों को एक बेहतरीन अनुभव दिया जाता है और बदले में ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्थिक व कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं।)
ई–मेल : bhaskarbhuwan@gmail.com

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

125 करोड़ भारतवासियों ने लड़ी भ्रष्टाचार और काले धन के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी लड़ाई और... विजयी हुए !

नोटबंदी की व्यापक और ऐतिहासिक सफलता

देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा कालेधन का पर्दाफाश

देश की जनसंख्या के 0.00011% लोगों ने देश में उपलब्ध कुल कैश का 33% जमा किया

17.73 लाख संदिग्ध मामलों का पता चला

23.22 लाख खातों में लगभग 3.68 लाख करोड़ रुपये का संदिग्ध कैश जमा हुआ

6 लाख करोड़ रुपये के हाई वैल्यू नोट प्रभावी रूप से कम हुए

आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूटी

कश्मीर में पत्थरबाज़ी की घटनाएं 75% तक घट गईं

वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 20% से ज़्यादा की कमी आई

7.62 लाख जाली नोट पकड़े गए

साफ़-सुथरी अर्थव्यवस्था की ओर एक मज़बूत और दूरगामी क़दम

कालेधन में डील करने वाली शेल कंपनियों का बड़ा गोरखधंधा हुआ उजागर

शेल कंपनियों पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक, 2.24 लाख कंपनियों पर ताला लगा

नोटबंदी के बाद 35,000 शेल कंपनियों द्वारा करीब 58,000 बैंक खातों में 17,000 करोड़ रुपये जमा किए गए और निकाले गए

संगठित क्षेत्र में गरीबों के लिए बेहतर रोज़गार के अवसर बने

कर्मचारियों के पूरे वेतन का भुगतान सीधे उनके खाते में

1.01 करोड़ नए EPFO पंजीकरण हुए

1.3 करोड़ कर्मचारी ESIC में पंजीकृत- सभी को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं

नोटबंदी से टैक्सपेयर्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि

- टैक्सपेयर्स की संख्या में हुई 26.6% की बढ़ोतरी, 2015-16 में थी 66.53 लाख, 2016-17 में बढ़कर हुई 84.21 लाख
- ई-रिटर्न की संख्या में हुई 27.95% की वृद्धि, 2016-17 में 2.35 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में हुई 3.01 करोड़

लेसकैश के जरिये स्वच्छ अर्थव्यवस्था की तरफ़ भारत की बड़ी छलांग

- अगस्त 2016 में 87 करोड़ डिजिटल लेन-देन हुआ था, जबकि अगस्त 2017 में यह संख्या बढ़कर 138 करोड़ हो गई, अर्थात 58% की वृद्धि
- अब तक 15.11 लाख पीओएस मशीनें चलन में थीं, नोटबंदी के बाद सिर्फ एक साल में 13 लाख से अधिक पीओएस मशीनें इनमें और जुड़ गईं

देशवासियों को नोटबंदी से मिले ढेरों फ़ायदे, जैसे बैंक लोन पर ब्याज दरों में कमी, घर ख़रीदना हुआ सस्ता और आसान, नगरपालिकाओं की आमदनी बढ़ी आदि।

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

नोटबंदी से आपने क्या पाया? जानने के लिए QR कोड स्कैन करें

davp 22201/13/0007/1718

राष्ट्रीय पर्यटन नीति और ग्रामीण पर्यटन

–ऋषभ कृष्ण सक्सेना

2015 में सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति का जो मसौदा पेश किया है, उसमें ग्रामीण पर्यटन पर सीधे जोर तो नहीं दिया गया, लेकिन कई ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिनसे गांवों में पर्यटन को ही रफ्तार मिलेगी। नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि पर्यटन से स्थानीय समुदायों और प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण को फायदा मिलना चाहिए। जाहिर है कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा गांवों में ही मिलेगी और यदि इस पर गंभीरता से काम किया जाता है तो ग्रामीण पर्यटन को ही बल मिलेगा। नीति में एकीकृत पर्यटन सर्किट बनाने की बात भी कही गई है। हालांकि ग्रामीण पर्यटन सर्किटों पर पहले से ही काम किया जा रहा है और कई राज्यों में ये आकार भी ले चुके हैं।

पर्यटन का मतलब एक जमाने में कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों पर जाने, समुद्र तट पर जाने या धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने तक सीमित था। लेकिन बदलते दौर के साथ पर्यटन का फलक भी बहुत बड़ा हो गया है। भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की तादाद रिकॉर्ड तोड़ रही है और लेह–लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों को नापने में भी लोग पीछे नहीं रहते। विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए भी भारत में तमाम तरह के आकर्षण बढ़ गए हैं। धार्मिक पर्यटन तो विदेशियों को हमेशा से पसंद रहा है, लेकिन पिछले 7–8 वर्षों से देश में ग्रामीण पर्यटन की बातें बहुत अधिक हो रही हैं। सरकारों का भी इस पर जोर बढ़ रहा है और सचमुच यह बहुत फायदेमंद भी है।

कुछ अरसा पहले विश्व आर्थिक मंच ने इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 नाम की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उसने भारत में ग्रामीण पर्यटन पर खासा जोर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, जिनकी अपनी अलग संस्कृति और धरोहर है। यदि पर्यटन में उनका खास ध्यान रखा जाए और उनके इर्द–गिर्द पर्यटन का ताना–बाना बुना जाए तो देसी–विदेशी पर्यटकों को अनूठा अनुभव मिलेगा और गांव में रोजगार का बहुत बड़ा स्रोत पैदा हो जाएगा। इसके लिए केंद्र के बजाय राज्य के स्तर पर ही पहल करनी होगी और राज्यों को अपने खास इलाकों में पर्यटन नेटवर्क तैयार करना होगा। ग्रामीण पर्यटन उन राज्यों के लिए खासतौर पर लाभकारी हो सकता है, जहां विदेशी पर्यटकों की आमद कुछ कम है। अगर निजी और सरकारी साझेदारी के आधार पर गांवों में ऐसी परियोजना विकसित की जाए तो तस्वीर ही बदल जाएगी।

उस रिपोर्ट में अनुमान जताया गया था कि भारत में विदेशी पर्यटकों की आमद कुछ ही समय में बढ़कर 2 करोड़ सालाना हो जाएगी, जिससे तकरीबन 2,000 करोड डॉलर की आय होगी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारत में इस मोर्चे पर कुछ हो नहीं रहा है। पिछले कुछ समय में पर्यटन के मामले में भारत काफी आगे बढ़ा है। 2013 की द ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपिटीटिवनेस रिपोर्ट में भारत 65वें पायदान पर था, लेकिन 2017 में वह 40वें पायदान पर पहुंच गया। बेशक स्थिति अब भी बहुत अच्छी नहीं है। हवाई यात्रियों के आंकड़ों में भी यह बात नजर आती है। भारत हवाई यात्रियों के मामले में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सालाना लगभग 10 करोड़ भारतीय हवाई सफर करते हैं, लेकिन यहां साल में बमुश्किल एक करोड़ विदेशी मुसाफिर आते हैं। इसी आंकड़े को बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए पर्यटन के पारंपरिक ठिकानों से इतर नए ठिकाने विकसित करने पड़ेंगे। इसी बिंदु पर सरकारों और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों की नजर गांवों पर टिकनी चाहिए। अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और प्राचीन सांस्कृतिक संपदा से भरे देश के अनछुए कोने पर्यटन उद्योग को नई रफ्तार देने की कुव्वत रखते हैं।

सरकार इस पर काम कर भी रही है। 2015 में सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति का जो मसौदा पेश किया है, उसमें ग्रामीण पर्यटन पर सीधे जोर तो नहीं दिया गया, लेकिन कई ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिनसे गांवों में पर्यटन को ही रफ्तार मिलेगी। नीति

केरल

राष्ट्रीय पर्यटन नीति पर एक नजर

राष्ट्रीय पर्यटन नीति 1982 में कड़ी लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के साथ तैयार की गई थी। नीति ने निजी क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार नहीं किया और धीमी अर्थव्यवस्था में इसके निर्माण के कारण, पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित नहीं किया गया था। इसके अलावा, नीति घरेलू पर्यटन को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती थी। पर्यटन पर जोर देने और पिछली नीति में खामियों को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने 2002 में राष्ट्रीय पर्यटन विकास नीति तैयार की। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे:

- आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन के रूप में पर्यटन को स्थान दिया जाए;
- पर्यावरण की दृष्टि से सतत तरीके से रोजगार और गरीबी उन्मूलन के प्रत्यक्ष और गुणक प्रभावों का उपयोग करना।
- पर्यटन के विकास के प्रमुख चालक के रूप में घरेलू पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करना।
- वैश्विक पर्यटन व्यापार से लाभ उठाने के लिए और गंतव्य के रूप में भारत की अप्रयुक्त क्षमता को बढ़ावा देने के लिए भारत को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करना।
- राज्यों, निजी क्षेत्र और अन्य एजेंसियों के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक–आर्थिक पहलुओं के आधार पर एकीकृत पर्यटन सर्किट बनाना और विकसित करना।
- पर्यटन उद्योग में निजी क्षेत्र और निजी निवेश के महत्व को पहचानने के लिए जिसमें सरकार पर्यटन राजस्व को बढ़ावा देने के एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है।

विश्व भर में पर्यटन क्षेत्र में हाल की घटनाओं और प्रगति को देखते हुए हाल ही में एक नई मसौदा पर्यटन नीति भारत सरकार द्वारा तैयार की गई है, जिसे अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है।

नई मसौदा पर्यटन नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं:

- नीति में पर्यटन विकास में रोजगार सृजन और सामुदायिक भागीदारी पर फोकस।
- टिकाऊ और जिम्मेदार तरीके से पर्यटन के विकास पर जोर।
- विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्यों/संघशासित प्रदेशों और हितधारकों के साथ संबंधों को शामिल करने वाली एक ऑल–कम्पासिंग नीति।
- यह नीति वैश्विक यात्रियों के 'भारत को जरूर अनुभव करें और दोबारा जरूर आएं' गंतव्य के रूप में विकसित करने पर जोर देती है, जबकि भारतीयों को अपने ही देश को जानने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत सहित विभिन्न पर्यटन उत्पादों जैसे मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म; बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों (एमआईसीई) सहित साहसिक पर्यटन और वन्यजीव पर्यटन के विकास और प्रचार को बढ़ावा देती है।
- मूल बुनियादी ढांचे (वायु मार्ग, रेलवे, सड़क मार्ग, जलमार्ग, आदि) और पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास।
- व्यावसायिक कौशल विकास और अवसर निर्माण के लिए वोकेशनल से प्रोफेशनल स्पेक्ट्रम में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन का विकास करना।
- पर्यटन और पर्यटन से संबंधित अवसंरचना में निवेश के लिए सक्षम वातावरण बनाना।
- पर्यटन में प्रौद्योगिकी सक्षम विकास पर जोर।
- पर्यटन के विकास के प्रमुख चालक के रूप में घरेलू पर्यटन पर ध्यान दें।
- स्थापित स्रोत बाजारों और संभावित बाजारों में प्रचार के बारे में ध्यान दें, जो लक्षित और देश के विशिष्ट अभियानों के साथ वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
- बहु–क्षेत्रीय गतिविधियों की पूर्ति के रूप में पर्यटन पर जोर और भारत सरकार की महत्वपूर्ण/प्रमुख योजनाओं के साथ मंत्रालय की गतिविधियों का तालमेल हो।

पर्यटन नीति का मसौदा काफी व्यापक है। इसमें पर्यटन क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया गया है। नीति में इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक के रूप में वैश्विक यात्रियों के लिए 'पुनः–यात्रा जरूरी' गंतव्य को शामिल करके भारत की रिपीट वैल्यू पर भी जोर दिया गया है। लक्षित और देश के विशिष्ट अभियान से भारतीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मसौदा नीति ने राज्य और केंदशासित प्रदेशों की भूमिका को भी मान्यता दी गई है और उम्मीद है कि इससे राज्य/संघशासित प्रदेशों, केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अन्य संबंधित हितधारकों के बीच लिंक स्थापित हो सकेगा। नीति में सहकारी संघवाद का जोरदार समर्थन किया गया है। पर्यटन देश में रोजगार पैदा करने और सृजित करने वाले क्षेत्रों में से एक है। रोजगार सृजन और समुदाय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने से इस विशेष क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की संभावना बढ़ेगी।

स्पष्ट रूप से कहती है कि पर्यटन से स्थानीय समुदायों और प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण को फायदा मिलना चाहिए। जाहिर है कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा गांवों में ही मिलेगी और यदि इस पर गंभीरता से काम किया जाता है तो ग्रामीण पर्यटन को ही बल मिलेगा। नीति में एकीकृत पर्यटक सर्किट बनाने की बात भी कही गई है। हालांकि ग्रामीण पर्यटन सर्किटों पर पहले से ही काम किया जा रहा है और कई राज्यों में ये आकार भी ले चुके हैं। लेकिन इस बार की नीति में प्रमुख शहरों से दूर देश के भीतरी हिस्सों में पर्यटकों को ले जाने की बात कही गई है। इस तरह इस बार की नीति में भी परोक्ष रूप से ग्रामीण पर्यटन को फायदा मिलने जा रहा है।

सरकार नीति बनाने के साथ–साथ उस दिशा में कदम भी उठा रही है। इसमें सबसे पहले स्वदेश दर्शन का नाम आता है, जिसमें किसी विषय या थीम पर आधारित सर्किट तैयार किए जाते हैं। इसमें शुरुआत में पूर्वोत्तर सर्किट, तटवर्ती सर्किट, हिमालय सर्किट और कृष्ण सर्किट पहचाने गए। इनमें ग्रामीण इलाके भी शामिल हैं। इसी तरह तीर्थ स्थलों तक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 'प्रसाद' नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया है। वाराणसी, मथुरा, गया, अजमेर, कांचीपुरम, अमृतसर, पुरी, केदारनाथ समेत कई तीर्थ इसमें शामिल किए गए हैं, जिनके आसपास के गांव भी लाभान्वित हो रहे हैं।

ग्रामीण पर्यटन कितना अहम

इसके बाद भी भारत के बड़े आकार और गांवों की अधिकता को देखते हुए ये प्रयास नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। सरकार को इस पर और भी ध्यान देना होगा क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के

भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या (लाख में)	वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)
2014	76.8	10.2
2015	80.3	4.5
2016	88	9.7
2017 (जन.–जून 2017 संभावित)	48.9	17.2 (इसी अवधि में 2016 में वृद्धि दर)

स्रोतः भारत पर्यटन सांख्यिकी पर एक नजर 2017

भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आमदनी

वर्ष	विदेशी मुद्रा से आमदनी (अमेरिकी डालर में)	वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)
2014	20236	9.7
2015	21071	4.1
2016	22923	8.8
2017 (जन.–जून 2017 संभावित)	13230	22.3* (इसी अवधि में 2016 में वृद्धि दर)

स्रोतः भारत पर्यटन सांख्यिकी पर एक नजर 2017

लिए पर्यटन बहुत जरूरी है। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गांवों में रोजगार के मौके लगातार कम हो रहे हैं और आय का स्तर भी गिर रहा है, जिसकी वजह से शहर की ओर पलायन बढ़ा है। यदि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो युवाओं को तो रोजगार मिलेगा ही, पूरे परिवार के लिए भी रोजगार का वैकल्पिक साधन तैयार हो जाएगा। फसल बिगड़ने की सूरत में ग्रामीण परिवारों को कोई घातक कदम उठाने से बचाने में इसकी अहम भूमिका रहेगी।

ग्रामीण पर्यटन को ठीक से अमलीजामा पहनाया जाए तो गांवों की संस्कृति और धरोहर लंबे समय तक संरक्षित रह सकती हैं। वास्तव में पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र ये दोनों ही होती हैं। जब ग्रामीणों को इस बात का अहसास होगा तो आर्थिक लाभ के लिए भी वे अपनी संस्कृति तथा धरोहरों की हिफाजत करेंगे। ग्रामीण पर्यटन के जरिए सैलानी गांवों की कलाओं तथा शिल्प से परिचित होते हैं, जिसके बारे में उन्हें पहले कभी पता ही नहीं होता है। जाहिर है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से कला एवं शिल्प की कृतियों को भी बेहतर बाजार तथा खरीदार मिलते हैं। साथ ही उनका प्रचार भी होता है।

लेकिन ग्रामीण पर्यटन को वास्तव में बल देने के लिए होम स्टे, शिल्पग्राम और थीम पर्यटन पर अधिक जोर देना पड़ेगा।

होम स्टेः ग्रामीण पर्यटन का सबसे अधिक संभावनाओं वाला पहलू 'होम स्टे' है, जिस पर अभी तक सबसे कम ध्यान दिया गया है। खासतौर पर विदेशी सैलानियों की दिलचस्पी तेजी से बदल रही है और अब वे रिसॉर्ट या होटलों में पसरने के बजाय पर्यटन स्थल की संस्कृति और रीति–रिवाजों का करीब से अनुभव करना पसंद करते हैं। इसके लिए 'होम स्टे' सबसे सटीक तरीका है, जो विदेश में बहुत अधिक लोकप्रिय है। भारत में भी यह प्रचलन में आ रहा है, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर है। यदि ग्रामीण पर्यटन में 'होम स्टे' को शामिल कर दिया जाए तो गांव बहुत तेजी से तरक्की करेंगे, विदेशी सैलानियों की आमद बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा की आवक भी बढ़ जाएगी। साथ ही, ग्रामीण परिवारों को आय का सतत और वैकल्पिक साधन भी मिल जाएगा।

होम स्टे के तहत ग्रामीण घरों के ही एक हिस्से को मेहमानों के लिए तैयार किया जाता है। ये फार्म हाउस भी हो सकते हैं, फलों के बगीचे भी हो सकते हैं और चाय के बागान भी हो सकते हैं। इनमें एक या दो कमरों को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जाता है और सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों, पहाड़ी राज्यों और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में यह लोकप्रिय हैं। लेकिन यदि मंदिरों से अटे पड़े समूचे दक्षिण भारत, वनसंपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे राज्यों, किलों से भरे राजस्थान और मध्य प्रदेश या आदिवासी संस्कृति से समृद्ध झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में आम ग्रामीणों के बीच इसे बढ़ावा दिया जाए तो सैलानी निश्चित रूप से उन्हें ज्यादा पसंद करेंगे।

लेकिन इसे बड़े स्तर पर लागू करने के लिए सरकार को ग्रामीण पर्यटन के लिए अलग से नीति बनाकर होम स्टे पर खास

सैलानियों को असली सामान किफायती दाम पर मिल जाएगा। स्थानीय प्रशासन तथा सरकार की आय अलग होगी।

थीम पर्यटनः थीम यानी किसी एक विषय के इर्द–गिर्द बुना गया पर्यटन ग्रामीण पर्यटन के लिए सबसे माकूल होता है। केरल और दूसरे दक्षिण भारतीय राज्यों में मसालों की खेती होती है, जहां मसाला पर्यटन की अवधारणा गांवों के जरिए साकार की जा सकती है। पर्यटकों को यदि गांवों में होम स्टे के दौरान मसालों की खेती, किस्में, उन्हें तैयार करना सिखाया जाए और साथ ही खेत से तैयार एकदम खालिस मसाले सही कीमत पर मिल भी जाएं तो उस अनुभव को कौन नहीं संजोना चाहेगा। इसी तरह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में चाय पर्यटन को ग्रामीणों के साथ बढ़ावा दिया जा सकता है। तमिलनाडु में मंदिर पर्यटन हो सकता है।

जोर देना होगा। इसके लिए निजी क्षेत्र के पेशेवरों की मदद ली जाए क्योंकि होम स्टे की अभी की नीति में सब कुछ घर के मालिक को ही करना पड़ता है और सरकार उसमें सक्रिय मदद बहुत कम करती है। यदि मौसम के हिसाब से राज्य के अलग–अलग हिस्सों में माकूल होम स्टे की सुविधाओं को सूचीबद्ध किया जाए और केंद्र सरकार की किसी एकीकृत वेबसाइट पर उन्हें डाल दिया जाए तो सैलानियों को भी आसानी होगी और होम स्टे का कारोबार भी तेजी से बढ़ेगा।

शिल्पग्रामः ग्रामीण पर्यटन में सरकार शिल्पग्राम जैसी पहल भी शामिल कर सकती है। भारत जितनी विविधता दुनिया के किसी भी देश में मुश्किल से मिलेगी। यहां खानपान, बोली और संस्कृति ही नहीं शिल्प में भी गजब की विविधता है। उत्तर प्रदेश में आपको सहारनपुर की लकड़ी की कारीगरी, खुर्जा की सिरामिक कारीगरी, बनारस का रेशम का काम मिलेगा तो मध्य प्रदेश में तमाम तरह का शिल्प बिखरा पड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि चार–चार जिलों पर ही स्थानीय–स्तर की ऐसी कारीगरी बदलती है, जिसके बारे में दूसरे प्रांत तो छोड़िए उसी राज्य के दूसरे हिस्सों में बसे लोग तक नहीं जानते। अगर इस शिल्प को सरकार सहारा देती है और शिल्पग्राम बना देती है, जहां हाट तो हो ही, सैलानियों के ठहरने का पूरा इंतजाम भी हो तो विदेशी ही नहीं देसी पर्यटकों के जत्थे भी वहां पहुंचेंगे। यदि होम स्टे और शिल्पग्राम को एक साथ जोड़ दिया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा।

सरकारें और स्थानीय प्रशासन 40–50 गांवों के बीच में एक शिल्पग्राम तैयार कर सकते हैं, जहां तक पहुंचना आसान हो और जहां उस इलाके की कारीगरी और शिल्प का प्रदर्शन किया जा सके। इससे शिल्प और कला का प्रचार–प्रसार होगा, स्थानीय महिलाओं और युवाओं को वैकल्पिक रोजगार मिलेगा और

इसी तरह मध्य प्रदेश में कई छोटे–बड़े किले और घने जंगलों के बीच बने मंदिर हैं। वहां तो कोस–कोस पर इतिहास बिखरा पड़ा है। यदि उसे पर्यटन में शामिल कर लिया जाता है तो विकास में बहुत मदद मिलेगी। झारखंड और छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हैं। सरकार उसी को ग्रामीण पर्यटन की रीढ़ बना सकती है। पंजाब और हरियाणा में यदि फार्महाउसों पर होम स्टे के साथ पर्यटन को बढ़ाया जाए तो रोजगार और आय के नए साधन तैयार हो जाएंगे। गोवा भी आमतौर पर समुद्र तटों पर आराम करने के लिए मशहूर है। लेकिन अगर गोवा के अंदरूनी गांवों में काजू और उसके तमाम व्यंजन तैयार करने तथा मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां वहीं के लोगों के बीच रहकर देखने और सीखने को मिलें तो कौन मौका छोड़ेगा। सरकार यह काम कर तो रही है, लेकिन उसे निजी क्षेत्र के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर करना होगा।

समस्याएं बेशुमार

सरकार की सीमित क्षमता होने के कारण देश में ग्रामीण पर्यटन की समग्र पर्यटन में अभी केवल 0.38 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ग्रामीण इलाकों में होटलों के कमरे भी चीन के मुकाबले केवल 10 प्रतिशत हैं। इसके अलावा, ग्रामीण पर्यटन का बाजार बहुत बिखरा है और उसका प्रचार भी प्रभावी ढंग से नहीं किया जा रहा है। सड़क, परिवहन और बिजली जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं तो नाकाफी हैं ही, सुरक्षा की भी बहुत समस्या है क्योंकि हर वर्ष पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें मिलती ही रहती हैं। इसके अलावा, प्रशिक्षित कर्मचारी इस क्षेत्र को नहीं मिल पा रहे हैं। इतनी समस्याओं के रहते इस क्षेत्र में पूंजी कौन लगाएगा, इसीलिए पूंजी की भी कमी है।

निजी क्षेत्र भी अहम

पर्यटन को आगे बढ़ाना है तो निजी क्षेत्र की मदद लेनी ही पड़ेगी क्योंकि इस मामले में उसे महारत हासिल है। ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र की कई कंपनियां और गैर–सरकारी संगठन कई प्रकार की परियोजनाएं चला रहे हैं। यदि उनके अनुभवों को सरकार अपनी योजना में शामिल करेगी तो ग्रामीण पर्यटन तेज रफ्तार से दौड़ेगा। बुनियादी ढांचा, ठहरने की जगहें, होटल, होम–स्टे के लिए प्रशिक्षण और सुविधाओं का नेटवर्क यदि निजी क्षेत्र तैयार करे तो सरकार को काफी आसानी हो जाएगी। इसके लिए हवाई अड्डों का प्रबंधन, सैलानियों का परिवहन, पार्किंग आदि का काम निजी क्षेत्र को दे देना चाहिए, जो क्षेत्रीय हवाई अड्डों के मामले में किया भी जा रहा है।

सरकार को ग्रामीण पर्यटन वाले इलाकों में सैलानियों के लिए सभी सुविधाएं मसलन ठहरने की जगह, घूमने के लिए वाहन, शिल्पहाट का प्रबंधन आदि प्रदान करने का काम निजी क्षेत्र को दे देना चाहिए। इसी तरह स्मारकों, संग्रहालयों और जन–सुविधाओं के रखरखाव का काम भी उसी के हवाले किया जा सकता है। ग्रामीण पर्यटन के लिए प्रशिक्षण का काम तो पूरी तरह इसी क्षेत्र को सौंपा जाए और मार्केटिंग का जिम्मा भी उसी का हो। यदि ऐसा होता है तो पर्यटन को और भी प्रभावी ढंग से बढ़ाया जा सकता है।

सरकार की बढ़े सक्रियता

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है तो सरकार को अपनी भूमिका बढ़ानी पड़ेगी और केंद्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर मुस्तैदी दिखानी होगी। राज्यों को खासतौर पर तालमेल बिठाने और सुविधाएं देने वाले विभागों के बीच संपर्क मजबूत करने का काम करना होगा।

बुनियादी ढांचा ग्रामीण पर्यटन की रीढ़ है। वर्तमान सरकार के समय में सड़क, बिजली और दूरसंचार के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। फिर भी सड़कों का नेटवर्क अभी कम है और ग्रामीण इलाकों में बिजली भी ठीक से नहीं आती। यदि ऐसी स्थिति रहती है तो देसी–विदेशी पर्यटकों को लुभाने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले सरकार को बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा और इसीलिए सरकार को गांवों तक बेहतर सड़कों, सस्ते होटल आदि का इंतजाम करना पड़ेगा ताकि विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण पर्यटन में हिचक नहीं हो। इसमें भी स्थानीय भौगोलिक विशेषताओं और जरूरतों के हिसाब से सुविधाएं देनी होंगी। मसलन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सहूलियतें और वाटरस्पोर्ट्स जैसी सहूलियतें गंगा के मैदानी इलाकों में दी जा सकती हैं, वैसी पानी की किल्लत से जूझते बुंदेलखंड में नहीं दी जा सकती।

साथ ही सरकार को क्षेत्र का विकास करने की योजना में पर्यटन को अटूट हिस्सा बनाना पड़ेगा। अभी पर्यटन में निवेश आकर्षित करने की दिशा में सरकारें कोई खास कदम नहीं उठा रही हैं। यदि बुनियादी ढांचा और सुविधाएं तैयार करने के बाद इस क्षेत्र में निवेश करने पर प्रोत्साहन या रियायतें दी जाएंगी तो निवेशकों के आने में कोई संदेह नहीं रहेगा। इसके लिए कर की दरें तार्किक बनानी होंगी, भूमि से संबंधित नीतियों में जरूरत पड़ने पर ढिलाई देनी होगी और जरूरत पड़ने पर रेलवे की बेकार पड़ी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत भी देनी होगी।

इसके बाद सुरक्षा की बारी आती है। हाल के दिनों में विशेषकर कस्बायी माहौल वाले पर्यटन स्थलों पर विदेशी पर्यटकों के साथ हिंसा की खबरें आई हैं। ग्रामीण इलाकों में कानून–व्यवस्था बनाए रखना तथा इस प्रकार की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करना आज भी दिवास्वप्न लगता है। यदि भारत को सुरक्षित देश के तौर पर सामने लाना है और ग्रामीण पर्यटन को गति देनी है तो देहात में भी कानून–व्यवस्था और सुरक्षा पर खास ध्यान देना पड़ेगा। यदि स्थानीय समुदाय को इसमें गहराई तक जोड़ा जाता है तो कानून–व्यवस्था और सुरक्षा तो अच्छी रहेगी ही, क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। इसके लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर स्थानीय ग्रामीणों को आतिथ्य–सत्कार और पर्यटन का प्रशिक्षण देना होगा ताकि वे स्थानीय सुविधाओं, तौर–तरीकों के बारे में जान सकें और सैलानियों के लिए गाइड का काम भी कर सकें।

अंत में सरकार को अतुल्य भारत अभियान को समग्र अभियान बनाना होगा। इसमें प्रिंट मीडिया ही नहीं डिजिटल, सोशल मीडिया, रिव्यू करने वाली वेबसाइट और ग्लोबल मीडिया भी शामिल हो। साथ ही ऐसी सरकारी वेबसाइट भी बनाई जाएं, जिसमें पर्यटक अपने अनुभव साझा कर सकें और उनके सामने आई कठिनाइयों पर फौरन ध्यान दिया जाए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। वर्तमान में आर्थिक दैनिक बिजनैस स्टैंडर्ड से जुड़े हैं।)

ई–मेल : rishabhakrishna@gmail.com

प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन

प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन ने पर्यटन मंत्रालय और उद्योग हेतु वर्ष 2022 तक 50 लाख व्यक्तियों का कुशल कार्यबल तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अतः पर्यटन और आतिथ्य उद्योग की जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु होटलों के लिए कौशल विकास पहल में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। होटल के वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के लिए संशोधित दिशा–निर्देशों में प्रत्येक वर्गीकृत होटल को 'हुनर से रोजगार योजना' के अंतर्गत अल्पावधि के कौशल विकास पाठ्यक्रम में प्रत्येक कलैंडर वर्ष में एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है।

ग्रामीण पर्यटन : बुनियादी संरचना और क्षमता निर्माण

–डॉ. सुयश यादव

ग्रामीण पर्यटन इस लिहाज से अनोखा है कि यह समुदाय के स्वामित्व और भागीदारी पर निर्भर रहता है। ग्रामीण पर्यटन स्थल पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ग्रामीण समुदाय को तैयार करना पड़ता है और उनके बीच गांव में जो कुछ बनाया जाना है, उसके प्रारूप के बारे में आम सहमति बनानी होती है। यह कार्य सरकार अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती। इसलिए गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को क्रियान्वयन में सहभागी बनाया जाता है। ऐसे में उस एनजीओ का महत्व बहुत बढ़ जाता है जो उस गांव पर असर डालने वाले कारकों को भली–भांति समझता है।

वृहद् आर्थिक–स्तर पर विकास मानव विकास की गारंटी नहीं है। विकासशील देशों में बढ़ते ग्रामीण संकट की पृष्ठभूमि में आबादी के एक ऐसे बड़े हिस्से को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना जिन्हें लगातार रोजी–रोटी तथा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जाता रहा है, बहुत बड़ी चुनौती है। ग्रामीण पर्यटन समाज में समता और सशक्तीकरण जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने का कोई करामाती नुस्खा नहीं हो सकता। लेकिन अगर जनता को केंद्र में रखकर पर्यटन की बात करें तो यह बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा के इर्द–गिर्द एक मजबूत मंच का विकास भारत जैसे देश के लिए निश्चित रूप से उपयोगी है जहां करीब–करीब 68 प्रतिशत जनसंख्या करीब साढ़े छह लाख गांवों में रहती है।

कृषि के क्षेत्र में आमदनी के घटते स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण की बीमारी के लक्षण दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही शहरी जीवनशैली के दबावों से 'प्रति–शहरीकरण' के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन उन गिनी–चुनी गतिविधियों में शामिल है जिनसे इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन अकेले पर्यटन के बूते पूरे साल शत–प्रतिशत रोजगार की उम्मीद नहीं की जा सकती, मगर यह एक वैकल्पिक अवसर प्रदान करता है, और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और पशुपालन आदि से हटकर कुछ करने के मौके मिलते हैं।

ग्रामीण पर्यटन के विकास की योजना के अंतर्गत मुख्य जोर इसे मुख्य पर्यटन गतिविधि के रूप में विकसित करने का है ताकि पर्यटन और इसके सामाजिक–आर्थिक फायदों को गांवों तक पहुंचाया जा सके और इस तरह देहाती इलाकों से लोगों का शहरों को पलायन रुके। ग्रामीण मनोरंजन मंडलियों के माध्यम से स्थानीय इतिहास, संस्कृति, मौखिक विधाओं के खजाने का पता लगाया जा सकता है। इस तरह पर्यटकों को भारत की ग्रामीण परंपराओं का 'आनंद' लेने का मौका उपलब्ध कराया जा सकता है। आज पर्यटन अनुभव हासिल करने का पर्याय बन गया है। लोग किसी स्थान पर जाकर वहां के स्मारकों को देखकर वापस नहीं लौट जाते, बल्कि वे वहां तरह–तरह के अनुभव हासिल करना चाहते हैं। वे लोगों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं और वहां के समाज के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारियों से समृद्ध होकर लौटना चाहते हैं।

भारत में ग्रामीण पर्यटन

पर्यटन का कोई भी रूप जिससे ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और धरोहर की झलक देखने को मिले और जिससे स्थानीय समुदाय

लाचुंग, सिक्किम

को आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से फायदा होने के साथ–साथ पर्यटक स्थानीय लोगों के संपर्क में आएं और एक सुखद अनुभव से समृद्ध होकर लौटें, 'ग्रामीण पर्यटन' कहा जा सकता है। भारत की राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 में ग्रामीण पर्यटन की पहचान विशेष रूप से ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में की गई है। एंडोजीनस टूरिज्म प्रोजेक्टस–रूरल टूरिज्म स्कीम (ईटीपी–आरटीएस) भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का साझा प्रयास है जिसकी शुरुआत 2003 में हुई।

यूएनडीपी प्रत्येक स्थल को 'साफ्टवेयर' यानी स्थानीय लोगों और बाहरी एजेंसियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 20 लाख रुपये का अनुदान देता है जबकि पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक स्थल पर 'हार्डवेयर' के विकास के लिए 50 लाख रुपये का अंशदान केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में देता है। इसके अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास की गतिविधियां जैसे सड़कों का विकास, साफ–सफाई, गांव के परिवेश में सुधार जैसे कार्य किए जाते हैं। ग्रामीण लोगों को खान–पान, साफ–सफाई और आरोग्य के बारे में जानकारी देने के लिए होटल प्रबंधन संस्थानों के साथ करार किए जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद (आईआरएमए) और विरासत वास्तुशास्त्रियों को सलाहकार के तौर पर जोड़ा जाता है। स्थानीय वास्तुशिल्प को परिवेश में ज्यादा फेरबदल किए बिना बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं।

परंपरागत पर्यटन के विपरीत, ग्रामीण पर्यटन में कुछ खास विशेषताएं होती हैं, जैसे यह अनुभवमूलक होता है। इस तरह के पर्यटन वाले स्थानों की आबादी कम होती है, यह आमतौर पर प्राकृतिक परिवेश में होता है, इसमें स्थानीय कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है और यह संस्कृति, धरोहर और परंपराओं के संरक्षण पर आधारित होता है। इसका कार्यान्वयन पर्यटन समिति द्वारा किया जाता है जिसका प्रमुख संबंधित ग्रामीण पर्यटन स्थल के जिले का कलेक्टर होता है। 31 मार्च, 2012 तक पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए 185 पर्यटन स्थलों की पहचान कर ली थी। मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ताजा आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में 52 ग्रामीण पर्यटन स्थल सैलानियों के लिए कार्य करने लगे हैं। इनमें से प्रत्येक स्थल की अपनी कोई–न–कोई खूबी है।

2014 में पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन' नाम के केंद्र सरकार के कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका उद्देश्य किसी एक विषय पर आधारित पर्यटक सर्किटों का समन्वित विकास करना था। पर्यटक सर्किट उस मार्ग को कहा जाता है जिसमें पर्यटकों के लिहाज से महत्वपूर्ण कम से कम तीन ऐसे प्रमुख स्थान होते हों जो अलग–अलग गांवों, कस्बों या शहरों में स्थित हों। धर्म, संस्कृति या जातीय पहचान से संबंधित किसी खास विषय पर आधारित पर्यटक सर्किट को थीम यानी विषय–आधारित 'पर्यटक सर्किट' कहा जाता है। ग्रामीण सर्किट उन 13 विषय–आधारित सर्किटों में से एक है जिन्हें विकसित करने के लिए चुना गया है।

सामुदायिक क्षमता का निर्माण

ग्रामीण पर्यटन इस लिहाज से अनोखा है कि यह समुदाय के स्वामित्व और भागीदारी पर निर्भर रहता है। ग्रामीण पर्यटन स्थल पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ग्रामीण समुदाय को तैयार करना पड़ता है और उनके बीच गांव में जो कुछ बनाया जाना है उसके खाके के बारे में आम सहमति बनानी होती है। यह कार्य सरकार अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती। इसलिए गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओज) को क्रियान्वयन में सहभागी बनाया जाता है। ऐसे में उस एनजीओ का महत्व बहुत बढ़ जाता है जो उस गांव पर असर डालने वाले कारकों को भली–भांति समझता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीनी–स्तर पर काम करने वाले एनजीओ की मदद से समुदाय के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाया जाता है। पर्यटन मंत्रालय अपने आप ये सब काम नहीं कर सकता। इस पर अमल का केंद्र बिंदु जिला कलेक्टर होता है जिसे ग्राम पर्यटन समिति से सहायता प्राप्त होती है। इसके लिए जिले के अधिकारियों और संबद्ध एनजीओ के बीच प्रभावी संवाद कायम होना जरूरी है। इस तरह की परियोजनाओं में साफ्टवेयर से संबंधित घटक पर अमल में अधिक समय लगता है (क्षमता निर्माण में 18 से 24 महीने तक लग जाते हैं)। साफ्टवेयर के तहत पहले ग्रामीण समुदाय के लोग आपस में चर्चा करके इस बात पर आम राय बनाते हैं कि पर्यटन घटक के तहत क्या करना चाहते हैं। और इससे ही बाद में हार्डवेयर घटक उभर कर सामने आना चाहिए। इसलिए राज्य के पर्यटन विभाग का एकमात्र काम हार्डवेयर घटक तक सीमित नहीं होना चाहिए।

इन परियोजनाओं के लिए दो चरणों वाली विधि में ग्रामीण समुदाय को एकजुट करना और उनकी क्षमताओं के निर्माण का कार्य शामिल रहता है। सबसे बड़ी चुनौती पर्यटन उत्पादों के सृजन की होती है उन्हें बाहर से लाकर नहीं रखा जा सकता, उन्हें गांव के भीतर ही से पैदा होना जरूरी है। परियोजना का एक उद्देश्य गरीबी कम करना है। ग्रामीण पर्यटन का अर्थ गांवों में पहले से समृद्ध लोगों को और धनी बनाना नहीं है बल्कि इसका मतलब है ऐसे लोगों को रोजी–रोटी उपलब्ध कराना जो खुशहाल नहीं हैं। ऐसे लोग पर्यटन में सहभागी बन सकते हैं और उनकी भागीदारी पर्यटकों की जरूरतों से संबंधित किसी भी सेवा या हुनर में हो सकती है। ग्रामीण पर्यटन योजनाओं के पीछे अंतर्निहित सोच यह है कि पर्यटन से हुई आमदनी को समूचे ग्रामीण समुदाय के सामान्य कल्याण में लगाया जाए ताकि जो लोग पर्यटन व्यवसाय से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी इसका फायदा मिले। जब हम समुदाय–आधारित पर्यटन की बात करते हैं तो गांवों में लोगों की उपस्थिति मात्र से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।

ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचा

इंडोजीनस टूरिज्म प्रोजेक्ट– रूरल टूरिज्म स्कीम (ईटीपी–

आरटीएस) यानी अंतः विकसित पर्यटन परियोजना और ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय द्वारा अतीत में लागू किए गए बुनियादी ढांचा केंद्रित मानक पर्यटन परियोजनाओं से हटकर हैं। परियोजना का उद्देश्य और इसकी चुनौती ऐसा माहौल तैयार करने की है जिसमें पर्यटकों को ग्रामीण पृष्ठभूमि का आनंद उठाने का मौका मिले। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवेश में शहरी सुख–सुविधाएं जुटाना नहीं है। ईटीपी–आरटीएस कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात में कच्छ के रन का होडका गांव एक उदाहरण है जिसमें बुनियादी ढांचे का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया। शान–ए–सरहद विलेज रिसोर्ट नाम से मशहूर इस पर्यटन केंद्र का स्वामित्व और संचालन होडका की ग्राम पर्यटन समिति के पास है।

कार्यक्रम के तहत पैनलबद्ध किए गए वास्तुशास्त्री इस बात का ध्यान रखते हैं कि बुनियादी ढांचे का निर्माण करते समय स्थानीय वास्तुशिल्प और परम्पराओं का पालन किया जाए। वास्तुशिल्प की शैली सामग्री की उपलब्धता की स्थिति पर निर्भर रहती है। निर्माण और रखरखाव का कार्य करते समय भी स्थानीय समुदाय की अधिक से अधिक भागीदारी पर जोर दिया जाता है। भुज के भूकंप में चौकोर इमारतों को नुकसान पहुंचा था जो टूट–फूट गई थीं, मगर गोलाकार भुंगा झोपड़ियां, जिनके लिए होडका प्रसिद्ध है, ज्यों की त्यों बच गई थीं। गांव के लोगों को अपने इतिहास, इमारतों के निर्माण की जानकारी और इसके तौर–तरीकों पर बड़ा गर्व है। इसी ने भूकंप की आशंका वाले इस इलाके में उन्हें सुरक्षित रखा है। इसीलिए लागत में कमी लाने के लिए वास्तुशास्त्रियों ने बुनियादी ढांचे के निर्माण में मिट्टी का इस्तेमाल करने की अवधारणा को अपनाया। इससे कच्छ के वास्तुशिल्प की सामाजिक और सौंदर्यशास्त्र विशेषताओं के संरक्षण में मदद मिली और कंक्रीट के ढांचों का निर्माण नहीं किया गया। कंक्रीट की जगह मिट्टी का इस्तेमाल करने का फायदा यह हुआ कि मिट्टी एक ऐसी निर्माण सामग्री है जो गर्मी और ठंड दोनों से बचाव करती है। ऐसे कारीगरों की मदद ली गई जो निर्माण कार्य में मिट्टी के इस्तेमाल में दक्ष थे। इसी तरह स्थानीय समुदायों में उपलब्ध दस्तकारों का भी अधिक से अधिक इस्तेमाल किया गया ताकि स्थानीय स्वामित्व की झलक मिले और साथ ही स्थानीय लोगों का पैसा उन्हीं के समुदाय में रहे। इससे कारीगरों और दस्तकारों में भी गर्व की भावना पैदा होती है जिन्हें रोजी–रोटी की तलाश में अपना घर छोड़ कर शहरों को जाने को मजबूर होना पड़ता है।

भारत में पर्यटकों और प्रमुख संगठनों (सेवा प्रदाताओं) के लिए सप्लाई चेन

पर्यटन निजी क्षेत्र के वृहत्तर नेटवर्क से जुड़ा है। यात्रा कारोबार की जरूरत है ग्रामीण पर्यटन स्थल पर स्वच्छता और आरोग्य तथा पर्यटकों की सुरक्षा। सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहे एनजीओ देश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं और पर्यटकों की सप्लाई चेन का बेहद जरूरी हिस्सा हैं। इस तरह की पहल में ग्रासरूट्स, रूरल टूरिज्म नेटवर्क एंटरप्राइज, धन फाउंडेशन और ट्रैवल अनदर इंडिया प्रमुख हैं।

सरकारी योजनाएं

प्रत्येक पर्यटन–स्थल को 50 लाख रुपये की सहायता के अलावा पर्यटन मंत्रालय इंडोजीनस टूरिज्म प्रोजेक्ट–रूरल टूरिज्म स्कीम (ईटीपी–आरटीएस) यानी अंतः विकसित पर्यटन परियोजना और ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम में मदद के लिए विदेशों में (जहां से पर्यटक आते हैं) विपणन संबंधी विभिन्न पहल कर रहा है। भारत में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर में इंडिया/60 कार्यक्रम में पहली बार पर्यटन मंत्रालय द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से विकसित चार ग्रामीण पर्यटन स्थलों के आठ हुनरमंद दस्तकारों ने आकर्षक कला और शिल्प के जरिए अपने यहां की खूबियों को प्रदर्शित किया। इसमें भाग लेने वाले दस्तकारों में से ज्यादातर पहली बार विदेश यात्रा पर गए थे और उन्हें वहां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, विपणन और प्रचार–प्रसार के तौर–तरीकों का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। इससे वे पर्यटन कारोबार, ग्राहकों, कॉरपोरेट संगठनों और मीडिया के साथ विस्तृत प्रत्यक्ष संपर्क बना। सितंबर 2008 में आयोजित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन (पाटा) की ट्रेवल मार्ट में ग्रामीण पर्यटन स्थलों के दस्तकारों ने हिस्सा लिया और अपनी कला व शिल्प का प्रदर्शन किया।

सुगम्यता और सुधार

देशभर में कई स्थानों पर ग्रामीण पर्यटन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। लेकिन इनमें से कुछ ही सफल हुई हैं और इनसे वहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ोतरी के साथ–साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए कराए गए अध्ययन में बताया गया है कि परियोजना क्षेत्रों में कम संख्या में पर्यटकों का पहुंचना और वहां तक पहुंचने में परेशानियां मूल्यांकित परियोजनाओं में से करीब 31 प्रतिशत की असफलता की वजह हैं। इसलिए किसी गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सबसे पहला कदम गांव की असली ताकत को पहचानना होना चाहिए और इसी के चारों ओर ग्रामीण पर्यटन का ताना–बाना बुना जाना चाहिए। ग्रामीण पर्यटन के विकास को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख तत्वों में उस स्थान की अवस्थिति और प्रमुख पर्यटन स्थलों से उसकी दूरी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ग्रामीण पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मजबूत सार्वजनिक–निजी भागीदारी का बड़ा महत्व है। इस संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों जैसे ग्रामीण विकास, संस्कृति, पर्यावरण और जनजातीय कल्याण के कई कार्यक्रमों को समन्वित कर समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नाबार्ड के तहत ग्राम पंचायतों और ग्रामीण नवसृजन कोष की भागीदारी सुनिश्चित करके उनकी ताकत का भी फायदा उठाया जाना चाहिए।

विकासशील देशों में ग्रामीण पर्यटन स्थलों की मार्केटिंग के

कार्य का जटिल हिस्सा यह है कि ग्रामीण पर्यटन पर्यटकों के आगमन पर प्रसन्न या कृतज्ञ होने तक सीमित नहीं हैं। बल्कि यह उस स्थल पर क्या अनुभव हो सकते थे, इसे सम्प्रेषित करने में है ताकि जो पर्यटक ऐसे अनुभवों की तलाश में हैं, उन्हें आकर्षित किया जा सके। इस तरह स्थिति निर्धारण और प्रोत्साहन जन–केंद्रित होना चाहिए न कि बाजार केंद्रित। आज दुनिया भर में कई जिम्मेदार पर्यटन उपक्रम फल–फूल रहे हैं। वे स्थानीय लोगों के साथ सक्रिय रूप से भागीदार बनने और स्थानीय विकास प्रक्रिया में योगदान करने को अपने पर्यटन अनुभव का स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। ग्रामीण पर्यटन की परिकल्पना करने, इस पर अमल करने और इसे बढ़ावा देने का कार्य इस तरह से किया जाना चाहिए कि इससे पर्यटक को किसी स्थान या दृश्य को देखने भर की प्रेरणा न मिले, बल्कि उसमें अनुभव हासिल करने की उत्सुकता जगे और उस पर असर पड़े। इतना ही नहीं, वह ग्रामीण समुदाय के साथ संपर्क से अपने आप को थोड़ा बदला हुआ–सा महसूस करें। ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं को इस तरह से बनाए जाने की जरूरत है जिससे इस समूची प्रक्रिया में ग्रामीण समाज शुरू से ही भागीदार बने और वे परियोजना के शुरू होने से काफी पहले से ही इसके फायदों और नुकसान के बारे में अच्छी तरह से अवगत हो।

निष्कर्ष

भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता को देखते हुए देश में ग्रामीण पर्यटन की क्षमताओं का फायदा उठाने के अनगिनत मौके हैं। अगर उचित तरीके से इसे लागू किया जाए और बढ़ावा दिया जाए तो परियोजनाएं आर्थिक विकास की प्रेरक बन सकती हैं और इनसे गरीबी, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण लोगों के आर्थिक दर्जे को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। जिन गांवों का चयन सही तरीके से हुआ है और जहां एनजीओ और जिला कलेक्टर के बीच गतिशील तालमेल कायम रहा है वहां सफलता की गाथाएं सुनने को मिली हैं। ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं की सफलता का आकलन सिर्फ आर्थिक फायदे के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए बल्कि गांवों में सामाजिक न्याय के स्तर में सुधार और सामाजिक पूंजी में वृद्धि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

(लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय के पर्यटन अध्ययन संस्थान में सहायक प्रोफेसर हैं।)

ई–मेल : yadav.suyash@gmail.com

ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त धनराशि जारी

वर्ष 2017–18 में सरकार ने मनरेगा के लिए बजट अनुमान के आधार पर अब तक का अधिकतम आवंटन 48000 करोड़ रुपये जारी किया है। इस वर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय को सभी योजनाओं के लिए कुल राशि 1,05,442 करोड़ रुपये प्राप्त हुई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय 85 प्रतिशत मामलों में 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान कर रहा है, जबकि 2015–16 और 2016–17 में यह क्रमशः 37 प्रतिशत और 42 प्रतिशत था। बजट अनुमान के आधार पर बढ़े हुए आवटन के कारण ऐसा संभव हुआ है।

राज्यों को दी जाने वाली धनराशि का दूसरा दौर प्रत्येक वर्ष सितंबर में प्रारंभ होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्यों ने सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित शर्तों का पालन किया है अथवा नहीं। इसके अंतर्गत पिछले वर्ष के लेखा रिपोर्ट सहित पूर्ण वित्तीय जांच शामिल है। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने राज्यों को इससे संबंधित अनुरोध किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा भुगतान और सामग्री भुगतान के लिए धनराशि की दूसरी किश्त जारी कर दी है। यह राशि उन राज्यों को जारी की गई है जिन्होंने वर्ष 2016–17 के लिए लेखा रिपोर्ट जमा कर दिया है। पिछले 10 दिनों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम और तमिलनाडु को धन जारी किया गया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को धनराशि देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है क्योंकि उनके प्रपत्र हाल में ही प्राप्त हुए हैं। मजदूरी भुगतान व अन्य गतिविधियों के लिए राज्यों को उनके लेखा रिपोर्ट प्राप्त होते ही धनराशि जारी कर दी जाएगी। अच्छे मानसून वाले वर्ष में मनरेगा के तहत अगस्त से नवंबर तक रोजगार की मांग में कमी आती है। जिन राज्यों और जिलों में मानसून की औसत से कम वर्षा हुई है उनके लिए धनराशि के आवंटन का विशेष ध्यान रखा गया है। सरकार समय पर भुगतान के लिए प्रतिबद्ध है और यदि आवश्यकता हुई तो मनरेगा के लिए पूरक बजट में अतिरिक्त धनराशि मुहैया करायी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि ग्राणीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार ने डीएवाई–एनआरएलएम, पीएमजीएसवाई, पीएमएवाई(जी) व अन्य कार्यक्रमों के लिए आवंटन राशियों में बढ़ोतरी की है। दिसंबर, 2018 तक पीएमएवाई(जी) के अंतर्गत एक करोड़ नए घरों को निर्माण किया जाएगा, जो एक रिकार्ड होगा। मार्च, 2018 तक 51 लाख ऐसे घरों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। 8 लाख घरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और शेष 43 लाख घरों का निर्माण अंतिम चरण में है। पीएमजीएसवाई अब एक वर्ष में 29 हजार करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करता है। इसमें राज्यों का हिस्सा भी शामिल है। 85 प्रतिशत निवास क्षेत्रों (मैदानी क्षेत्रों में 500 और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 की आबादी) को सभी मौसमी सड़कों से जोड़ दिया गया है। 6 महीने पहले यह मात्र 57 प्रतिशत था। मार्च, 2019 तक शत–प्रतिशत कनेक्टिविटी का लक्ष्य रक्षा गया है और यह लगभग पूरे होने की राह पर है। डीएवाई–एनआरएलएम के तहत जीविका के साधनों को विविधिकरण करने का लक्ष्य है। स्वयं सेवी समूहों को बैंकों के खातों से जोड़ा गया है और इसमें 47 हजार करोड़ रुपये की राशि जमा है। ढाई वर्ष पूर्व जमा राशि की तुलना में यह दुगुनी से अधिक है। ग्रामीण विकास की अन्य गतिविधियों से भी ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के अवसरों का सृजन हो रहा है। इस कारण ग्रामीण भारत में मजदूरी की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्वच्छ भारत मिशन, 14वें वित्त आयोग और कई अन्य गतिविधियां भी ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी आधारित रोजगार की वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं।

ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के प्रयास

–हेना नक़वी

भारत विविधताओं का देश है। मौसम, रंग–रूप, पहनावे, संस्कृति और धर्मों की इतनी विविधता विश्व में विरले ही देखने को मिलती है। इसीलिए भारत को 'पर्यटकों का स्वर्ग' कहा जाता है। पर्यटन हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वूपर्ण हिस्सा और राजस्व–अर्जन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस क्षेत्र की असीम क्षमता के कारण बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसे प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। हाल के वर्षों में देश में ग्रामीण पर्यटन की ओर भी यथोचित ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण पर्यटन को ग्रामीण विकास की रणनीति के रूप में अपनाया गया है। भारत सरकार के कुछ नए कदम ग्रामीण पर्यटन को वैश्विक फलक पर स्थापित करने का दमखम रखते हैं। प्रस्तुत आलेख में ऐसे ही कुछ नए कदमों को रेखांकित किया गया है।

वर्ष 2017 को 'विकास के लिए सतत् पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' के रूप में मनाया गया। यानी अब पर्यटन को एक ऐसे टिकाऊ उद्यम के रूप में देखा जा रहा है जिसके साथ विकास भी होता रहे। भारत के लिए विकास की अवधारणा गांवों के विकास से जुड़ी है। गांव अगर विकसित होंगे तो देश अपने आप विकसित होगा। भारत सरकार अब ग्रामीण पर्यटन को विकास के एक माध्यम के रूप में देखती है। गांवों में देशी–विदेशी पर्यटकों के आगमन से न सिर्फ स्थानीय गृह उद्योग, हस्तकला और हस्तशिल्प का विकास होगा, बल्कि रोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे और गांव सबल और आत्मनिर्भर आर्थिक इकाईयों के रूप में विकसित होंगे।

भारत जैसे परंपरावादी देश की महान परंपराओं में से एक है, 'अतिथि देवो भव'। यह केवल एक सूक्ति नहीं है बल्कि देश की सुसंस्कृति का परिचायक है जिसके तहत आज भी घर आए अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है। यह आदर्श आज हमारे प्रगतिशील पर्यटन उद्योग का मूल सिद्धांत भी है जो देश–विदेश के पर्यटकों को उत्कृष्ट सेवाएं देने का लक्ष्य रखता है। पर्यटन उद्योग की गणना किसी भी अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में की जाती है क्योंकि राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत होने के अतिरिक्त यह उद्योग किसी भी देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं उनके व्यापक प्रचार–प्रसार का माध्यम भी है। यही नहीं, यह क्षेत्र लोगों को लोगों से जोड़ता भी है।

चूंकि भारत गांवों का देश है, इसलिए भारत की सांस्कृतिक धरोहरों का अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से ही जुड़ा है। इस नाते भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण पर्यटन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसाकि नाम से ही झलकता है, ग्रामीण पर्यटन उद्योग उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसके माध्यम से पर्यटकों को ग्रामीण जीवन–शैली, कला–संस्कृति, अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अंचलों की धरोहर आदि से रुबरु होने का अवसर मिलता है। इन अवसरों को प्रदान करने अथवा उन तक पहुंचने में सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को इस सेवा के बदले आय की प्राप्ति होती है।

भारत की आत्मा गांवों में बसती है। पश्चिमी देशों में गांव तो हैं, लेकिन आधुनिकता के प्रवेश से वहां प्राचीन परंपराओं और सभ्यताओं यहां तक कि कुटुम्ब व्यवस्था का भी लोप हो चुका

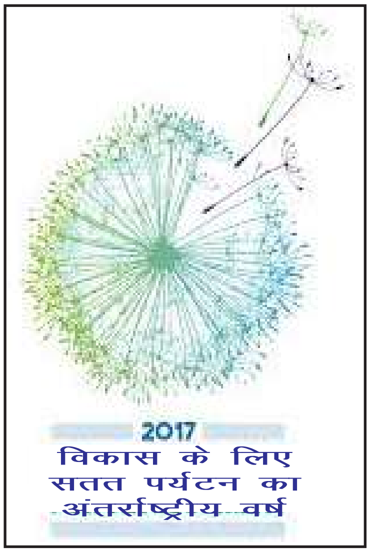

है। इसके विपरीत हमारे देश में गांव की सोंधी मिट्टी, खेत–खलिहान, कच्चे घर उन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो शहरों की चकाचौंध और आपाधापी से दूर सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं।

सरकार द्वारा ग्रामीण पर्यटन को प्राथमिकता में शामिल करने के कारण जहां एक ओर रोजगार को बढ़ावा मिला है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण धरोहरों के संरक्षण पर भी यथोचित ध्यान जा रहा है। देश की विविधता के दृष्टिगत ग्रामीण पर्यटन के सुदृढ़ीकरण के लिए हाल के वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदम प्रशंसनीय हैं। भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में पर्यटन मंत्रालय निरंतर इस क्षेत्र के विकास हेतु प्रयत्नशील है। मंत्रालय द्वारा विषय–मूलक 'टूरिस्ट सर्किट' के विकास की कवायद शुरु की गई है। इसके तहत मुख्यतः चार प्रकार के टूरिस्ट सर्किट–तीर्थस्थल एवं आध्यात्मिकता, धरोहर, संस्कृति एवं पारिस्थितिकी पर्यटन (इको टूरिज़्म) निर्धारित किए गए हैं। इसी क़वायद का अंग है, 'प्रसाद' (पिलग्रिमेज रिज्युवेनेशन एंड स्प्रिच्युएलिटी ड्राइव) नामक योजना। इस योजना के अंतर्गत देश के 25 स्थलों–अमरावती (आंध्र प्रदेश), अमृतसर (पंजाब), अजमेर (राजस्थान), अयोध्या (उत्तर प्रदेश), बद्रीनाथ (उत्तराखंड), बेलूर (प. बंगाल), द्वारका (गुजरात), देवघर (झारखंड), गया (बिहार), गुरुयावूर (केरल), हज़रतबल (जम्मू एवं कश्मीर), कामख्या (असम), कांचीपुरम् (तमिलनाडु), कटरा (जम्मू एवं कश्मीर), केदारनाथ (उत्तराखण्ड), मथुरा (उत्तर प्रदेश), ओमकारेश्वर (मध्यप्रदेश), पटना (बिहार), पुरी (ओडीशा), सोमनाथ (गुजरात), श्रीसायलम (आंध्र प्रदेश), तिरुपति (आंध्र प्रदेश), त्रिम्बकेश्वर (महाराष्ट्र), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) एवं वेलंकनी (तमिलनाडु) का चयन किया गया है। योजना के द्वारा इन चयनित महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों के सौंदर्यीकरण एवं विकास का कार्य किया जाना है। योजना के तहत तीर्थस्थलों पर बुनियादी ढांचों के विकास से एक ओर जहां तीर्थयात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होंगी, वहीं दूसरी ओर अधिक से अधिक पर्यटक इन स्थलों की ओर आकर्षित होंगे। मंत्रालय द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मिशन निदेशालय की स्थापना की गई है जो योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

ग्रामीण पर्यटन की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली एक और महत्वाकांक्षी योजना है, 'स्वदेश दर्शन'। यह योजना विषय–मूलक पर्यटन सर्किट (परिधियों) के समेकित विकास पर आधारित है। यह सर्किट हैः दक्षिण–पूर्व भारत सर्किट, बुद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्णा सर्किट, मरुस्थल सर्किट, आदिवासी सर्किट, पारिस्थतिकी सर्किट, वन्य जीवन सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट एवं धरोहर सर्किट। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से क्रमबद्ध एवं सुनियोजित ढंग से 13 चयनित पर्यटन सर्किट

'आमार आलोही', आतिथ्य सत्कार पर आधारित नवाचार

ग्रामीण पर्यटन एवं पारिस्थतिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से असम सरकार द्वारा 'आमार आलोही' (हमारा अतिथि) नामक ग्रामीण 'होम–स्टे' योजना की ओर कदम बढ़ाया गया है।

Awesome Assam
Department of Tourism

योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को घर में उपलब्ध समस्त आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रथम चरण (2017–18) में इस योजना के तहत कुल 200 ग्रामीण होम–स्टे स्थापित किए जाने की योजना है। पहले से इस तरह का रोजगार कर रहे परिवारों को इस योजना के तहत एक अधिकृत पर्यटन इकाई के रूप में पहचान दी जाएगी, साथ ही साथ कारोबार बेहतर बनाने के लिए आवश्यक पेशेवर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। आमार आलोही पर आधारित नया काम शुरु करने वाले परिवारों को योजना के तहत असमिया अंदाज़ के कॉटेज निर्माण के लिए 70 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी जबकि शेष 30 प्रतिशत का प्रबंध उद्यमियों द्वारा बैंकों अथवा अन्य स्रोतों से किया जाएगा। यह योजना पर्यटकों के लिए सुविधाजनक तो है ही, यह ग्रामीण समुदाय के लिए रोजगार का एक ऐसा अनूठा तरीका है जिसके माध्यम से वह अपनी कला–संस्कृति से जुड़े रहकर अपने अतिथियों की सेवा भी कर सकते हैं और अपनी जीविका भी अर्जित कर सकते हैं।

ऐसे ही प्रयास विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य संबंधित राज्यों की सांस्कृतिक धरोहरों एवं परंपराओं को संजोने के साथ–साथ रोजगार का सृजन करना भी है।

के विकास की योजना है। पर्यटकों की सुविधा के लिए इन चयनित स्थलों पर गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचों का विकास किया जाना है। योजना के तहत सरकार द्वारा अभी तक दो दर्जन से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। यह परियोजनाएं अपने–अपने ढंग से योजना को सहयोग प्रदान करेंगी। 'प्रसाद' योजना की ही तरह इस योजना का क्रियान्वयन भी मिशन मोड में किया जाएगा।

अक्तूबर, 2017 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों एवं अन्य साझीदारों के सहयोग से राष्ट्रव्यापी 'पर्यटन पर्व' का आयोजन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य देश की सांस्कृतिक विविधता का प्रचार–प्रसार करना था। पांच अक्तूबर 2017 से 25 अक्तूबर, 2017 तक चले इस अभियान के तीन प्रमुख घटक थे, 'देखो अपना देश','पर्यटन सभी के लिए' तथा 'पर्यटन एवं शासन–व्यवस्था'। इस अभियान के तहत विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थानों के सहयोग से विभिन्न गतिविधियों द्वारा देश की संस्कृति को उजागर करने के प्रयास किए गए। अभियान के अंतर्गत कपड़ा मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्थलों पर हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किए जाने से ग्रामीण क्षेत्र के बुनकरों एवं हस्तशिल्पकारों को प्रश्रय मिला, साथ ही साथ उनके हुनर को भी व्यापक–स्तर पर पहचान मिली। इसी प्रकार ग्रामीण मंत्रालय के 'नेशनल रुर्बन मिशन' द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन पर आधारित विभिन्न गतिविधियों की श्रृंखला आयोजित की गई। यहां गुजरात के सूरत में आयोजित ग्रामीण ओलंपिक का उल्लेख करना आवश्यक है जिसका लक्ष्य ग्रामीण गुजरात की सुंदरता को राष्ट्रीय फलक पर लाने के साथ–साथ ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रश्रय देना भी था। पर्यटन पर्व जैसे राष्ट्रव्यापी आयोजन से ग्रामीण पर्यटन को प्रत्यक्ष तो नहीं किंतु अप्रत्यक्ष रुप से सहयोग मिला और ग्रामीण पर्यटन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा।

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने वाला एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है, 'इंक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट/होमस्टे'। यह योजना विदेशी एवं भारतीय पर्यटकों को सुदूर अंचलों में भुगतान के आधार पर भारतीय परिवारों के साथ रहने एवं आवासीय सुविधाएं प्रदान करने पर आधारित है। दो श्रेणियों, 'सिल्वर' एवं 'गोल्ड' में पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। देश के पांच क्षेत्रों–उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एवं केंद्र तथा उत्तर–पूर्व में कुल 313 इकाइयों की पहचान की गई है जिनका पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत अनुमोदन एवं पंजीकरण किया गया है। योजना के तहत ऐसी इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें संबंधित मालिक अथवा देखभालकर्ता अपने परिवार के साथ रहता हो तथा पर्यटकों के लिए न्यूनतम एक तथा अधिकतम छह कक्ष उपलब्ध हों। इसके तहत किसी प्रकार के वित्तीय अनुमोदन का प्रावधान नहीं है किन्तु योजना के कुशल संचालन हेतु मंत्रालय द्वारा पांच क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं, जो संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के

ई–टूरिस्ट वीज़ा से विदेशी पर्यटकों को आसानी

विदेशी पर्यटकों के लिए भारत भ्रमण आसान करने के लिए 'ई–टूरिस्ट वीज़ा' या 'टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल' जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं, जिससे देश में पर्यटकों की आमद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ई–वीज़ा प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, यानी इसमें किसी एजेंट या मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट https://indianvisaonline.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इसके माध्यम से अपनी विदेश यात्रा की योजना बनाते समय पर्यटक अपने घर बैठे ही वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। वीज़ा फीस भी ऑनलाइन ही जमा की जाती है और दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। आवेदन दुरुस्त पाए जाने और पात्रता होने पर ऑनलाइन वीज़ा जारी कर दिया जाता है। ई–वीज़ा की सुविधा 164 देशों के लिए उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन के बाद भारत आने पर एयरपोर्ट या निकास टर्मिनल पर पर्यटक को अपने पासपोर्ट पर आव्रजन डेस्क पर मुहर लगवानी पड़ती है।

ई–वीज़ा के लिए शर्तें

- वे सभी भ्रमणकर्ता आवेदन कर सकते हैं, जिनके भारत–भ्रमण का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, दृश्यावलोकन, दोस्तों या रिश्तेदारों से आकस्मिक मुलाकात, कम अवधि का चिकित्सा पर्यटन, या आकस्मिक व्यापारिक भ्रमण है।
- पर्यटक के भारत पहुंचने के समय उसका पासपोर्ट कम से कम छह माह की अवधि के लिए वैध होना चाहिए। और उसमें कम से कम दो सादे पृष्ठ आव्रजन अधिकारी द्वारा मुहर लगाने के लिए होने चाहिए।
- राजनयिक या सरकारी पासपोर्टधारकों के लिए ई–वीज़ा की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- पाकिस्तानी पासपोर्टधारकों या पाकिस्तानी मूल के निवासियों के लिए ई–वीज़ा की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- सभी भ्रमणकर्ताओं के पास व्यक्तिगत पासपोर्ट होने चाहिए यानी एक ही पासपोर्ट पर बच्चे/पति पत्नी का नाम होने पर यह सुविधा नहीं मिलेगी।

को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए राजनयिक प्रयासों से न केवल दूसरे देशों के लोगों में भारत के प्रति उत्सुकता जगी है, बल्कि उन देशों में भारतीयों का जाना भी आसान बना है। हालांकि प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर, 2017 को आकाशवाणी पर ''मन की बात'' कार्यक्रम में लोगों से आग्रह किया कि वे विदेशों की कृत्रिम चकाचौंध से आकर्षित होकर विदेश भ्रमण करने के बजाय अपने देश के रमणीय स्थलों को देखें और अपने देश की विविधता को जानें। उन्होंने कहा कि उन्हें विदेश भ्रमण पर ऐतराज नहीं है, लेकिन लोगों को अपने देश को भी देखना और समझना चाहिए।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए बहुत कुछ है। अब चाहे वह राजस्थान के मरुस्थल की सुनहरी आभा हो, झारखण्ड के जंगल, लेह के पहाड़ी इलाके़ या फिर असम के कछार और पर्वतीय गांव; विविधताएं हर जगह भरी पड़ी हैं। राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन देशवासियों में पर्यटन के प्रति रुचि जगाने का मूलमंत्र है– ऐसी बेहतर परिवहन व्यवस्था और आधारभूत सुविधाएं, जो हर प्रकार के आय वर्ग के लोगों के अनुकूल हों। इसमें न केवल सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है, बल्कि इससे भी बड़ी भागीदारी निजी क्षेत्र के उद्यमों और पर्यटन के पेशे से जुड़े लोगों की है। साथ ही ज़रूरत है स्वच्छ, सुरक्षित एवं प्रदूषण रहित माहौल उपलब्ध कराने की ताकि देशी–विदेशी पर्यटकों में भारत के गांवों की सकारात्मक छवि उभरे और वे अपने भ्रमण को लंबे समय तक याद रख सकें।

सहयोग से योजना को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं।

देश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों, टूर–ऑपरेटरों और इस उद्योग से जुड़ी संस्थाओं व एजेंसियों को पुरस्कार देने की योजना चलाई है। ''हॉल ऑफ फेम'' अवार्ड उन राज्य सरकारों/संस्थाओं को दिया जाता है, जो लगातार तीन वर्षों तक एक ही श्रेणी में पुरस्कार पाती रही हैं। समेकित पर्यटन विकास के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए यह पुरस्कार इस बार गुजरात और मध्यप्रदेश की सरकारों को दिया गया है। सोशल मीडिया/एप के बेहतर इस्तेमाल के लिए केरल के पर्यटन विभाग को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा चार टूर ऑपरेटरों को भी यह पुरस्कार दिया गया। समेकित पर्यटन विकास के लिए इस बार आंध्र प्रदेश को प्रथम, राजस्थान को द्वितीय और केरल तथा गोवा

एक प्रयास ऐसा भी!

उत्तराखण्ड में पहले से चल रही 'होम–स्टे' योजना को दीनदयाल उपाध्याय रोज़गार योजना के नाम से एक नया जामा पहनाया गया है। योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में होम–स्टे के माध्यम से रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है। योजना के बेहतर संचालन के लिए इसके तहत संचार कौशलों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इससे योजना के लाभार्थीगण (होम–स्टे संचालक) विभिन्न विदेश भाषाएं सीख सकेंगे और बेहतर ढंग से विदेशी पर्यटकों से जुड़ सकेंगे। दूसरी ओर, विदेशी पर्यटकों की भी भाषा संबंधी समस्या कुछ हद तक हल हो सकेगी और उनकी भारत यात्रा यादगार बन सकेगी।

आज आवश्यकता इस बात की है कि पर्यटन के उच्चस्तरीय मूल्यों का विकास हो, पर्यटक अपने आप को ठगा हुआ महसूस न करें, इसके लिए विभिन्न भागीदारों के बीच स्वच्छ प्रतियोगिता विकसित की जाए और इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोज़गार के अवसर उपलब्ध हों, तभी पर्यटन को हम एक टिकाऊ व्यवसाय के रूप में विकसित कर सकेंगे।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के हालिया प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यटन के साथ–साथ विकास प्रक्रिया को भी गति मिलेगी, साथ ही साथ आय के एक नवीन स्रोत के सृजन से जीवन–स्तर बेहतर बनेगा। इसका एक अन्य लाभ यह होगा कि ग्रामीणों को रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा बल्कि वह अपने ही गांव में रहकर जीविकोपार्जन कर सकेंगे। अलग–थलग पड़े ग्रामवासी देश की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। इस प्रकार सरकार का यह प्रयास ग्रामीण विकास की दिशा में बेहतरीन प्रयास है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : hena.naqvipti@gmail.com

ग्रामीण पर्यटन में रोजगार के अवसर

–हरिकिशन शर्मा

अगर ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं को सुनियोजित ढंग से विकसित कर प्रभावी तरीके से अमल में लाया जाता है तो गांव के कुशल और प्रशिक्षित युवाओं को उनके घर के पास ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्र से शहरों को होने वाले पलायन में भी कमी आएगी। साथ ही, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्तर भी ऊपर उठेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजित करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संख्या में साल–दर–साल वृद्धि इसका प्रमाण है। वर्ष 2016 में 88 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए जिससे देश को 22.92 अरब डालर (1,54,146 करोड़ रुपये) विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। हालांकि पिछले साल वैश्विक–स्तर पर अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 123 करोड़ रही जिसमें मात्र 1.18 प्रतिशत ही विदेशी पर्यटक भारत आए। इसी तरह दुनियाभर में पर्यटन से जितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, उसका दो फीसदी से भी कम भाग भारत की झोली में आता है। विश्व के कई विकसित और विकासशील देश ऐसे हैं जो भौगोलिक क्षेत्रफल या जनसंख्या के आधार पर भारत से छोटे हैं लेकिन वहां बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक जाते हैं। यही वजह है कि सरकार ने अधिकाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 'इन्क्रेडिबल इंडिया' जैसे अभियानों का सहारा लिया। साथ ही पर्यटन के नए–नए रूप जैसे 'इको टूरिज्म', 'हेल्थ टूरिज़्म' 'हेरिटेज टूरिज़्म' और 'ग्रामीण पर्यटन' को विकसित करने पर बल दिया है। सरकार की पहल और निजी उद्यमिता के परिणामस्वरूप 'ग्रामीण पर्यटन' अब धीरे–धीरे लोकप्रिय होने लगा है।

शहरों की भीड़ भरी जिंदगी से कुछ दिनों के लिए निजात और एकांत की तलाश लोगों को गांवों की ओर आकर्षित कर रही है। समृद्ध सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विविधता से परिपूर्ण भारत में 'ग्रामीण पर्यटन' की अपार संभावनाएं हैं लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। देश की दो तिहाई से अधिक आबादी करीब साढ़े छह लाख गांवों में ही निवास करती है। सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने के लिए सड़क, रेल और हवाई यातायात जैसी ढांचागत सुविधाएं विकसित करना जितना कठिन है, उतना ही मुश्किल इस क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास है। कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन के बगैर ग्रामीण अंचल में पर्यटन के विकास की कल्पना करना मुश्किल है। दुर्भाग्य से अब तक इस दिशा में कुछ खास प्रयास नहीं हुए हैं। ग्रामीण पर्यटन के लिए किस तरह के मानव संसाधन की आवश्यकता है, न तो इस पर कोई नीतिगत दस्तावेज तैयार हुआ और न ही उनके कौशल प्रशिक्षण के लिए अलग से कोई संस्थान स्थापित किया गया। वास्तविकता यह है कि 'ग्रामीण पर्यटन' के लिए मानव संसाधन विकास के संबंध में अब तक नीति और रणनीति का अभाव रहा है।

'ग्रामीण पर्यटन' की अवधारणा और उसका विकास

भारत में 'ग्रामीण पर्यटन' की अवधारणा सर्वप्रथम राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 में पेश की गई। इसमें 'एग्रो रूरल टूरिज्म' को प्रोत्साहित करने का विचार दिया गया। इस नीति में 'ग्रामीण पर्यटन' को परिभाषित करते हुए कहा गया, ''पर्यटन का वह रूप

जो ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और ग्रामीण स्थलों पर धरोहर को प्रदर्शित करता है, जिससे स्थानीय समुदाय को आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त होता है और जो सुखद पर्यटन अनुभव के लिए पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच विचार विनिमय में मदद करता है, उसे 'ग्रामीण पर्यटन' कहा जा सकता है।'' इसके साथ ही तत्कालीन योजना आयोग ने भी नौवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिन छह क्षेत्रों की पहचान की उनमें 'ग्रामीण पर्यटन' को प्रमुख स्थान दिया गया। इस अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए 2002 में सरकार ने 'ग्रामीण पर्यटन योजना' बनाई जिसके तहत ग्रामीण अंचल में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने पर बल दिया गया। बाद में इसे एक पायलट परियोजना 'एंडोजीनियस टूरिज्म प्रोजेक्ट' के तौर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से लागू किया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण पर्यटन पर विशेष बल देते हुए असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नगालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और उत्तरांचल में ग्रामीण पर्यटन परियोजनाएं विकसित करने की शुरुआत हुई। इस पचंवर्षीय योजना की अवधि में कुल मिलाकर करीब ऐसी 80 ग्रामीण पर्यटन परियोजना पर काम शुरू किया गया। प्रत्येक परियोजना के लिए सरकार ने 50 लाख रुपये भी उपलब्ध कराए। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में कुछ खास प्रगति न होते देख सरकार ने 'ग्रामीण पर्यटन' के संबंध में अपनी नीति में व्यापक बदलाव किया। पहले जहां एक गांव पर फोकस किया जा रहा था वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच–छह गांवों के 'ग्रामीण पर्यटन कलस्टर' (आरटीसी) विकसित करने की रणनीति तैयार की गई। तत्कालीन योजना आयोग के मुताबिक छह गांवों का एक 'ग्रामीण पर्यटन कलस्टर' विकसित करने पर करीब 11 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस तरह ग्रामीण पर्यटन कलस्टर बनाने पर अपेक्षाकृत कम धनराशि ही खर्च होगी।

मानव संसाधन विकास

पर्यटन में देश का आर्थिक इंजन बनने की संभावनाएं विद्यमान हैं लेकिन इसके लिए जिस तरह ढांचागत सुविधाएं जरूरी हैं उसी तरह प्रशिक्षित और व्यवहार–कुशल (टूरिस्ट फ्रेंडली) श्रमबल भी आवश्यक है। ऐसा अनुमान है कि अर्थव्यवस्थाओं में निर्माण क्षेत्र के बाद रोजगार देने वाला अगला क्षेत्र पर्यटन ही होगा। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) का अनुमान है कि 2022 तक पर्यटन के क्षेत्र में देश में 50 लाख नए कुशल व्यक्तियों की दरकार होगी। इसलिए इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकास आज समय की जरूरत है। खासकर 'ग्रामीण पर्यटन' की दृष्टि से श्रमबल को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। हालांकि पर्यटन क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास के संबंध में सरकार की जो रीति रही है, उसमें ग्रामीण पर्यटन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कौशल, प्रशिक्षण और शिक्षण का ढांचा खड़ा नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास के लिए छह सूत्रीय रणनीति अपनाई जो इस प्रकार है–

1. नए होटल प्रबंधन संस्थान और फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खोलना;
2. आइएचएम के ढांचे को उन्नत और सुदृढ़ बनाना;
3. आइएचएम में क्राफ्ट कोर्स शुरू करना;
4. 'हुनर से रोजगार' योजना के तहत अल्पावधि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना;
5. आतिथ्य, शिक्षण और प्रशिक्षण का विस्तार करना;
6. मौजूदा सेवा प्रदाताओं की स्किल टैस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन।

इस रणनीति को अमल में लाने के लिए 2008 में सरकार ने दो योजनाओं को मंजूरी भी दी। इनमें से पहली योजना होटल प्रबंधन संस्थानों, फूड क्राफ्ट संस्थानों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, नेशनल कौंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टैक्नोलॉजी, व्यावसायिक स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटैक्निक संस्थान, सरकारी कालेज और विश्वविद्यालयों को वित्तीय मदद मुहैया कराने से संबंधित थी। दूसरी योजना सेवा प्रदाताओं की क्षमता संवर्धन से संबंधित थी।

इस तरह साफतौर पर स्पष्ट है कि सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास की जो रणनीति तैयार की उसमें ग्रामीण पर्यटन की जरूरतों को तबज्जो नहीं दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम है। स्थानीय भाषा में गाइड तैयार करने से लेकर स्थानीय क्यूजाइन में माहिर श्रमबल तैयार करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके अलावा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कई खामियां भी रहीं। मसलन, ग्रामीण पर्यटन योजना की शुरुआत के साथ से ही जिला कलेक्टरों को उनके जिले में इसका नोडल अधिकारी बनाया गया लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण इस योजना के क्रियान्वयन पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि सरकार ने 2008 में ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पर्यटन विभागों को सौंप दी। इसके बाद इस दिशा में राज्यों ने कुछ कदम उठाना शुरू किया।

बहरहाल ग्रामीण पर्यटन के लिए अलग से मानव संसाधन विकास का कोई समर्पित तंत्र नहीं है। पर्यटन क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए सरकार ने जो तंत्र खड़ा किया है, उसी के भरोसे यह काम भी किया जा रहा है। फिलहाल देश में 42 होटल मैनेजमेंट संस्थान (आइएचएम) हैं जिनमें 21 केंद्रीय आइएचएम और 21 राज्य आइएचएम हैं जबकि 10 फूड क्राफ्ट संस्थान हैं। हाल के वर्षों में एक नया इंडियन कलनरी इंस्टीट्यूट तिरुपति में शुरू किया गया है जबकि इसकी एक शाखा नोएडा में स्थापित की जा रही है। यह अकेला संस्थान है जो पाक कला और व्यंजन कला (कलनरी एंड क्यू जाइन) में तीन साल की डिग्री प्रदान कर रहा है। इसकी शुरुआत 30 छात्रों के बैच के साथ

अगस्त 2016 में हुई थी।

ग्रामीण पर्यटन के लिए मानव संसाधन विकास में सरकार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लायड के टी. जी. बौम और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच के जे. जे. कोक्क्रीनीकल ने 2002 में केरल में जब इस विषय पर शोध किया तो पाया कि ग्रामीण समुदाय में पर्यटन के लिए मानव संसाधन विकास की व्यवस्था में कई खामियां हैं। शुरुआती दौर में निजी क्षेत्र की उपस्थिति सीमित होने के चलते सार्वजनिक क्षेत्र को स्थानीय समुदायों को अर्थपूर्ण तरीके से भागीदार बनाने के लिए पहल करने की जरूरत है। बौम और कोक्क्रानीकल ने केरल में ग्रामीण पर्यटन के लिए मानव संसाधन के विकास पर अपने शोध के बाद जो दस निष्कर्ष पेश किए उनमें सबसे ऊपर वित्तीय संसाधन का अभाव बताया। इसके बाद उन्होंने कौशल, शिक्षा, उद्यमिता और गुणवत्ता नियंत्रण के अभाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने यह भी उजागर किया कि किस तरह सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों की वजह से लोग पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार अपनाने से परहेज कर रहे हैं।

इस तरह बौम और कोक्क्रानीकल ने केरल का उदाहरण देकर ग्रामीण पर्यटन के लिए मानव संसाधन के विकास की राह में चुनौतियों को सामने रखने का प्रयास किया। समय–समय पर पर्यटन संबंधी संसद की स्थायी समिति ने भी इस क्षेत्र में मानव–संसाधन विकास की स्थिति को लेकर अपनी चिंता प्रकट की है।

हाल के वर्षों में सरकार की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में मानव–संसाधन विकास के लिए जो प्रमुख पहल हुई है उसमें 'हुनर से रोजगार तक' योजना भी शामिल है। इसके तहत युवाओं को हॉस्पिटलिटी क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। खास बात यह है कि विगत की गलतियों से सीख लेते हुए इसके क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाया गया है। इसके तहत फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज, हाउसकीपिंग, टूर असिस्टेंस, सिक्युरिटी गार्ड और बेकरी जैसे उत्पाद बनाने का प्रशिक्षिण दिया जा रहा है। वित्तवर्ष 2016–17 में हुनर से रोजगार तक योजना के तहत करीब पंद्रह हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वित्तवर्ष 2017–18 में करीब 86,000 युवाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र कोर्स उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

हुनर से रोजगार योजना के तहत निम्न कोर्स किए जा सकते हैं– फूड एंड बेवरेज सर्विस; फूड प्रोडक्शन; हाउस कीपिंग; बेकरी; फ्रंट ऑफिस; इवेंट फैसिलिटेटर और टूर असिस्टेंट।

बहरहाल 'हुनर से रोजगार तक' योजना के जरिए सरकार शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के लिए कौशल विकास का प्रयास कर रही है। हालांकि अब तक जो प्रयास हुए हैं, वे नाकाफी साबित हुए हैं। 'ग्रामीण पर्यटन' के लिए मानव संसाधन विकास के लिए सरकारी योजनाओं के साथ–साथ स्थानीय निकायों को भी अपने स्तर पर पहल करनी चाहिए। हाल के वर्षों में देश की ढाई लाख पंचायतों में अधिकतर तक कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है। ग्रामीण पर्यटन के लिए मानव संसाधन विकास करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटरों की मदद ली जा सकती है। साथ ही सामान्य स्कूली शिक्षा में भी पर्यटन को शामिल किया जा सकता है। वहीं निजी उद्योगों के साथ–साथ गैर–सरकारी संगठनों को भी इस कार्य में भागीदार के रूप में जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से जिन युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए, उनका एक ऑनलाइन डाटाबेस तैयार किया जा सकता है ताकि क्षेत्र विशेष में जरूरत होने पर सर्टिफाइड मानव संसाधन उपलब्ध हो सकें। प्रशिक्षण के काम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआई) अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही गैर–सरकारी संगठनों और पंचायती राज संस्थानों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

वास्तव में ग्रामीण पर्यटन में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। हाल में विश्व बैंक ने एक निजी कंपनी के साथ मिलकर भारत में ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं पर निवेश करने की घोषणा भी की है। अगर ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं को सुनियोजित ढंग से विकसित कर प्रभावी तरीके से अमल में लाया जाता है तो गांव के कुशल और प्रशिक्षित युवाओं को उनके घर के पास ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्र से शहरों को होने वाले पलायन में भी कमी आएगी। साथ ही, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्तर भी ऊपर उठेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेल : hari.scribe@gmail.com

भारत में ग्रामीण पर्यटन संसाधनों का विकास जरूरी

–शिशिर सिन्हा

ग्रामीण पर्यटन उद्योग की संभावनाएं कितनी हैं, इस बारे में अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है। साथ ही ऐसा कोई आंकड़ा नहीं जो बताए कि कितने लोग ग्रामीण पर्यटन के लिए जाते हैं। फिर भी ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं को पर्यटकों की संख्या से खंगाला जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2017 में जनवरी से अक्टूबर के दौरान करीब 80 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए। इस दौरान पर्यटन के जरिए 1.40 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की विदेशी मुद्रा में कमाई हुई। अब इन दोनों का महज 10 फीसदी भी ग्रामीण पर्यटन के लिए जाता है तो जरा सोचिए किस तरह से वहां पर लोगों को फायदा होगा।

ज्यादा दिन नहीं हुए। स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस की सीमा पर बसे एक गांव में जाने का मौका मिला। आधुनिक सुख–सुविधाओं के बीच गांव के स्वरूप को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। गांव में एक बहुत ही पुराना शैटो (chateau यानी महल, दुर्ग या प्रसाद) था। ये तो याद नहीं कब का बना था, लेकिन बताया गया कि कुछ सौ साल पुराना है। शैटो के मूल मालिक के वशंज पर्यटन विभाग के साथ मिलकर तरह–तरह के सांस्कृतिक आयोजन करते हैं और वहां ज्यूरिख या जेनेवा से पर्यटकों को विशेष तौर पर लाया जाता है। शैटो ने पूरे गांव को एक आर्थिक इकाई में तब्दील कर दिया है।

खैर, शैटो में सांस्कृतिक आयोजन के बाद पारंपरिक भोजन परोसा जाता है। किसी कारणवश मुझे वो पारम्परिक भोजन पसंद नहीं आया। लिहाजा बाजार में कुछ और ढूंढ़ने निकला। तभी हिंदी गाने की आवाज कानों में पड़ी। यकीन नही हो रहा था। आवाज की दिशा में आगे बढ़ा तो बॉम्बे होटल का बोर्ड नजर आया। वहां प्रवेशद्वार पर ही उत्तराखंड के मूल निवासी रमेश से मुलाकात हुई। पता चला कुछ समय पहले वो घूमने आए थे। वहां उन्होंने कई हिंदुस्तानियों को देखा जो भारतीय भोजन करना चाहते थे, लेकिन वो वहां उपलब्ध नहीं था। बस यहीं से उनके मन में आया कि क्यों ना वहां एक भारतीय रेस्तरां खोला जाए। थोड़ी–बहुत परेशानी तो हुई लेकिन आज उनका रेस्तरां काफी बढ़िया चलता है। गांव से अपने बावर्ची चाचाओं को बुला लिया। कामचलाऊ फ्रेंच भी सीख लिया है। बस काम हो गया।

क्या मतलब है इस प्रसंग का? जवाब के लिए दो बातों पर ध्यान दीजिए। पहला तो ये कि किस तरह से अपने पूर्वजों की धरोहर को लोग न केवल बचाए हुए हैं, बल्कि उसका रखरखाव कर अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीविका का इंतजाम किए हुए हैं। वहीं दूसरी बात ये है कि उस गांव में एक भारतीय जाकर जीविका का साधन ढूंढ लेता है। इस बारे में जब रमेश से सवाल पूछा तो उसका कहना था कि अगर उसके राज्य में कुछ गांवो में बेहतर बुनियादी सुविधाओं के बूते पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो वो निश्चित तौर पर भारत वापस लौट आएगा चूंकि अपना देश अपना ही होता है।

बड़ा सवाल ये कि क्या ग्रामीण पर्यटन का अर्थशास्त्र देश में इतना मजबूत है जो रमेश जैसे लोगों को तो विदेश से वापस बुलाए ही, साथ ही अपने ही देश में गांव से रोजगार की तलाश में शहर पलायन करने वालों को भी रोका जा सके। इस बारे में चर्चा बढ़ाने के पहले 2011 की जनगणना की कुछ खास बातों पर नजर डालना जरूरी है। 2011 की जनगणना के शुरुआती नतीजों पर रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर की ओर से पेश ब्यौरे (http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/paper2/data_files/india/Rural_Urban_2011.pdf) के मुताबिक

- गांवों की कुल संख्या 6.40 लाख से ज्यादा दर्ज की गई;
- 121 करोड़ की कुल आबादी में 83.3 करोड़ यानी 68.84 फीसदी गांवों में रहती थी;
- लेकिन कुल आबादी में ग्रामीण आबादी की हिस्सेदारी 2001 के 72.19 फीसदी से घटकर 68.84 हो गई।
- वहीं दूसरी ओर शहरीकरण का स्तर 27.81 फीसदी से बढ़कर 31.16 फीसदी हो गया।

मतलब साफ है कि गांवों में अभी भी बड़ी आबादी रहती हो, लेकिन उनके लिए जीविका के साधन सीमित होते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बस किसानी पर जीविका चलाना आसान नहीं। अब ऐसे में क्या कुछ ऐसे किया जाए जिससे गांव, गांव रह सकें, और गांव वालों के लिए अच्छी आमदनी का इंतजाम हो सके। और ये मुमकिन हो सकता है ग्रामीण पर्यटन के जरिए। गौर करने की बात ये है कि पर्यटन बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके मुहैया कराता है।

क्यो जाएं गांव में सैर–सपाटे के लिए

ग्रामीण परिवेश जहां आपको प्रकृति के काफी करीब ले जाता है, वहीं आप सभ्यता–संस्कृति के विभिन्न रंग, परम्पराओं और हस्तकला–हस्तशिल्प से सीधे–सीधे रू–ब–रू होते हैं। और हां, यदि आप रोमांच के शौकीन हैं तो देश के कई ग्रामीण इलाके आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। एक बात और, यदि आध्यात्म के लिए आना चाहें तो उसके लिए भी कई विकल्प मौजूद हैं। सच पूछिए तो भारत की वास्तविक तस्वीर देखनी है तो शहरों के बजाए गांवों में आपको जाना चाहिए। पर्यटन विभाग ने ऐसे विभिन्न गंतव्यों की सूची तैयार कर रखी है, जहां आप अपनी रूचि के हिसाब से पर्यटन के लिए जा सकते हैं (चुनिंदा जगहों के लिए देखें सूची संख्या–1)

कैसे विकसित हो ग्रामीण पर्यटन

गांव में सबसे जरूरी है बुनियादी सुविधाओं का विकास। पर्यटन मंत्रालय की ओर से यहां पर एक विशेष योजना चलाई जाती है जिसे 'गंतव्य विकास' के नाम से जाना जाता है। इसके लिए उन गांवों या उन ग्रामीण क्षेत्रों का चयन किया जाता है जहां पर्यटन की काफी संभावनाएं हो। इस योजना का मकसद जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जीवन, संस्कृति, कला और विरासत को प्रदर्शित करना है, वहीं दूसरी ओर ऐसे गांवों को प्राकृतिक माहौल में संपत्ति के रूप में विकसित करना है जो कला–संस्कृति, हस्तकला और वस्त्रों के मामले में खास स्थान रखता हो। इस पूरी कवायद का मकसद ग्रामीण समुदायों को हर तरह की मदद पहुंचाना है। यही नहीं पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच संवाद से दोनों ही कुछ नया सीख सकेंगे।

योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन से गांव वालों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर फायदा पहुंचाने का लक्ष्य है। इससे गांवों से शहरों की ओर पलायन रुक सकेगा। बुनियादी सुविधाएं विकसित होने के बाद एक गांव पर्यटक का स्वागत करने के लिए तैयार होता है। पर्यटक जब वहां आकर खर्च करता है तो स्थानीय लोगों के लिए आमदनी का जरिया तो खोलता ही है, साथ ही वो खरीदारी कर स्थानीय हस्तकला व हस्तशिल्प को बढ़ावा देता है। पर्यटकों के लिए ग्रामीण संस्कृति, कला और गीत–संगीत–नृत्य वगैरह से परिचित होने का मौका भी मिलता है जो कलाकारों को

कैसे चले गांवों की ओर

गांव अच्छे हैं। सभी सुविधाएं भी हैं। फिर भी परेशानी ये है कि इन जगहों की जानकारी मिले तो कैसे? इस काम में आपकी मदद के लिए कुछ स्रोत आसानी से उपलब्ध हैं। मसलन https://www.tripsavvy.com या फिर https://www.outlookindia.com/outlooktraveller पर आप जाकर देश के ग्रामीण पर्यटन के प्रमुख जगहों की जानकारी ले सकते हैं। अब पहले वाले ही वेबसाइट को ले लीजिए। ग्रामीण पर्यटन के लिए दस प्रमुख आकर्षणों का पूरा ब्यौरा दिया गया है। मसलन, गुजरात के कच्छ को ले लीजिए। आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह कच्छ के होडका गांव (www.hodka.in) मे आप मिट्टी के बने घरों या टेंट में रह सकते हैं। यही नहीं अगर आप खुले आकाश के नीचे खटिया पर तारों को निहारना चाहते हैं तो उसका भी इंतजाम किया गया है। यदि आपकी इच्छा पंजाब जाने की है तो वहां अमृतसर के करीब गांव में विशेष इंतजाम हैं, जहां दूध दुहने के साथ ट्रैक्टर चलाने, धार्मिक समारोहों में भाग लेने और गांव में खुलकर घूमने–फिरने का मजा ले सकते हैं।

दूसरी ओर, राजस्थान में बिश्नोई समुदायों को करीब से जानना है तो जोधपुर चले आइए और वहां से कुछ ही दूर स्थित बिश्नोई गांव में आप अलग ही जिंदगी जी लेंगे। ये समुदाय प्रकृति के साथ इतना प्यार करता है कि वहां मृत शरीर जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया जाता है, ताकि पेड़ बचाए जा सकें। यहां विशेषतौर पर बने घरों में आप रह सकते हैं। वहां ऊंट की सवारी से लेकर ट्रैकिंग तक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पारम्परिक राजस्थानी खाना तो मिलेगा ही और वो भी घर में तैयार।

हेल्प टूरिज्म

ये कहना तो आसान है कि गांवों में पर्यटन की संभावना है, लेकिन इन संभावनाओं का दोहन आसान नहीं। खासतौर पर बात जब पूर्वोत्तर जैसे राज्यों की आती हो तो वहां ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी ऐसी मुश्किलों का हल ढूंढने की पहल करीब 26 साल पहले हुई जब हेल्प टूरिज्म नाम के निजी संगठन ने पश्चिमी सिक्किम में खास पहल की।

योजना में एक गांव के सभी 40 परिवारों को शामिल किया गया। इन परिवारों ने घर पर सैलानियों के ठहरने या फिर रेस्तरां की व्यवस्था की। लक्ष्य इलाके मे आने वाले ट्रैकर और पर्वतारोही थे। भले ही यहां पर सुविधाएं सितारा होटल के समान नहीं थी, लेकिन साफ–सुथरे और आरामदायक माहौल में हर जरूरी सुविधाएं दी गई। योजना कामयाब रही और अब ये पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में विरासत को बचाए रख स्थानीय संस्कृति से रुबरु होने का एक मजबूत माध्यम बन गया है। कोशिश यही है कि पर्यटन को संरक्षण के साथ–साथ सतत विकास का जरिया बनाया जाए। इन्ही मकसदों के आधार पर 'हेल्प' को कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया गयाः

H-eritage (विरासत)
E-nvironment (पर्यावरण)
L-ivelihood (जीविका)
P-eople (लोग)

आज हेल्प की मदद से पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके लिए आप http://www.helptourism.com/index.html की मदद से ऑलनाइन बुकिंग करा सकते हैं। यहां बुकिंग से असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाकों तक पहुंच ही सकते हैं, वहीं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में भी कुछ दिन बिताने में मदद मिलेगी। सुंदरबन को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल कर रखा है।

बढ़ावा देने के लिए बेहद जरूरी है। पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक, ग्रामीण पर्यटन की कुल 153 परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराया गया है।

कैसे हो ग्रामीणों में कौशल व उद्यमिता का विकास

इसमें कोई शक नहीं कि गांवों में रहने वाले जी–तोड़ मेहनत करने से झिझकते नहीं। लेकिन मेहनत के साथ कौशल और उद्यमिता जुड़ जाए, साथ ही पूंजी का इंतजाम भी हो जाए तो पर्यटन से जुड़ी कारोबारी संभावनाओं का दोहन करने में परेशानी नहीं होगी। इस दिशा में सरकार की कौशल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाएं मदद कर सकती हैं। मसलन,

- दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास करके उनकी रोजगार पाने की क्षमताएं बढ़ाती है;
- वहीं दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बैंकों और राज्य सरकार के सहयोग से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI) की स्थापना की गई है। इसका मकसद गरीब परिवारों के लिए ग्रामीण बेरोजगारों को प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वो अपने निवास स्थान के आसपास ही स्वरोजगार शुरू कर सकें।

पर्यटन के लिए आतिथ्य–सत्कार के तौर–तरीकों को सीखना बेहद जरूरी है। अब गांव में आकर कोई पर्यटक ठहरता है तो किस तरह से उसके लिए इंतजाम किया जाए, इस बारे में जरूरी प्रशिक्षण होटल मैनेजमेंट संस्थानों से लिया जा सकता है। इन संस्थानों से प्रशिक्षण हासिल करने के बाद पेशेवर रुख को अपनाने मे मदद मिलेगी। यही नहीं आतिथ्य सत्कार के नए तौर–तरीकों को स्थानीय संस्कृति में रंग कर पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना संभव हो सकेगा।

कौशल व उद्यमिता के बाद जरूरत होती है पूंजी की। यहां पर आपको सरकार की मुद्रा (माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) योजना से मदद मिल सकती है। मुद्रा योजना दरअसल देश में सूक्ष्म उद्यमिता यानी बहुत ही छोटे उद्यमी को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गई है। इसके तहत 10 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए बैंक व वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त की सुविधा मुहैया कराई जाती हैं। योजना के तहत तीन तरह के विकल्प शिशु (50 हजार रुपये तक का कर्ज), किशोर (50 हजार से ज्यादा लेकिन 5 लाख रुपये तक का कर्ज) और तरुण (5 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख रुपये तक का कर्ज) मौजूद हैं। योजना के तहत किसी भी तरह की छोटी दुकान खोलने से लेकर हस्तकला–हस्तशिल्प से जुड़ी छोटी–छोटी इकाईयां लगाने के लिए कर्ज मुहैया कराया जाता है। विभिन्न सहूलियतों की वजह से योजना में कर्ज पर ब्याज की दर कम होती है।

उद्यमिता के विकास में दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना से भी मदद मिलेगी। यहां कोशिश यही है कि गांव–गांव में उद्यमी तैयार हो। इसके लिए जरूरी प्रशिक्षण तो मुहैया कराया ही जाएगा, मुद्रा के जरिए पूंजी की व्यवस्था कराई जाएगी। कर में रियायतें मिलेंगी। साथ ही ऐसे उद्यमी पूरी तरह से विकास कर सकें, उनके लिए जरूरी वातावरण यानी इन्क्यूबेशन सेंटर तैयार होगा। सरकार की कोशिश निजी क्षेत्र को भी इस कवायद में शामिल करने की है जिससे ग्रामीण उद्यमिता के लिए ऐसे स्वतंत्र निवेशक मिल सकें जो ना केवल पूंजी बल्कि तकनीकी तौर पर भी सहयोग करने के लिए तैयार हो। गांवों में पर्यटन के लिए जरूरी सुविधाएं तैयार करने में ऐसी व्यवस्था काफी मददगार साबित होगी।

विपणन

पुरानी कहावत है, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। यही बात ग्रामीण पर्यटन के साथ भी लागू होती है। गांव में सब कुछ है, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा, तभी तो वो वहां जाएंगे। और

सैलानियों की सुरक्षा

शहर हो या गांव, जहां कही भी सैलानी आए हो, उनकी सुरक्षा का इंतजाम बेहद जरूरी है। क्योंकि जब सैलानी को महसूस होता है कि वो यहां सुरक्षित हैं, वो दूसरे सैलानियों को भी यहां आने के लिए प्रोत्साहित करता है। पर्यटन मंत्रालय ने सैलानियों और खासतौर पर विदेशी सैलानियों की सुरक्षा के लिए जो उपाय किए हैं, उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

- 1800111363 या फिर 1363, ये टेलीफोन नंबर है सैलानियों की मदद के लिए। यहां हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 विदेशी भाषाओं में मदद मांगी जा सकती है। इसका इस्तेमाल विदेशी सैलानियों के साथ–साथ घरेलू सैलानी भी कर सकते हैं। यहां देशभर में सैर–सपाटे के लिए पूरी जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही यदि कहीं कोई सैलानी मुसीबत में फंस जाए तो वो इस नंबर का इस्तेमाल कर राहत पा सकता है।
- जो भी विदेशी सैलानी ई–वीजा पर भारत में दाखिल होते हैं, उन्हें दिल्ली और कोचीन हवाई अड्डे पर प्री लोडेड सिम कार्ड मिलता है। इससे बिना किसी देरी के अपना फोन चालू किया जा सकता है।
- हर विदेशी सैलानी को एक स्वागत कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड के जरिए देश में अपने प्रवास को सुखदायी बनाने के लिए जरूरी जानकारी दी जाती है।
- आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू–कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मध्य–प्रदेश और ओडीसा में विशेष रूप से पर्यटन पुलिस की नियुक्ति की गई है।
- अतिथिदेवो भवः की भावना पूरी तरह से बनी रहे, इसके लिए समय–समय पर अभियान चलाए जाते हैं।

यहीं पर भूमिका है विपणन यानी मार्केटिंग की। वैसे तो अतुल्य भारत योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। इस कोशिश के तहत जहां पर्यटकों को गांवों तक लाना है, वहीं ग्रामीण हस्तशिल्प और हस्तकला के लिए शहरों में बाजार विकसित करना है जिसके जरिए पर्यटक ग्रामीण पर्यटन की ओर आकर्षित हो सकें। सरकार की योजना के तहत शिल्पकारों, दस्तकारों को विदेश ले जाने की योजना भी समय–समय पर चलती रहती है। इस कड़ी में ग्रामीण इलाकों के शिल्पकारों, दस्तकारों को सिंगापुर और दुबई तक ले जाया जा चुका है, वहीं दिल्ली–मुंबई में लगने वाली प्रदर्शनियों में इन्हें रियायती दर पर भाग लेने का मौका दिया जाता है।

ग्रामीण शिल्पकार, दस्तकार ग्रामीण पर्यटन के ब्रांड एम्बेसेडर होते हैं। शहरों में ये अपने गांव की संस्कृति–कला की नुमाइंदगी कर लोगों को अपने यहां आने के लिए न्यौता दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरुरी है कि इस तरह की प्रदर्शनी के लिए सस्ती–सहज सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। ऐसी ही सुविधा मिलती है, राष्ट्रीय राजधानी स्थित दिल्ली हाट में।

दिल्ली पर्यटन की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में तीन जगहों पर दिल्ली हाट विकसित किए गए हैं। इस हाट में पंजीकृत शिल्पकारों, दस्तकारों को 15–15 दिन के लिए बहुत ही मामूली किराये पर स्टॉल मुहैया कराया जाता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक ओर जहां हस्तकला की लागत नहीं बढ़ती, वहीं देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों को अपने सामान बेचने में मदद मिलती है। खास बात ये है कि दिल्ली हाट में केवल हस्तकला या दस्तकारी के सामान ही नहीं बिकते, अलग–अलग प्रांतों के भोजन भी मिलते हैं। समय–समय पर सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाते हैं। ये सब कुछ केवल ग्रामीण कारीगरों को जीविका का साधन मुहैया कराने के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि उसका एक मकसद लोगों को गांवों तक खींच लाना भी है।

डिजिटल दौर में विपणन

ये दौर इंटरनेट का है और इस दौर में डिजिटल माध्यमों से विपणन न केवल सस्ता पड़ता है, बल्कि आसानी से दूर–दूर तक पहुंच जाता है। अच्छी बात ये है कि डिजिटल के लिए ग्रामीण इलाकों में जरूरी बुनियादी सुविधाएं तेजी से विकसित की जा रही है। इसी के तहत 1.8 लाख किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाया जा चुका है और अगले साल दिसंबर तक इसे 10 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य है। अभी तक 17 हजार ग्राम पंचायतों में भारत नेट चालू हो चुका है जबकि 78500 गांवों को ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। इन सबके अलावा निजी क्षेत्र की साझेदारी मे चालू कारोबारी साल के दौरान 20 हजार वाई–फाई हॉट स्पॉट विकसित करने की योजना है।

अब इन आंकड़ों का एक मतलब तो ये है कि ग्रामीण पर्यटन के लिए डिजिटल माध्यमों से जहां प्रचार–प्रसार का रास्ता तैयार हो चुका है, वहीं जो भी इन गांवों में आएगा, उसे बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए रखने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कई जगहों पर शहरों की तरह आसानी से इंटरनेट सुविधा हासिल हो सकेगी।

आज गांवों का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन स्वाभाविकता नहीं। जरुरत है कि इसी का फायदा उठाया जाए और लोगों को गांवों की ओर ले चला जाए। ऐसा हुआ तो रमेश, सुरेश, मोहम्मद या ऐसे ही किसी को गांव छोड़ने की जरुरत नहीं होगी। गांवों का विकास तो होगा ही, शहरों पर बोझ कम होगा और अंत में इन सबका फायदा पूरे देश को मिलेगा।

(लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं।)
ई–मेल : hblshishir@gmail.com

कृषि पर्यटन : गांवों में पर्यटन का नया आकर्षण

–सुरेंद्र प्रसाद सिंह

कृषि पर्यटन से किसान, ग्रामीण समुदाय और टूर आपरेटरों को लाभ ही लाभ है। किसानों को अपनी खेतीबाड़ी के दायरे को बढ़ाने के साथ व्यावसायिक बनाने की जरूरत होती है; समेकित और आधुनिक खेती करनी होती है; कृषि आय में वृद्धि बनाए रखने के लिए इसमें नए निवेश की जरूरत पड़ती है; स्थानीय कृषि उपज के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ती है; और खेती में प्रबंधकीय कुशलता की जरूरत होती है।

भारत में कृषि और पर्यटन दोनों ऐसे क्षेत्र हैं, जो सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में अभी भी असीम संभावनाएं है, जिसका दोहन करना अभी बाकी है। भारत की बड़ी आबादी गांवों में रहती है, जो कृषि पर निर्भर है। कुछ पीढ़ी पहले गांवों से शहरों में पहुंच गए लोग अपनी जड़ों की याद बनाए रखना चाहते हैं। पूर्णतः शहरी हो चुके लोग अपने बाल–बच्चों, नाती–पोतों को गांव को नजदीक से दिखाना चाहते हैं। विदेशी सैलानियों की रूचि भी भारत के गांवों का जीवन और कृषि पर निर्भर लोगों को जानने व समझने में अधिक है। इसी के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि क्षेत्र में पर्यटन एक नई संभावना के रूप में उभरा है।

कृषि पर्यटन में ग्रामीण माटी की सोंधी महक और असल भारत को देखने, समझने और जानने का मौका मिलता है, जहां स्थानीय खानपान के साथ खेती से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने में सहूलियत होती है। देश की 70 फीसदी आबादी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। नौ करोड़ से अधिक किसान देश के साढ़े छह लाख गांवों में निवास करते हैं, जहां सालाना 27 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन होता है। इसके अलावा बागवानी उत्पाद, फल–फूल, डेयरी उत्पाद, पशुधन, पॉल्ट्री और मछली उत्पादन शामिल नहीं हैं। सरल व सहज रूप में कहें तो भारत का 'एग्रीकल्चर ही यहां का कल्चर' है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए खेती व उससे जुड़े उद्यमों पर जहां खूब जोर दिया जा रहा है, वहीं अब जरूरत कृषि पर्यटन को आगे बढ़ाने की है। पर्यटन क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार सृजन की क्षमता है तो कृषि पर्यटन जैसे नए क्षेत्र के विकास से दोहरा फायदा हो रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, गरीबी उन्मूलन और सतत मानव संसाधन विकास को बल मिलेगा। यहां आने वाले ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय पर्यटक भारत के गांवों को देखने की इच्छा रखते हैं। लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ऐसा करना फिलहाल पूरी तरह संभव नहीं हो पा रहा है। विदेशी सैलानियों के मुकाबले घरेलू पर्यटकों की संख्या अधिक है, जो गांव और कृषि पर्यटन में ज्यादा रूचि दिखाते हैं।

एग्रो टूरिज्म क्या है?

एग्रो टूरिज्म की शुरुआत यूरोप के इटली में पहली बार हुई, जहां इसे 'एग्रो टूरिज्मो' का नाम दिया गया। इसकी शुरुआत 1980 में हुई। मौजूदा समय में सारी दुनिया में कृषि पर्यटन लोकप्रिय हो चुका है। आस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और एशिया में यह तेजी से फैला। कृषक समुदाय के लिए यह पर्यटन एक तरह की अतिरिक्त आय का साधन बन गया है। पर्यटकों की खेती–किसानी से जुड़ी गतिविधियों की प्राचीन विरासत को मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करना ही एग्रो टूरिज्म है। खेतों से सीधे आपके खाने की मेज तक (फार्म टू डायनिंग टेबल) जो वस्तुएं परोसी जाती हैं, जिसका लुत्फ बड़े शौक से उठाया जाता है। भला उनके बारे में जानने की इच्छा किसे नहीं होती है? इसी इच्छा का दोहन ही एग्रो टूरिज्म को प्रोत्साहित करता है।

एग्रो टूरिज्म का आकर्षण

पर्यटकों व उपभोक्ताओं का रुझान खेती और खाने की वस्तुओं से जुड़ा होता है, जिनका उपभोग वे दैनिक तौर पर करते हैं। उससे भी अधिक ग्रामीण विरासत को देखने और नजदीक से उनके साथ रहने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ी है। फूड सप्लाई के स्रोत यानी खेत और उन वस्तुओं के पैदा होने की खेती की पूरी प्रक्रिया को नजदीक से देखने और जानने की इच्छा से ही एग्रो टूरिज्म को हवा मिली, जो अब फूलने–फलने लगा है।

शहरवासियों का आकर्षण?

छुट्टियों में लोगों का रुझान अब फार्म यानी खेती को देखने की ओर बढ़ा है। शहरी बच्चों को न यह पता है कि दूध कहां से आता है और न ही चने की झाड़ के बारे में पता हो पाता है। मुर्गी का अंडा फैक्ट्री में बनता है या मुर्गी देती है। फलों के बाग में फलों को विभिन्न रूपों में देखना और हाथ से तोड़ने का रोमांच भी बच्चों के साथ शहरी मां–बाप को होता है। पशुओं से दूध निकालने, उससे पनीर व अन्य उत्पाद बनाने की प्रक्रिया से भी पर्यटक लाभान्वित होते हैं।

किसान बनने का लुत्फ

गांव में अस्थायी तौर पर रहकर भी किसानों की जिंदगी को बहुत कुछ समझा जा सकता है। कृषि उत्पादों में जैविक खेती और उसके उत्पाद खरीदकर प्रयोग किए जा सकते हैं। खेतों से ताजा सब्जियां व फल निकालना, घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी, बैलगाड़ी पर बैठना, ईक्का–तांगा पर बैठकर घूमना और ताजा शहद को सीधे पेड़ से चखना, वाइन का अंगूर के बाग में ही बनते हुए मजा लेना, हस्तशिल्प की वस्तुओं को वहां से खरीदने की सुविधा मिलती है। पर्यटक खुद किसान बनकर वहां रहता है, तो उसे उसका शानदार अनुभव मिलता है। खेती के कामों में सहयोग करना और नजदीक से खेती के गुर सीखना भी कृषि पर्यटन को प्रोत्साहित कर रहा है।

किसानों को अतिरिक्त आमदनी

एग्रो टूरिज्म छोटे किसानों और गांव के लोगों की अतिरिक्त आय के साधन के रूप में विकसित हो रहा है। इससे मुश्किलों के दौर में चल रहे किसानों की खेती के साथ अन्य मदों से आमदनी होने लगती है। खेत पर ही उनके उत्पादों की बिक्री और उपभोक्ताओं को ताजा कृषि उत्पाद मिल जाता है। एक ओर जहां लोग कृषि पर्यटन की ओर खिंचने लगे हैं, वहीं किसानों को दोहरा लाभ मिलने लगा है। सरकार का भी पूरा जोर किसानों की आमदनी बढ़ाकर दोगुना करने पर है। कृषि पर्यटन से इसे और बल मिलेगा।

भारत में एग्रो टूरिज्म की शुरुआत

महाराष्ट्र और हरियाणा में कृषि पर्यटन केंद्रों को बढ़ावा

भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 2004 में औपचारिक रूप से हुई। महाराष्ट्र के बारामती टूरिज्म सेंटर में लोगों का आना–जाना बहुत बढ़ गया। सेंटर ने इसे कृषि पर्यटन के तौर पर विकसित किया। महाराष्ट्र के बारामती सेंटर को विशेष पर्यटन के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर में कुछ युवाओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अपील पर इसी क्षेत्र में स्टार्टअप से इसकी शुरुआत की। 15 हेक्टेयर भूमि में इसकी विधिवत शुरुआत बहुत शानदार रही है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में सेब के बागानों में रहने, खाने और सेब तोड़ने, पैकिंग करने और सेब से जुड़ी अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए पर्यटकों की एडवांस बुकिंग की जाती है।

एग्रो टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एटीडीसी) ने वर्ष 2014 तक देश के 218 किसानों और उनके फार्म को इसकी इजाजत दी है। लेकिन ये सभी गांव महाराष्ट्र के ही है। इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने वाला दूसरा राज्य हरियाणा है जहां सरकार ने अपने यहां कई जगहों पर किसानों को एग्रो टूरिज्म की अनुमति दी है। यहां पर्यटकों को रहने की पूरी सुविधा है, ग्रामीण रहन–सहन,

गांव चनाखा : कृषि पर्यटकों का गंतव्य

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में लीक से हटकर कुछ कर गुजरने की मंशा के साथ चार युवाओं ने राजुरा तहसील के चनाखा गांव के पास 15 एकड़ जमीन लेकर वहां विभिन्न प्रकार की फसलों की पैदावार के साथ इसे कृषि पर्यटन के रूप में विकसित करने की शुरुआत कर दी है। सुहास आसेकर, रिंकू, रूपेश शिवांकर और नितिन मुसले ने चनाखा गांव के पास 15 एकड़ जमीन खरीदी। इसमें से 10 एकड़ जमीन वर्ष 2014 में यहां 99 क्विंटल अदरक की पैदावार ली गई। इस वर्ष मिर्ची, बीट, मूली, ज्वारी, चना आदि की बुआई की गई है।

पूरक व्यवसाय भी अपनाया

यहां खेती के साथ पूरक व्यवसाय के रूप में गौशाला, बकरी पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन किया जा रहा है। गाय, बैल, बकरियों के मल–मूत्र का जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यहां पर्यटक के रूप में आने वाले बच्चों के हाथों क्यारियों में बीज बोए जाएंगे। इसके बाद आने वाले दूसरे बच्चों को उन पौधों को दिखाकर बताया जाएगा कि आपके जैसे दूसरे बच्चों ने इसका बीजारोपण किया था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि प्रधान भारत देश के बच्चों को मिट्टी से जोड़ना है। इसे चरणबद्ध रूप से विकसित किया जा रहा है। पर्यटकों का भोजन बनाने के लिए चनाखा गांव के बचत समूह को काम दिया गया है। इस माध्यम से 8–9 महिलाओं को रोजगार मिला है। पर्यटक स्थल विकसित हो जाने के बाद 30–35 बेरोजगारों को स्थायी रोजगार मिल सकेगा। आने वाले पर्यटकों का विशेष वाद्य बजाकर स्वागत किया जाता है। भारतीय बैठक पद्धति तरीके से भोजन परोसा जाता है। पर्यटकों के भ्रमण के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था है।

बुनियादी ढांचे का समुचित विकास करना होगा। सरकार की ओर से इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। फार्म के भीतर खुद कुछ घंटे काम करने, होते हुए काम को देखने और सीखने का मौका दिया जाता है। मुर्गी के अंडे एकत्रित करना, पशुओं को चारा खिलाने का मौका दिया जाता है। फार्म हाउस के भीतर उनके काम करने के घंटे के हिसाब से उनके वहां ठहरने, नाश्ता व खाना आदि के खर्च में रियायत दी जाती है। फार्म में रहने के लिए केबिन, कॉटेज, खलिहान, मचान, खटिया, मचिया, मोढ़ा और चौकी पर धूप या छाया में नींद का आनंद उठाया जा सकता है।

खान–पान की सुविधा

राज्य व क्षेत्र के हिसाब से गंवई अंदाज से खाना परोसा जाता है। बागों से ताजा

जीवनशैली, संस्कृति व सामाजिक सरोकार जैसी चीजें मौजूद हैं। दिल्ली से नजदीक स्थित हर्बल बगीचे में हर तरह की जड़ी–बूटी के पेड़ व लताएं हैं। आयुर्वेद का रत्न कहे जाने वाले आंवला, हर्रे और बहेर्रा की खेती देखी जा सकती है। यहां भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, घोड़े, मुर्गी, बत्तख, भैंस और शोर मचाती छोटी–छोटी पक्षियों का कलरव से दो–चार हुआ जा सकता है। गाय के गले में बंधी घंटियां किसी को भी लुभाने के लिए काफी हैं। बरगद और पीपल के पुराने भारी–भरकम पेड़ों की छाया में सरकती ठंडी हवाएं हर किसी को यहां आने को बाध्य करती हैं। पर्यटकों को खेतों की जुताई, बीजों की बुवाई, पेड़ लगाने, फूल और फलों के पेड़ों को अपने सामने देखा जा सकता है।

गांव की सीधी सादी–जिंदगी में कठोर मेहनत का भी नजारा देखने को मिलता है। कुम्हार की चाक पर मिट्टी के चिकने बर्तन और सुंदर चीजें आकार लेते देखा जा सकता है। यहां पर्यटक खुद भी हाथ आजमा सकते हैं। बच्चे गुल्ली–डंडा, कंचा, गुलेल चलाकर गंवई खेलों से परिचित हो सकते हैं। लेकिन इन जगहों पर शहरों के इनडोर व आउटडोर किसी भी खेल की इजाजत नहीं होती है।

गांव के नाई से सिर मालिश करा सकते हैं। वास्तविक व खेत की सोंधी मिट्टी के कीचड़ में लिपट कर उसे धूप में सुखा सकते है। नहाने के लिए गांव के ट्यूबवैल की टंकी में कूद–कूद कर नहाने का आनंद लिया जा सकता है। हरियाणा के प्रतापगढ़ गांव को पूरी तरह से फार्म टूरिज्म के लिए अधिकृत किया गया है। वहां पर्यटकों के रहने, खान–पान आदि की पूरी व्यवस्था है। हाथ से बनी और चूल्हे की आग में सेंकी हुई मोटी रोटी और चटनी खाने का सुख तो गांव में ही मिल सकता है।

ठहरने की सुविधा

खेतों में ठहरने की सहूलियतें दी जाती हैं। लेकिन इसके लिए

फसल और खेतों से ताजा सब्जियां निकाल कर सामने ही पकाई जाती हैं। पर्यटकों को खेत से सब्जियां चुनने और पेड़ों से फल तोड़कर खाने का असीम आनंद मिलता है। ताजा मट्ठा, गाय व भैंस से निकला ताजा दूध गरम कर पीने को दिया जाता है। भैंस, गाय और बकरी के थन से दूध निकालने की भी सुविधा मुहैया कराई जाती है। उनसे तैयार परंपरागत गांव की मिठाइयां भी दी जाती हैं।

कृषि पर्यटन से किसान, ग्रामीण समुदाय और टूर आपरेटरों को लाभ ही लाभ है। किसानों को अपनी खेतीबाड़ी के दायरे को बढ़ाने के साथ व्यावसायिक बनाने की जरूरत होती है। समेकित और आधुनिक खेती करनी होती है। कृषि आय में वृद्धि बनाए रखने के लिए इसमें नए निवेश की जरूरत पड़ती है। स्थानीय कृषि उपज के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ती है। खेतों पर खेती की अन्य गतिविधियां बढ़ाने से लाभ होता है। खेती में प्रबंधकीय कुशलता की जरूरत होती है।

ग्रामीण समुदाय को इससे बहुत फायदा होता है। उसे पर्यटन के विभिन्न मदों से आर्थिक लाभ होता है। स्थानीय कारोबारी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। पर्यटकों को खेती के साथ उससे जुड़े विभिन्न उद्यमों में रूचि होती है। स्थानीय कला, संस्कृति व हस्तशिल्प की मांग बढ़ती है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है।

टूरिज्म आपरेटरों के लिए यह नए और आकर्षित क्षेत्र के रूप में उभरा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों की रूचि ने आपरेटरों को एक नया अवसर प्रदान किया है। पर्यटन के हिसाब से ऑफ सीजन में कृषि पर्यटन में खूब संभावनाएं हैं, जिसका लाभ आपरेटर उठा सकते हैं।

(लेखक दैनिक जागरण के नेशनल ब्यूरो में डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं। कृषि, खाद्य व ग्रामीण विकास जैसे विषयों के विशेषज्ञ हैं।)
ई–मेल : Surendra64@gmail.com

CHANAKYA IAS ACADEMY®

Also known as Chanakya Civil Services Academy

24 Years of Excellence, Extraordinary Results every year, 3000+ selections in IAS, IFS, IPS and other Civil Services so far...

CHANAKYA IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

A Unit of CHANAKYA ACADEMY FOR EDUCATION AND TRAINING PVT. LTD.

under the direction of Success Guru AK Mishra

IAS 2018

Upgraded Foundation Course™

A Complete solution for Prelims, Mains & Interview

- Special modules on administrative traits by Success Guru AK Mishra & retired civil servants
- Intensive Classes with online support
- Offline/ Online test series for Prelims & Mains
- Pattern proof teaching
- Experienced faculty
- Hostel assistance
- Regular class test

Separate classes in Hindi & English medium

Batches Starting From

10th November, 10th December-2017

Weekend Batches & Postal Guidance Also Available

To Reserve your seat - Call: 1800-274-5005 (Toll Free)

www.chanakyaiasacademy.com | enquiry@chanakyaiasacademy.com

HO/ South Delhi Branch: 124, 2nd Floor, Satya Niketan, Opp. Venkateswara College, Near Dhaula Kuan, Delhi-21, Ph: 011-64504615, 9971989980/ 81

North Delhi Branch: 1596, Outram Line, Kingsway Camp, Delhi-09, Ph: 011-27607721, 9811671844/ 45

Our Branches

Allahabad: 10B/1, Data Tower 1st Floor, Tashkand, Patrika Chauraha, Allahabad-211001, Ph: 9721352333
Ahmedabad: 301, Sachet III, 3rd Floor, Mirambika School Road, Naranpura, Ahmedabad-380013, Ph: 7574824916, 7574824919
Bhubaneswar: Saffire Tower, 2nd & 3rd Floor, Opposite Crown Hotel, Plot No: N-6/454, IRC Village, Jayadev Vihar, Nayapalli, Bhubaneshwar-15, Ph: 9078878233
Chandigarh: S.C.O 45 - 48, Sector 8 C, Madhya Marg, Chandigarh-160009, Ph: 8288005466
Dhanbad: Univista Tower, Near Big Bazaar, Saraidhela, Dhanbad-828127, Ph: 9771463546
Faridabad: G-Block, Manav Rachna International University, Delhi Suraj Kund Road, Sector 43, Faridabad-04, Ph: 8860403403, 8527301209
Guwahati: Building No. 101, Maniram Dewan Road, Silpukhuri, Near SBI evening branch, Kamrup, Assam - 781003, Ph: 8811092481
Hazaribagh: 3rd Floor, Kaushaliya Plaza, Near Old Bus Stand, Hazaribagh (Jharkhand)-825301, Ph: 9771869233
Indore: 120, 1st Floor, Veda Business Park, Bhawarkuan Square, AB road, Indore-462001, Ph: 8818896686
Jammu: 47 C/C, Opposite Mini Market, Green Belt, Gandi Nagar, Jammu-180001, Ph: 8715823063
Jaipur: Felicity Tower, 1st Floor, Plot no- 1, Above Harley Davidson Showroom, Sahakar Marg, Jaipur-30201, Ph: 9680423137
Kochi: ICMS International, Masjid Road, Opp. KIMS Hospital, Pathadipalam, Edappally, Kerala-682021, Ph: 7561829999, 7356654999
Mangaluru: 3rd Floor, Amruthothsava Building, Bunts Alias Nadavara Mathr Sangha(R), Bunts Hostel Circle, Mangaluru-575003, Ph: 0824-2493701
Patna: 304, 3rd Floor, above Reliance Trends, Navyug Kamla Business park, East Boring Canal Road, Patna, Bihar-800001, Ph: 8252248158
Pune: Millennium Tower, 4th Floor, Bhandarkar Road, Opp. Kotak Mahindra Bank, Deccan Gymkhana, Pune-411004, Ph: 9067975862, 9067914157
Ranchi: 1st Floor, Sunrise Form, Near Debuka Nursing Home, Burdhwan Compound, Lalpur, Ranchi-834001, Ph: 9204950999, 9771463546
Rohtak: DS Plaza, Opp. Inderprasth Colony, Sonipat Road, Rohtak- 124001, Ph: 8930018881
Srinagar: University of Kashmir, Hazratbal, Srinagar-190006, Kashmir, Ph: 9599224341

CAUTION NOTICE

Students/ aspirants are hereby cautioned that some unaffiliated entities have been using trademarks/ tradenames which are identical/ deceptively similar to trademarks/ tradenames of Chanakya IAS Academy/ Chanakya Academy (promoted under the direction of SuccessGuru AK Mishra since 1993). We hereby declare that these entities have no affiliation with us and legal actions have already been initiated against such entities. All students must verify authenticity of the academy/ study centre/ institute before enrolling and are requested to inform us of any such functioning under an identical/ deceptively similar trademarks/tradenames by calling on 09650299662/3/4 or sending email at info@chanakyaacademygroup.com.

पूर्वोत्तर में समुदाय-आधारित ईको पर्यटन

–डॉ. प्रदीप कुमार मुखर्जी

ईको पर्यटन को आजकल सभी मर्जों की दवा के रूप में देखा जा रहा है। इसका कारण यह है कि इससे भारी मात्रा में पर्यटन राजस्व मिलता है और पर्यावरण एवं संसाधनों का दोहन नहीं किया जाता। हालांकि एक संकल्पना के रूप में ईको पर्यटन की महत्ता को भारत में हाल ही में पहचाना गया है, लेकिन एक जीवन पद्धति के रूप में भारतीय सदियों से इस संकल्पना पर अमल करते रहे हैं।

भारत में प्राचीनकाल से ही लोग शैक्षिक एवं धार्मिक उद्देश्यों से देश भ्रमण के लिए निकलते थे। इसे देशाटन का नाम दिया जाता था। लेकिन, अब यह पर्यटन का रूप ले चुका है। मोटे तौर पर, पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्यों से की जाती है।

भारतीय प्राचीन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मानव के विकास, सुख और शांति तथा उसकी संतुष्टि एवं ज्ञान के लिए पर्यटन को अति आवश्यक माना गया है। हमारे देश के ऋषि–मुनियों ने भी पर्यटन को बहुत महत्व दिया है। पाश्चात्य विद्वान संत आगस्टिन ने तो यहां तक कह दिया था कि बिना विश्व दर्शन ज्ञान ही अपूर्ण है। पंचतंत्र नामक भारतीय साहित्य दर्शन में भी देश–देशांतर के भ्रमण के महत्व को स्वीकारा गया है।

पर्यटन में देश भ्रमण करने वालों यानी पर्यटकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्राचीन से लेकर वर्तमान काल में इसे परिलक्षित किया जा सकता है। सम्राट अशोक ने भी पथिकों के आश्रय की व्यवस्था की थी। बाद में समुद्रगुप्त के काल में और उसके बाद शेरशाह सूरी के काल में भी यात्री सुविधाओं का समुचित ध्यान रखा गया था।

पिछले कुछ दशकों से पर्यटन का लगातार विकास हुआ है और आधुनिक युग में मानव कार्यकलापों में पर्यटन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। पर्यटन आज सबसे बड़ा उद्योग है जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर बहुत तेजी से विकसित और पल्लवित–पुष्पित हो रहा है और एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत में पर्यटन सबसे बड़ा सेवा उद्योग है जहां इसका राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.23 प्रतिशत और देश के कुल रोजगार में 8.78 प्रतिशत योगदान है।

आइए, देखें पर्यटन को लेकर भारत में क्या–क्या मुख्य प्रयास हुए।

पर्यटन को लेकर भारत में हुए प्रयास

आधुनिक काल में, भारत में पर्यटन को लेकर पहला वास्तविक प्रयास सन् 1945 में हुआ जब तत्कालीन शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता में पर्यटन विकास के लिए समिति बनाई गई। लेकिन, भारत में पर्यटन का वास्तविक विकास सन् 1980 के दशक से आरंभ हुआ। पर्यटन को लेकर राष्ट्रीय पर्यटन नीति की घोषणा सन् 1982 में हुई। पर्यटन के क्षेत्र में सतत विकास के लिए व्यापार योजना बनाने के लिए सन् 1988 में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। सन् 1989 में पर्यटन निगम की स्थापना की गई ताकि पर्यटन संबंधी कार्यों को वित्तीय सहायता मुहैया की जा सके।

पर्यटन के संवर्धन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति सन् 1996 में तैयार की गई थी। नई पर्यटन नीति सन् 1997 में आई जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी उपक्रमों की भूमिका तय की गई। साथ ही, पंचायती–राज संस्थानों, स्थानीय संस्थानों, गैर–सरकारी संस्थाओं एवं स्थानीय युवाओं की सहभागिता को आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया गया।

सामान्यतया पर्यटन ऐतिहासिक महत्व की इमारतों एवं स्मारकों, सुरम्य पर्वतीय स्थलों तथा प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त रमणिक स्थलों की यात्रा से जुड़ा होता है। किसी पर्यटक स्थल की जैवविविधता पर्यटकों को आकर्षित करती है और वे जीवों एवं प्रकृति के सौंदर्य प्रेम के कारण दूरदराज की यात्रा करते हैं।

लेकिन, पर्यटन की क्रियाओं द्वारा स्थान विशेष की पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) एवं पर्यावरण पर कुछ न कुछ हानिकारक प्रभाव अवश्य पड़ता है। जैसेकि कई विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों से यात्राएं आयोजित की जाती है। अध्ययन के लिए कुछ पौधे उखाड़े जाते हैं तथा अनजाने ही कुछ छोटे मगर महत्वपूर्ण पौधे पैरों तले कुचले जाते हैं इससे जैवविविधता को नुकसान पहुंचता है। इसी प्रकार ऐतिहासिक महत्व की इमारतों, स्मारकों या राष्ट्रीय धरोहरों को उन पर लिखकर तथा चित्र आदि बनाकर उनके स्वरूप को बिगाड़ा जाता है। इसके अलावा, नदियों अथवा समुद्र के किनारे अवस्थित पर्यटक सुविधाओं से निकलने वाला संदूषित मल–जल जल स्रोतों को प्रदूषित करता है जिसका सीधा प्रभाव जलीय जीवों, तटीय क्षेत्रों तथा उन जल स्रोतों के आसपास निवास करने वालों पर पड़ता है। पर्यटक स्थलों पर कचरे, खासकर प्लास्टिक कचरे, एवं अपशिष्ट का निपटान भी बहुत बड़ी समस्या है। कई स्थानों, खासकर पर्वतीय स्थलों, पर यह समस्या इतनी गंभीर है कि उन स्थानों का स्वरूप ही बिगड़ गया है। पर्यटकों द्वारा वन्य प्राणी उद्योगों में वन्य जीवों का अवलोकन उनके दैनिक कार्यकलापों, विशेषकर उनके मुक्त–स्वाभाविक व्यवहार एवं प्रजनन–चक्र में बाधा पहुंचाता है।

इस प्रकार पर्यटक, पर्यटन स्थलों को जाने–अनजाने कई प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें पर्यटन स्थलों की पारिस्थितिकी एवं वहां के पर्यावरण की क्षति भी शामिल है। स्थानीय समुदायों, खासकर जनजातियों की सांस्कृतिक–सामाजिक धरोहरों एवं विशेषताओं से छेड़छाड़ का खतरा भी सार्वजनिक पर्यटन में रचा–बसा होता है। प्रकृति का दोहन एवं स्थानीय समुदायों की संस्कृति एवं अस्मिता से छेड़छाड़ सार्वजनिक पर्यटन का अघोषित लक्ष्य हो सकता है।

असल में, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी–तंत्र एवं पर्यटन एक–दूसरे के पूरक होने चाहिए तभी धारणीय यानी सतत पर्यटन एवं विकास की संकल्पना सार्थक हो सकती है। स्पष्ट है कि प्रकृति, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का संरक्षण पर्यटन के विकास के लिए आवश्यक है। पर्यटक ऐतिहासिक इमारतों एवं स्मारकों तथा आम पर्यटक स्थलों की ओर तभी आकर्षित होंगे जब वहां की शुचिता, स्वच्छता एवं प्राकृतिक सौंदर्य अपने मूल रूप में बना रहेगा। इसके मद्देनजर सार्वजनिक पर्यटन से दीगर अब एक नई संकल्पना सामने आई है जिसे पारिस्थितिकी पर्यटन यानी ईकोटूरिज्म की संज्ञा दी गई है। इसमें स्थानीय समुदायों या जनजातियों के कल्याण एवं हितों का भी ध्यान रखने के लिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इससे समुदाय–आधारित पारिस्थितिकी पर्यटन (कम्युनिटी–बेस्ड ईकोटूरिज्म) की नई अवधारणा भी सामने आई है।

इस पर विराद विवेचन से पहले, आइए पारिस्थितिकी पर्यटन यानी ईकोटूरिज्म पर थोड़े विस्तार से चर्चा करते हैं।

परिस्थितिकी बनाय ईको पर्यटन एवं इसके निहितार्थ

ईको पर्यटन अब पूरे विश्व में एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। कई राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में इसका अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है जिसका उपयोग प्रकृति एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के साथ–साथ राष्ट्र के विकास में भी किया जा सकता है। यानी ईको पर्यटन परोक्ष रूप से राष्ट्रीय विकास के साथ भी जुड़ा है।

दरअसल, समूचे विकासशील उष्ण–कटिबंधीय क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्र प्रबंधकों तथा स्थानीय समुदायों के आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ईको पर्यटन इस संतुलन का एक महती पक्ष है। सुनियोजित ईको पर्यटन से संबंधित क्षेत्रों और उसके आसपास रहने वाले समुदायों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए दीर्घकालिक जैव–विविधता संरक्षण के उपायों तथा स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक विकास के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा।

सामान्य शब्दों में, ईको पर्यटन का अर्थ है पर्यटन और प्रकृति, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का प्रबंधन इस ढंग से करना कि एक तरफ पर्यटन और पारिस्थितिकीय आवश्यकताएं पूरी हों और दूसरी तरफ स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार, नए कौशल, आय एवं उनके बेहतर स्तर और आसान जीवन को सुनिश्चित किया जा सके; साथ ही स्थानीय समुदायों या जनजातियों के प्राकृतिक संसाधनों तथा उनके सांस्कृतिक–सामाजिक धरोहरों एवं परंपरागत मूल्यों एवं जीवनशैली का संरक्षण किया जा सके।

ईको पर्यटन को प्रकृति–आधारित पर्यटन (नेचर बेस्ड टूरिज्म), धारणीय या सतत पर्यटन (सस्टेनेबल टूरिज्म), हरित पर्यटन (ग्रीन टूरिज्म), दायित्वपूर्ण पर्यटन (रेस्पॉसिबल टूरिज्म) तथा सॉफ्ट टूरिज्म आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता हे। हालांकि इन विभिन्न प्रकार के पर्यटनों में कुछ बातें समान हैं, लेकिन फिर भी इनमें भिन्नता है।

ईको पर्यटन शब्द को देने का श्रेय मैक्सिको सिटी के हेक्टर सैबालस–लेस्कुरेन को जाता है जिन्होंने सन् 1983 में पहले–पहले इस शब्द को गढ़ा था। उन्होंने ईको पर्यटन को इस प्रकार परिभाषित किया था– 'अध्ययन, प्राकृतिक दृश्यों, वन्य पौधों एवं जीव–जंतुओं तथा इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली सांस्कृतिक संपदाओं को सराहने और आनंद उठाने के विशिष्ट उद्देश्यों से अपेक्षाकृत अछूते एवं असंदूषित क्षेत्रों की यात्रा करने को ही इको पर्यटन कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार, प्राकृतिक दृश्यों को देखने और उनकी सराहना करने तक ही ईको पर्यटन सीमित नहीं है बल्कि प्राकृतिक आकर्षणयुक्त क्षेत्रों के वैज्ञानिक एवं पारिस्थितिकी लक्षणों के बारे में पर्यटकों की समझ को बढ़ाना भी इसके अंतर्गत आता है।

अतः ईको पर्यटन के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु समाहित हैंः

- प्रकृति के नैसर्गिक मूल्यों को पहचानना तथा यह स्वीकारना

कि राष्ट्रीय उद्यानों का मूल उद्देश्य पौधों, जीव–जंतुओं एवं भू–क्षेत्रों का संरक्षण है।

- पारिस्थितिकी एवं सांस्कृतिक रूप से यात्रा एवं पर्यटन को बढ़ावा देना एवं उसका विकास करना।
- पर्यटन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों में किए जाने वाले निवेश के संरक्षण को बढ़ावा देना एवं उसे प्रोत्साहित करना।
- ईको पर्यटन के लिए आचार संहिता एवं मानकों का विकास करना।
- पर्यटकों को जागरूक बनाना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना ताकि अपनी भागीदारी से वे प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संपदाओं का समादर कर सकें।

दूसरे शब्दों में, ईको पर्यटन प्राकृतिक क्षेत्रों की पारिस्थितिकीय रूप से धारणीय यात्रा है जो पर्यटकों में पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक समझ, समादर एवं संरक्षण की भावना उत्पन्न करता है।

तीन पहलुओं को रेखांकित किया गया है– प्रकृति, पर्यटन और स्थानीय समुदाय। प्रकृति, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ सांस्कृतिक विविधता संरक्षण ईको पर्यटन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस प्रकार ईको पर्यटन निम्नलिखित तीन बुनियादी लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है:

- संरक्षण क्षेत्र प्रबंधन प्रणालियां (सार्वजनिक एवं निजी) अनुकूल बनाकर तथा सुदृढ़ पारिस्थितिकी प्रणालियों का योगदान बढ़ाकर जैव–विविधता और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण
- ईको पर्यटन और संबद्ध व्यापार नेटवर्क से आमदनी, रोजगार और व्यापार के अवसर उत्पन्न करके जैव–विविधता के स्थली इस्तेमाल को प्रोत्साहन, और
- स्थानीय समुदायों और जनजातीय लोगों को पर्यावरण पर्यटक गतिविधियों के लाभ में समान रूप से भागीदार बनाना और इसके लिए ईको पर्यटन व्यापार की आयोजनों और प्रबंधन में उनकी पूर्ण सहमति एवं भागीदारी प्राप्त करना।

पर्यावरण–अनुकूल गतिविधि होने के कारण ईको पर्यटन का लक्ष्य पर्यावरण मूल्यों और शिष्टाचार को प्रोत्साहित करना तथा निर्बाध रूप से प्रकृति का संरक्षण करना हे। इस प्रकार, पारिस्थितिकी विषयक अखंडता में योगदान देकर ईको पर्यटन वन्य जीवों, प्रकृति और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाता है। स्थानीय लोगों की इसमें भागीदारी उनके लिए आर्थिक लाभ सुनिश्चित करती है जो आगे चलकर उन्हें बेहतर स्तर और आसान जीवन उपलब्ध कराती है।

आइए, अब ईको पर्यटन के कुछ आधारभूत लाभों की चर्चा करते हैं।

ईको पर्यटन के लाभ

आर्थिक लाभ

ईको पर्यटन से सीधा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है जिसका उपयोग जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र (परितंत्र) के संवर्द्धन एवं संरक्षण के लिए किया जा सकता है। प्रत्यक्ष लाभ के रूप में सरकार को विदेशी मुद्रा की आमदनी होती है। परोक्ष लाभ में विभिन्न प्रकार के करो एवं शुल्कों के द्वारा भी आमदनी होती है। इस प्रकार ईको पर्यटन न केवल पर्यावरण के संवर्द्धन एवं संरक्षण में योगदान देता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी सीधा योगदान देता हैं।

पर्यावरणीय चेतना का विकास

ईको पर्यटन के द्वारा लोगों में पर्यावरणीय चेतना का विकास किया जा सकता है क्योंकि इसके द्वारा आम जन एवं पर्यावरण को साथ लाने का प्रयास हो सकता है। इससे लोगों में पर्यावरण से होने वाले लाभों की जानकारी होगी एवं वे और भी बेहतर ढंग से संरक्षण कार्यों में अपना सहयोग दे पाएंगे।

पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण

प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण एक अति महत्वपूर्ण कार्य होगा क्योंकि इससे इनके अमूल्य होने की वास्तविकता सामने आएगी और इस प्रकार संरक्षण के प्रयास और ज्यादा तेज होंगे। साथ ही इससे जन–भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

स्पष्ट है कि ईको पर्यटन में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अलावा स्थानीय समुदाय की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी से ही समुदाय–आधारित ईको पर्यटन की संकल्पना उभर कर आई है। सरकार और निजी क्षेत्र द्वार ईको पर्यटन तथा समुदाय–आधारित ईको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ईको पर्यटन विकास नीति घोषित की है जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी

को बता दिया गया है। इसी प्रकार कर्नाटक, सिक्किम, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के वन एवं पर्यटन विभागों ने अधिकारी मनोनीत किए हैं जो इन गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। केरल द्वारा स्थापित तेन्माला ईको टूरिज्म सोसाइटी ईको पर्यटन का एक मॉडल तैयार करेगी। निजी क्षेत्र में भी पर्यावरण–अनुकूल सैरगाहों और होटलों की धारणा जोर पकड़ रही है।

अब पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में समुदाय–आधारित ईको पर्यटन की चर्चा पर हम आते हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में समुदाय–आधारित ईको पर्यटन

प्रकृति का अद्‌भुत सौंदर्य और जनजातीय संस्कृति एवं सभ्यता की धरोहरों को अगर आप मूल रूप में देखना चाहते हैं तो आपको भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सैर को निकलना होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 'सेवन सिस्टर्स' कहलाने वाले सात राज्यों के साथ फूलों के प्रदेश सिक्किम को भी जोड़ा जाता है। इस प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों की कुल संख्या आठ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले सात राज्य हैं– असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सूर्योदय का प्रदेश अरुणाचल, सुहानी जलवायु के लिए प्रसिद्ध मिजोरम, मेघों का घर कहलाने वाला मेघालय तथा अनूठी संस्कृति का धनी नगालैंड। वैसे तो इन सभी पूर्वोत्तर राज्यों की अपनी–अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं सभ्यता है, लेकिन मेघालय के बारे में खास बात यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह राज्य तेजी से विकास कर रहा है।

कुल 2,65,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला आठ राज्यों वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र तरह–तरह के जीव–जंतुओं और पेड़–पौधों के अलावा लोक संस्कृति तथा कलाओं से भरपूर है। सौ से अधिक जनजातियों एवं उपजातियों का निवास इस क्षेत्र में है।

पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी संस्कृति के रूप में परंपरागत त्योहारों, नृत्यों एवं लोककलाओं का अद्‌भुत संगम देखने को मिलता है। यहां अनेक प्राचीन प्रासाद एवं मंदिर भी हैं। बौद्ध संस्कृति के परिचायक बौद्ध मठ भी यहां बहुतायत में देखने को मिलते हैं। परंपरागत शिल्प यानी दस्तकारी व कारीगरी का अनूठा कौशल भी इन राज्यों में दृष्टिगोचर होता है। इन राज्यों में अनेक संग्रहालय तथा ग्राम संस्कृति केंद्र (विलेज कल्चर सेंटर) भी हैं। पिछले कुछ वर्षों से इन राज्यों में पारिस्थितिकी ग्रामों यानी ईको विलेजेस की अवधारणा भी जोर पकड़ती जा रही है।

इस प्रकार अपने अछूते सौंदर्य तथा जैव–विविधता एवं सांस्कृतिक विविधतायुक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र देशी एवं विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा है। भारत सरकार भी यहां पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। सरकारी कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र की सैर के लिए हवाई यात्रा की विशेष सुविधा सरकार ने प्रदान की है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में समुदाय–आधारित ईको पर्यटन का चलन भी हाल ही में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस क्षेत्र के लिए फिलहाल एक नई संकल्पना है लेकिन स्थानीय एवं जनजातीय लोगों में अपने–अपने राज्यों की जैवविविधता एवं सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण की भावना बलवती होती जा रही है। तभी अपने गांवों एवं पवित्र समझे जाने वाले वनों (सैक्रेड फॉरेस्ट) के संरक्षण में ये लोग विशेष रुचि ले रहे हैं। खासकर मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं असम में कुछ आदिवासी गांवों का विकास किया गया है। इन गांवों में उनकी परंपरागत संस्कृति व शिल्प, खानपान और रहन–सहन तथा आवास के विभिन्न प्रकारों को प्रदर्शित किया जाता है ताकि पर्यटक इनकी तरफ आकर्षित हों तथा यहां रहकर उनकी परंपरागत संस्कृति एवं सभ्यता से परिचित हो सकें। इस प्रकार ईको पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ–साथ इससे समुदायों की दायित्वपूर्ण भागीदारी भी सुनिश्चित होती है जो समुदाय–आधारित ईको पर्यटन की सफलता के लिए आवश्यक हैं।

नगालैंड में ऐसे ही कुछ ईको–परिसर हैं जिनमें किसामा विलेज' तथा 'ट्योप्लेमा टूरिस्ट विलेज' का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इसी प्रकार मेघालय जो अपनी पहाड़ियों, झरनों तथा विश्व के सर्वाधिक वर्षापात वाले राज्य के रूप में प्रसिद्ध है, के दक्षिणी पठार (चेरापूंजी के पास) के अंचलों, जैसेकि मॉलिमॉन्ग तथा लैटकिन्सन में भी ऐसे ही ईको या पर्यटक गांवों का विकास किया गया है। इन गांवों का एक विशेष, आकर्षण है पौधों की जीवित जड़ों से बना पुल, जिसे 'डबल डैकर' या लिविंग रूट ब्रिज' भी कहते हैं। इस ब्रिज का निर्माण रबड़ प्रजाति के फाइटा इलास्टिका नामक कुछ विशेष पौधों, जो मेघालय में पाए जाते हैं, की जीवित जड़ों से हुआ है। इस पुल को पिछले सौ से भी अधिक वर्षों से संरक्षित रखा गया है। यह पुल समय के साथ और मजबूत होता जा रहा है; इसकी मरम्मत की आवश्यकता कम ही पड़ती है। यहां यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस परंपरागत प्राचीन 'रूट ब्रिज' के अलावा मेघालय के विकास के लिए नए पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है। बिल्डर्स अब स्टील रोप एवं आधुनिक टेक्नोलॉजी से मेघालय की जलधाराओं एवं नदियों के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं।

जहां मेघालय अपने रूट ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है वही मणिपुर अपनी विशिष्ट लोकटक झील के लिए प्रसिद्ध है। यह विशेष झील, जो लगभग 300 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है, इम्फाल से

लोकटक झील, मणिपुर

करीब 53 किलोमीटर दूर विशुपुर जिले में स्थित है। अपनी तैरती प्रकृति के कारण इसे 'फ्लोटिंग लेक' भी कहते हैं। यह झील पुनः बिजली (हाइड्रो पावर) के उत्पादन, सिंचाई तथा आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति तथा मछुआरों के लिए आमदनी का स्रोत है। लोकटक झील जैवविविधता की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। यह जलीय पक्षियों एवं जीव–जंतुओं के लिए विशेष आश्रय प्रदान करती है। यहीं मणिपुरी संगाई हिरण का भी निवास है।

दो राय नहीं कि जैव–विविधता एवं सांस्कृति विविधता से ओत–प्रोत पूर्वोत्तर राज्यों में समुदाय–आधारित ईको पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। लेकिन, स्थानीय एवं जनजातीय लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उनमें जागरूकता उत्पन्न किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही पर्यटन से प्राप्त आर्थिक लाभों को उन तक पहुंचाया जाना भी आवश्यक है ताकि उनके जीवन–स्तर में सुधार हो और वे खुशहाली की जिंदगी जिएं फिलहाल इस दिशा में व्यावहारिक एवं कार्यकारी योजना की बेहद कमी है। लेकिन ग्रामवासियों एवं ग्राम मुखियाओं द्वारा इस दिशा में कुछ कदम अवश्य उठाए जा रहे हैं। लोगों में अपनी सांस्कृति विरासत एवं राज्य के पर्यावरण को संरक्षित किए जाने की रूचि दिखाई पड़ रही है, जो समुदाय–आधारित ईको पर्यटन के विकास के लिए एक स्वागत योग्य कदम है।

समुदाय–आधारित ईको पर्यटन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर अमल किया जाना अत्यावश्यक है:

- स्थानीय समुदाय को शामिल करना ताकि क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास हो सके;
- ईको पर्यटन के लिए संसाधनों का उपयोग और स्थानीय समुदाय के मध्य संभावित संघर्ष की पहचान करना तथा इस संघर्ष को खत्म या न्यूनतम करना;
- ईको पर्यटन के विकास के प्रकार एवं पैमानों को पर्यावरण एवं स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक–सामाजिक विशेषताओं के अनुरूप करना;
- ईको पर्यटन का नियोजन समग्र क्षेत्र विकास नीति के रूप में करना।

सही कार्ययोजना के साथ समुदाय–आधारित ईको पर्यटन कुछ अन्य आमदनी विकल्पों के साथ स्थानीय समुदायों के आर्थिक विकास का व्यवहार्य विकल्प बन सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि परंपरागत कलाओं, हस्तशिल्पों, नृत्य, संगीत, नाटक, खान–पान, रहन–सहन, रीति–रिवाज और उत्सवों का संरक्षण तथा परंपरागत जीवनशैली के कुछ पहलू सीधे समुदाय–आधारित ईको पर्यटन से जोड़े जा सकते हैं।

हालांकि भारत सरकार को समुदाय–आधारित ईको पर्यटन के विकास की दिशा में अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय ने कंपनी कानून 2013 की धारा 8 के अंतर्गत नार्थ ईस्ट डेवलपमेंट कौंसिल का गठन किया है ताकि सरकारी क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्र को भी समुदाय–आधारित ईको पर्यटन के विकास कार्य से जोड़ा जा सके।

समुदाय–आधारित ईको पर्यटन के विकास में फिलहाल कुछ समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं। इनमें एक बड़ी समस्या समुदाय–आधारित पर्यटक क्षेत्र को सही ढंग से परिभाषित करने से जुड़ी है। इसके साथ ही स्थानीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर पर्यटकों द्वारा पड़ने वाले नकारात्मक अधिप्रभावों के प्रबंधन से जुड़े सरोकार भी हैं। स्थानीय समुदायों को योजना प्रक्रिया के साथ उनकी सहमति के साथ जोड़ना ताकि पर्यटन कार्यकलापों से प्राप्त आर्थिक लाभ उन तक पहुंचाए जा सकें, भी अपने आप में एक गंभीर समस्या है। फिलहाल पर्यटन से संबंद्ध विकास परियोजनाओं में सामुदायिक सहमति प्राप्त करने के तरीकों का घोर अभाव दिखता है, साथ ही इस दिशा में बुनियादी ढांचे का अभाव भी है।

समुदाय–आधारित ईको पर्यटन में भारत सरकार द्वारा कुछ बुनियादी कदम उठाए जाने की महती आवश्यकता है। एक तो यह कि पूर्वोत्तर राज्यों के पारिस्थितिकी–तंत्र का सही आकलन किया जाना चाहिए ताकि इसकी वहनीय क्षमता का सही लेखा–जोखा प्राप्त हो सके। इससे पर्यटकों द्वारा इन राज्यों के प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं मानव संसाधनों के अति दोहन पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। साथ ही सरकार को चाहिए कि स्थानीय समुदायों को सही ढंग से प्रशिक्षित करके उनकी मदद करे ताकि समुदाय–आधारित ईको पर्यटन में उनकी भागीदारी एवं सहमति सुनिश्चित की जा सके। इन राज्यों के रीति–रिवाजों, परंपराओं तथा सांस्कृतिक विविधता को भी अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में भी सरकार द्वारा यथोचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तभी पूर्वोत्तर राज्यों में समुदाय–आधारित ईको पर्यटन सही ढंग से फलफूल कर वहां के लोगों के जीवन में खुशहाली लाएगा।

(लेखक वरिष्ठ विज्ञान लेखक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं।)

ई–मेल : **prm_du@rediffmail.com**

आगामी अंक

जनवरी, 2018 – ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण

ग्रामीण पर्यटन और स्वच्छता

–धीप्रज्ञ द्विवेदी

भारत में ग्रामीण पर्यटन भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह करोड़ों लोगों के लिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध करा सकता है। अतः इसका पर्याप्त विकास आवश्यक है। लेकिन इसका विकास सीधे तौर पर स्वच्छता से जुड़ा है जिसमें स्वच्छ भारत अभियान बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं बल्कि नागरिकों की सहभागिता से अधिक से अधिक पेड़ लगाना, कचरामुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है।

भारत की लगभग 68.84 प्रतिशत आबादी भारत के लगभग 640,867 गांवों में निवास करती है (2011 की जनगणना)। हर एक गांव की अपनी विशेषता होती है। कहीं की संस्कृति बेहद समृद्ध है तो किसी स्थान की कला अनुपम है, कहीं की परम्पराएं अलग हैं तो कहीं कुटीर उद्योग अतुलनीय हैं। विश्व भर के लोग भारत के इस अद्वितीय विविधतापूर्ण ग्राम्य जीवन की झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं, और इसके लिए गांवों की यात्रा करते हैं, जिसे 'ग्रामीण पर्यटन' कहा जाता है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण पर्यटन, पर्यटन का वह स्वरूप है जिसके द्वारा ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को दर्शाया जाता है जिससे स्थानीय समुदाय को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से लाभ मिल रहा है। इसमें पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत के माध्यम से पर्यटन के अनुभव को समृद्ध किया जाता है। यह बहुआयामी है और इसमें कृषि पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, प्रकृति पर्यटन, साहसिक पर्यटन और पर्यावरण पर्यटन सब शामिल हैं। परंपरागत पर्यटन के विपरीत, ग्रामीण पर्यटन में कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं, यह अनुभव–उन्मुख है, कम आबादी वाले स्थानों में है, यह मुख्य रूप से प्राकृतिक वातावरण में है, यह मौसम और स्थानीय घटनाओं, विरासत, परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण पर आधारित है।

हम कह सकते हैं कि ग्रामीण पर्यटन, पर्यटन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें नगरों में रहने वाले निवासी, गांव और ग्रामीण जीवन को समझने और उनका आनंद लेने के उद्देश्य से गांवों में जाकर भ्रमण एवं निवास करते हैं। यह ग्रामीण जीवन की कला,संस्कृति तथा परंपराओं से संबंधित होता हैं एवं स्थानीय लोगों को रोजगार तथा आर्थिक विकास का अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही यह प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में भी सहायता प्रदान करता है। यह पारिस्थितिकी पर्यटन का हिस्सा भी हो सकता है। ग्रामीण पर्यटन के लिए विभिन्न बातें आवश्यक हैं, जैसे– वह स्थान ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो तथा निम्नलिखित में से कम से कम एक या एक से अधिक स्थितियां उपलब्ध हो, वहां ग्रामीण कार्यपद्धति जैसे कुटीर या छोटे लघु उद्योग, खुला वातावरण, प्रकृति का सानिध्य, धरोहर, परम्पराएं, सामाजिक गतिविधियां इत्यादि हों।

प्राचीन भारत में ग्रामीण पर्यटन के बहुत से उदाहरण उपलब्ध हैं। जब भगवान राम 14 वर्षों तक विविध स्थानों पर घूमते रहे, इसी प्रकार पांडवों ने भी अज्ञातवास के काल में विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। महावीर तथा गौतम बुद्ध ने भी विभिन्न गांवों में भ्रमण किया। भारतीय परंपरा में तीर्थाटन का अपना महत्व है, पर्यटन की दृष्टि से यह भी ग्रामीण पर्यटन से जुड़ी गतिविधि है, हम यह कह सकते हैं कि भारत में ग्रामीण पर्यटन का अतीत बेहद समृद्ध रहा है।

आधुनिक काल में ग्रामीण पर्यटन का इतिहास 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। शार्पले और शार्पले के अनुसार यह ग्रामीण पर्यटन 18वीं शताब्दी के बाद यूरोप में एक जाने–पहचाने क्रियाकलाप के रूप में लोकप्रिय हुआ। थामस कुक ने 1863 में स्विट्जरलैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का पहला पर्यटन अभियान आरंभ किया। तत्पश्चात इस उद्योग में अत्यधिक वृद्धि हुई। 20वीं शताब्दी

से ग्रामीण पर्यटन समस्त देशों में बढ़ता चला गया। 1990 के बाद भारत में भी धीरे–धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई।

भारतीय गांवों में ग्रामीण पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। भारत सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। 31 मार्च, 2011 को भारत सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 172 गांवों की सूची को जारी किया था, जो 29 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केंद्र जम्मू–कश्मीर, नगालैंड एवं सिक्किम में हैं जबकि उत्तर प्रदेश में केवल चार केंद्र हैं तथा बिहार में एक। इस सूची के बाद 30 जून, 2011 को मान्यता प्राप्त स्थानों की एक नई सूची जारी हुई जिसमें उपरोक्त 172 में से 52 को स्थान मिला। इसमें सबसे ज्यादा केंद्र नगालैंड के हैं जबकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक ही केंद्र है तथा बिहार और झारखंड से कोई केंद्र नहीं है। इस सूची में शामिल गांव कुछ खास विशेषताओं वाले हैं जैसे सूती या रेशम के कार्य में लगे गांव, प्राकृतिक सौंदर्य, लकड़ी के काम वाले गांव, कलमकारी से जुड़े, सांस्कृतिक क्षेत्र, नृत्य, चित्रकारी, बांस के कार्य में लगे गांव, मिट्टी की कलाकारी, ऐतिहासिक महत्व इत्यादि। इस सूची के बाहर भी ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने ग्रामीण पर्यटन को नई ऊंचाईयां दी हैं।

ग्रामीण पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र भी इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए आगे आया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने ग्रामीण पर्यटन के लिए चुने गए स्थानों की विभिन्न विशेषताओं के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो विभिन्न देशों के पर्यटक संचालकों को उपलब्ध कराया गया है।

ग्रामीण पर्यटन के द्वारा अब गांवों में धन आने लगा है तथा गांवों के भूले–बिसरे स्मारकों की भी खोज–खबर अब ली जाने लगी है। जो स्मारक तथा धर्मस्थल अब तक उपेक्षित थे अब उनकी भी साज–संभाल की जा रही है। ग्रामीण पर्यटन के द्वारा स्थानीय कलाओं को भी नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अनेक ग्रामीण परिवारों में जहां उच्च–स्तर की शिल्पकलाएं गुरु–शिष्य परंपराओं के अंतर्गत चली आ रही हैं जिनका अब तक उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता था, ग्रामीण पर्यटन के द्वारा इन कलाओं को भी महत्व प्राप्त हो रहा है।

आज हर राज्य में पर्यटन का अपना स्वतंत्र मंत्रालय है, उसके बहुत से विभाग हैं, निगम हैं, बोर्ड हैं और बाहर निजी क्षेत्र में भी अनगिनत संस्थान और इस उद्यम से जुड़े लाखों लोग हैं। हाल के वर्षों में भारत के ग्रामीण पर्यटन बाजार में वृद्धि का मतलब है कि कई भारतीय गांवों ने अब पर्यटक मानचित्र पर एक स्थान पाया है। न केवल यह ग्रामीणों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है, बल्कि आगंतुकों को उनके साथ बातचीत करने और ग्रामीण जीवन में एक दुर्लभ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। यह माना जाता है कि भारत का दिल उसके गांवों में है। उसे अनुभव करने का सबसे बेहतरीन तरीका ग्रामीण पर्यटन है। सुदूर ग्रामीण इलाकों में बने किले, हवेलियां और रावले, जो देखरेख के अभाव में खंडहर होते जा रहे थे, वे अच्छे–खासे हेरिटेज होटलों और रेस्तंराओं में तब्दील होकर कमाई का नायाब जरिया बन गए हैं।

स्वच्छ पर्यटन–स्वच्छता ही सेवा अभियान

स्वच्छ भारत मिशन के तहत पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता के प्रति आम लोगों में जागरूकता हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही, सभी पर्यटन केंद्रों और उनके आसपास के क्षेत्रों में समय–समय पर सफाई अभियान चलाया जाता है। हाल ही में **'स्वच्छ पर्यटन–स्वच्छता ही सेवा'** अभियान भी शुरू किया गया है। देश के सभी 3686 संरक्षित स्मारकों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए स्वच्छता कार्ययोजना के तहत वर्ष 2017–18 के वास्ते 43 करोड़ 20 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। पर्यटन मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के निर्देश के अनुसार स्वच्छ कार्ययोजना तैयार की है जिसके तहत पर्यटन के क्षेत्र में संबंधित पक्षों और स्कूल–कॉलेज के विद्यार्थियों, पर्यटकों आदि के लिए विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता से जुड़ी अघोसंरचना का निर्माण किया जाता है।

भारत के प्रसिद्ध ग्रामीण पर्यटक स्थलों में बेहद विविधता पाई जाती है। उदाहरणस्वरूप पंजाब के किला रायपुर में ग्रामीण ओलम्पिक होता है जिसमें बैलगाड़ी की दौड़ से लेकर कई अन्य खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है। यह ग्रामीण खेल–कूद प्रतियोगिता 1933 में प्रारंभ हुई थी और तब से अब तक लगातार आयोजित हो रही हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का गुलेहर गांव कलाप्रेमियों के स्वर्ग के रूप में जाना जा रहा है। इसे एक 'कला ग्राम' के रूप में विकसित किया जा रहा है। जर्मन–इंडियन आर्ट इम्प्रेसैरियो फ्रैंक श्लेकिट्मैन ने वहां एक परियोजना की स्थापना की, जिसमें गांव को एक समृद्ध कला केंद्र में परिवर्तित किया गया। यह गांव गद्दी एवं अन्य चरवाहा समूहों का गांव है जहां आप कला के साथ ही उन घुमंतु लोगों की जीवनशैली के बारे में भी जान सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर के दक्षिण में कुछ दूरी पर एक बिश्नोई गांव है जो ग्रामीण राजस्थान का एक प्रामाणिक अनुभव प्रदान करता है। बिश्नोई लोग प्रकृति का सम्मान करते हैं और इसके साथ सद्भाव में जीते हैं। उस गांव में छोटाराम प्रजापत का 2009 में स्थापित होम–स्टे बहुत प्रसिद्ध हो गया है जहां परंपरागत भव्य राजस्थानी आतिथ्य प्रदान किया जाता है। अन्य गतिविधियों में लोकनृत्य, ऊंट सफारी भी शामिल हैं। कच्छ के होडका गांव ने ग्रामीण पर्यटन को नई ऊंचाई दी है। इस गांव में अपनी ग्राम पर्यटन समिति है जो यहां होने वाली गतिविधियों को संचालित करती है। यहां के गांव रिजॉर्ट का नाम शाम–ए–सरहद (सीमा पर सूर्यास्त) है जहां रहते हुए पर्यटक लोककला, कारीगरी के साथ ही कच्छ के रन का

मौलीनौंग गांव, मेघालय

अद्वितीय अनुभव प्राप्त करते हैं। शाम–ए–सरहद की जिम्मेदारी ग्राम पर्यटन समिति की है। भारत के उत्तर–पूर्व क्षेत्र में सात बहनों का अंचल ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है साथ ही अभी लगभग अछूता है। वहां की जीवनशैली भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अलग है; साथ ही अभी भी चारों ओर अतुल्य प्राकृतिक सौंदर्य है। मेघालय के प्राकृतिक पुलों से लेकर त्रिपुरा की मूर्तियों तक उत्तर–पूर्व की विविधता अनुपम है, इसी कारण भारत सरकार द्वारा जारी सूची में सर्वाधिक गांव नगालैंड से हैं। मध्य एवं दक्षिण भारत की अपनी सांस्कृतिक–सामाजिक विशेषताएं हैं जैसे दुनिया का इकलौता संस्कृतभाषी गांव मुत्तुर कर्नाटक के शिमोगा जिले में अवस्थित है जहां हम आज भी प्राचीन भारतीय परम्पराओं को देख और महसूस कर सकते हैं। चेन्नई के निकट का वेदांथंगल गांव अपने पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध है। वहीं महाराष्ट्र का पुरुषवाडी गांव वर्ष के अलग–अलग मौसम में अलग–अलग अनुभव उपलब्ध कराता है। इन सबसे अलग मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले के मौलीनौंग गांव अपनी स्वच्छता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे 2003 में एशिया के सबसे स्वच्छ गांव होने का श्रेय प्राप्त हुआ था। इसे देखने दुनियाभर से सैलानी आते हैं। ग्रामीण पर्यटन के विकास ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक उन्नति के रास्ते खोले हैं।

भारत में इसके प्रचार के साथ–साथ इसको भुनाने का प्रयास भी देखा जा रहा है। पहले पर्यटन बड़े शहरों और ऐतिहासिक–धार्मिक–प्राकृतिक महत्व के स्थलों से जुड़ा उद्यम था जो अब लगातार उनके आसपास के ग्रामीण इलाकों और वहां के ग्रामीण जीवन को अपनी लालसा में लपेटता जा रहा है। उन ग्रामीणों का खान–पान, पहनावा, उनके तीज–त्यौहार और लोकानुरंजन के उत्सव अपने मूल स्वरूप से हटकर उनके आमोद–प्रमोद का हिस्सा होकर एक तरह के पर्यटक बाजार में तब्दील होते जा रहे हैं। शायद यह उसी का परिणाम है कि आज हर बड़े शहर में ऐसे अनोखे गांव और चौखी–अनोखी ढाणियां विकसित हो गई हैं, जो उन्हें शहर में ही गंवई खुलेपन और अपनेपन का आभास देने लगी हैं और सैलानियों के आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र भी बनती जा रही हैं।

पर्यटन भारत सहित अनेक देशों में आर्थिक विकास का एक प्रमुख साधन और विदेशी मुद्रा आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें विविध प्रकार के रोजगार सृजन की क्षमता है– सर्वाधिक विशेषज्ञता से लेकर अकुशल तक और इसीलिए अतिरिक्त रोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। यह एक समान विकास प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। और इसमें ग्रामीण पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

भारत के पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का निर्माण किया है और कई फैसले लिए हैं। **स्वदेश दर्शन योजना** के तहत 13 परिपथ वर्ष 2016 में तय किए गए जिनमें से कई सीधे तौर पर ग्रामीण पर्यटन से जुड़े हैं जैसे ग्रामीण परिपथ, जनजातीय परिपथ, पूर्वोत्तर भारत परिपथ इत्यादि।

सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ साझेदारी में लांच किया था। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजना में कुछ गतिविधियों को शामिल किया गया है, जो निम्नलिखित हैं–

i) गांव के परिवेश में सुधार। बागवानी जैसी गतिविधियों, पार्कों के विकास,बाड़ लगाना, यौगिक दीवार आदि के द्वारा ऐसा होगा;

ii) पंचायत की सीमाओं के भीतर सड़कों में सुधार, इसमें गांव को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क शामिल नहीं होगी;

iii) गांव में प्रदीप्ति;

iv) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार और सीवरेज प्रबंधन;

v) पथ के आसपास सुविधा निर्माण;

vi) सीधे पर्यटन से संबंधित उपकरणों की खरीद, जैसे पानी के खेल, साहसिक खेल, पर्यावरण के अनुकूल तरीके, पर्यटन क्षेत्र में जाने के लिए परिवहन;

vii) स्मारकों का नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण;

viii) चिह्नित करना;

ix) स्वागत;

स्वच्छ भारत–स्वच्छ पर्यटन

साफ–सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय अभियान चला रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वच्छता के असमान मानदंडों का पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर, स्वच्छता से हमारे सांस्कृतिक स्थलों की अनोखी सुंदरता, हमारे प्राकृतिक स्थलों की मनोरम छटा और वास्तु कलात्मक धरोहरों की समृद्धि परिलक्षित होती है।

x) पर्यटन से सीधे संबंधित अन्य कार्य गतिविधियां;
xi) पर्यटक आवास।

उपरोक्त गतिविधियों में से कई ऐसी हैं जो सीधे तौर पर स्वच्छता से जुड़ी हैं जैसे गांव के परिवेश में सुधार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवर तंत्र, पथ के आसपास की सुविधाएं इत्यादि।

भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा वहां सुविधाओं की कमी है। गांव में जाना आसान है लेकिन यह सिर्फ वहां जाने का सवाल नहीं है– वहां सैलानियों के रहने और उनकी बुनियादी स्वच्छता की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाओं की जरूरत है। हमारे गांवों में खुले में शौच करना एक समस्या थी। इस समस्या के समाधान के लिए भारत में हुए कुछ सफल प्रयासों का उदाहरण लिया जा सकता है जैसे 1991 में हेल्प टूरिज्म नामक संस्था ने पश्चिम सिक्किम में एक गांव आधारित पर्यटन पहल के लिए एक डेमो परियोजना शुरू की। इसमें बुनियादी स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास हुआ। गांव के सभी 40 परिवारों को इसमें शामिल किया गया जो रहने के स्थान या भोजन की सुविधा या दोनों उपलब्ध कराते थे। प्रारंभ में इसमें ट्रेकर्स या पर्वतारोही जैसे विशेष रुचि वाले यात्रियों को लक्षित किया गया। वहां की सुविधाएं स्वच्छ और आरामदायक हैं, पांच सितारा नहीं, क्योंकि ध्यान ग्रामीण अनुभव पर है, और कीमत का भी ध्यान रखा गया। बाद में यह परियोजना पूर्वोत्तर के 22 स्थानों पर सफलतापूर्वक लागू की गई।

वर्तमान में बुनियादी स्वच्छता के क्षेत्र में भारत में काफी प्रगति हुई है। 2 अक्तूबर, 2014 से 27 नवंबर 2017 के बीच 5,47,25,200 से अधिक घरेलू शौचालय बने हैं, 2,77,912 गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए हैं, 238 जिले और 7 राज्य भी खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। बुनियादी स्वच्छता के क्षेत्र में यह सफलता निश्चित रूप से पर्यटकों को आकर्षित करेगी। इसके साथ ही शौचालय की उपलब्धता क्षेत्र के परिवेश में सुधार में भी सहायता करेगी। साथ ही इससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। 2 अक्तूबर, 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया जिसका लक्ष्य देश के सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना है तथा 2019 में महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस के पहले देश के सभी गांवों को पूरी तरह खुले में शौचमुक्त बनाना है साथ ही, ठोस एवं तरल अपशिष्ट निपटान की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों का सही एवं सुचारू प्रबंधन सभी हितधारकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इनका सही प्रबंधन नहीं होने के कारण क्षेत्र में न केवल रुग्णता की समस्या सामने आती है बल्कि दुर्गंध के साथ अन्य प्रकार के प्रदूषण का सामना करना पड़ता है जिसका सीधा असर पर्यटन के ऊपर पड़ता है। अतः इनका निराकरण आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर ठोस और तरल अपशिष्टों में प्राकृतिक रूप से जैविक पदार्थ होते हैं जिन्हें सही प्रबंधन द्वारा पुनः उपयोग के लायक बनाया जा सकता है। इससे न केवल

> ऊर्जा संरक्षण के नए और नवोन्मेषी तरीके खोजने होंगे। यह पर्यटन संस्थानों और अतिथ्य इकाइयों पर निर्भर होना चाहिए कि वे एक ऐसे तरीके से काम करें जोकि पानी और ऊर्जा की खपत कम करने में सक्षम हो और रचनात्मक पुर्नचक्रण तथा कूड़े प्रभावी रूप से निपटाने को सुनिश्चित करें।

वातावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी बल्कि लोगों के लिए रोजगार और आय का जरिया भी बनाया जा सकता है। साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी। अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपचयन और निवारण, पुनः उपयोग, पुनःचक्रण तथा पुनःप्राप्ति के तरीकों का उपयोग होना चाहिए। गांव में प्रदीप्ति के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग हो सकता है जैसे गोबर गैस का उपयोग या पराली के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन इत्यादि।

इसके साथ ही गांव की सुंदरता को बढ़ाने का प्रयास भी होना चाहिए जिसके लिए बागवानी को बढ़ावा देना, जल स्रोतों का सौंदर्यीकरण, स्थानीयता के अनुसार वृक्षारोपण, क्रीड़ा–स्थलों का निर्माण, प्राकृतिक बाड़ का निर्माण, सार्वजनिक स्थानों एवं घरों के ऊपर स्थानीय कलाकृतियों का निर्माण (उदाहरणस्वरूप मधुबनी रेलवे स्टेशन को अक्तूबर, 2017 में मधुबनी चित्रकला से सुसज्जित किया गया है), धरोहरों का संरक्षण जैसी गतिविधियां सैलानियों को आकर्षित करने में सहायक होंगी।

पर्यटन से स्वच्छता के सीधे जुड़े होने के कारण ही पर्यटन मंत्रालय स्वच्छ भारत अभियान से सीधे तौर पर जुड़ा है, साथ ही यह पर्यावरण संरक्षण के अपने दायित्व को भी पूरा कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत परियोजना मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित की गई है, जो पूरे देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करती है जैसे थीम–आधारित स्वच्छता अभियान चलाना (1–15 मार्च), थीम–आधारित स्वच्छता पखवाड़ा मनाना (16–30 मई एवं 15–30 सितंबर), स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप्लिकेशन का निर्माण इत्यादि।

पर्यटन स्थलों पर पर्यावरण विकास के उपाय

पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की बड़ी संख्या में आवाजाही को ध्यान में रखते हुए वहां पर्यावरण की सुरक्षा एवं विकास के लिए विशेष ध्यान देना जरूरी है। शुद्ध पर्यावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। आबोहवा की शुद्धता के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपरण किया जाना चाहिए। कहीं पर भी जल प्रभाव और गंदगी न हो, इस पर ध्यान दिया जाए। स्वास्थ्य की दृष्टि से ही स्वीकृत मानदंडों का पालन करते हुए ही निर्माण कार्य किए जाएं। पर्यावरण स्वच्छ एवं स्वस्थ हो तो पर्यटक भी ऐसी जगह पर छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। यही कारण है कि पर्यटकों को हमेशा पहाड़ या समुद्र तट आकर्षित करते रहे हैं। महानगरों के लोग शांति और साफ आबोहवा की तलाश में ही गांवों की ओर का रुख करते हैं।

(लेखक पर्यावरण विषय के विशेषज्ञ हैं। स्वास्थ्य जागरूकता पर कार्य करने वाली संस्था 'स्वस्थ भारत' के संस्थापक सदस्य भी हैं।)
ई–मेल : dhimesh.dubey@outlook.com

पर्यटन पर्व 2017

पर्यटन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर 5 से 25 अक्तूबर, 2017 तक देश भर में तीन सप्ताह के पर्यटन पर्व का आयोजन किया गया। यह समारोह पर्यटन के लाभ, देश की विभिन्न सांस्कृतियों, भिन्नताओं और सबके लिए पर्यटन के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। पूरे देश में पर्यटन पर्व में 5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया।

5 अक्तूबर, 2017 को पर्यटन सचिव श्रीमती रश्मि वर्मा द्वारा इंडिया गेट पर साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ पर्यटन पर्व की गतिविधियों को शुरू किया गया। नई दिल्ली, इंडिया गेट से कुतुब मीनार तक आयोजित इस साइकिल रैली मे लगभग 80 साइकिल चालकों ने भाग लिया जिनमें पर्यटन उद्योग हितधारकों के सदस्यों, केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों, डॉक्टरों, शिक्षकों सहित छात्र शामिल थे।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और हितधारकों के सहयोग से आयोजित किए गए पर्यटन पर्व का हर दिन गतिविधियों से भरा था। देश के सभी क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों पर काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली और लोगों ने बढ़–चढ़कर आयोजनों में भागीदारी की। पूरे देश के विभिन्न शहरों में पर्यटन जागरूकता वॉक एंड रन का आयोजन किया गया जिसमें होटल प्रबंधन संस्थान के सैकड़ों छात्रों सहित स्थानीय हितधारकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

केरल की राज्य सरकार द्वारा पर्यटन पर्व के हिस्से के रूप में लाइट हाउस बीच, कोवलम में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। तमिलनाडु सरकार के सहयोग के साथ इंडिया टूरिज्म, चेन्नई ने मम्मनलपुरम में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। राष्ट्रीय रूर्बन मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्पितुक गोम्पाम, लेह में पर्यटन के ढांचे, पर्यटन सूचना केन्द्र, मनोरंजन/थीम पार्क और पार्किंग सुविधाओं के विकास के लिए स्पितुक रूर्बन कलस्टर में पर्यटन परियोजनाओं की शुरुआत की। तमिलनाडु मे यात्रा मार्ट का आयोजन किया गया जो पर्यटन समुदाय से हितधारकों के लिए एक वैश्विक आयोजन था। इसमें राज्य की संस्कृति, विरासत और पर्यटन क्षमता प्रदर्शित की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने चंदेरी स्थित होटल ताना–बाना में एक खाद्य महोत्स्व का आयोजन किया तथा जबलपुर के होटल कलचुरी रेजीडेंसी में अन्तर्राष्ट्रीय सतत पर्यटन वर्ष पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। पर्यटन पर्व के रूप में गुजरात सरकार ने पाटन जिले के सिद्दपुर में पर्यटन की थीम 'यूथ इन एक्शन' पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। राजस्थान सरकार ने उदयपुर में दिवाली मेले का आयोजन किया वहीं उत्तराखंड सरकार ने उत्तरकाशी में यमुनोत्री महोत्सव का आयोजन किया। आईटीडीसी द्वारा होटल कलिंगा अशोक में तटीय खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया।

पर्यटन पर्व के समारोह में तीन तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया–

देखो अपना देश : भारतीयों को अपने देश में घूमने के लिए प्रोत्साहित करना।

सबके लिए पर्यटन : देश के सभी राज्यों में पर्यटन संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पर्यटन एवं गर्वेनेंस : देशभर में विभिन्न विचारों पर भागीदारों के साथ पारस्परिक सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की गई।

पर्व के दौरान रेलवे, सड़क परिवहन व शहरी विकास जैसे कई मंत्रालयों ने पर्यटन स्थलों व उसके आस–पास के इलाकों में साफ–सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया। पर्यटन मंत्रालय ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटक स्थलों की साफ–सफाई का अभियान चलाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम भी चला रहा है, जिससे लोगों को ऐतिहासिक स्थलों का महत्व पता चले और वह उनकी देखभाल व साफ–सफाई करने के लिए प्रेरित हों।

इस पूरे पर्व के दौरान स्थानीय नागरिकों विशेष तौर पर युवाओं को इसमें जोड़ा गया। पर्यटन उद्योग में रोजगार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर असीम संभावनाएं हैं और इसके लिए युवाओं को पर्व के दौरान जानकारी दी गई। यही नहीं कई राज्यों में टैक्सी, ऑटो, रिक्शा चालकों, होटल व्यवसायों व अन्य लोगों को पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार करने व उनकी मदद करने के तरीकों की भी जानकारी दी गई। पर्यटन पर्व जैसे आयोजन बेहद महत्वपूर्ण हैं जो भारत के पर्यटन उद्योग का परिदृश्य बदलने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। इससे जहां घरेलू पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा, वही विदेशी सैलानियों को और अनुकूल वातावरण देश में उपलब्ध हो सकेगा।

19 नवंबर, 2017 को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया

19 नवंबर, 2017 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर बिहार में पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया गांव में आयोजित चेतना यात्रा

विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर राज्यों और जिलों द्वारा **स्वच्छ भारत मिशन** के तहत देश भर में बड़ी संख्या में व्यवहार परिवर्तन और शौचालय उपयोग गतिविधियों का आयोजन किया गया। जुलूस निकाले गए, चर्चाओं का आयोजन किया गया और स्कूल के बच्चों ने कई नवीन गतिविधियों में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया जिनमें शौचालय की पहुंच और उपयोग के महत्व पर प्रकाश डाला गया। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की वरिष्ठ केंद्रीय स्तर की टीम ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में तुरकोलिया गांव में दो पिट वाले शौचालयों के निर्माण में ग्रामीणों की सहायता करने हेतु श्रमदान करके इस पहल की अगुवाई की।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में सचिव श्री परमेश्वर अय्यर के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारी 17 नवंबर, 2017 को गांव में श्रमदान हेतु गए। तीन दिन के इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य था अधिकारियों को अधिक समय तक गांव में ग्रामीणों के बीच रहने का अवसर मिले जिससे वे सीधे ग्रामीणों के साथ बातचीत कर उनके व्यवहार परिवर्तन में अपना योगदान कर सकें और उनकी चुनौतियों और आकांक्षाओं पर चर्चा कर सकें। यह जिला देश में सबसे कम स्वच्छता कवरेज वाले जिलों में से एक है। चंपारण शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक समारोहों के एक भाग के रूप में टीम ने इस अभ्यास के लिए चंपारण जिले को चुना। टीम ने ग्रामीणों को अपने घरों मे दो पिट वाले शौचालयों के निर्माण और उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया।

श्रमदान के पहले दिन के बाद रात्रि चौपाल के तहत ग्रामीणों को फिल्म 'टॉयलेट एक प्रेमकथा' दिखाई गई।

मंत्रालय और बिहार राज्य की संयुक्त टीम ने गांव में दो पिट वाले शौचालयों को खोदने, पिट के भीतर ईंट रखने और शौचालय के निर्माण में ग्रामीणों के साथ सहयोग किया। विश्व शौचालय दिवस पर गांव को ओडीएफ घोषित किया गया।

टीम ने चंपारण में गांधीजी को विभिन्न स्मारकों में श्रद्धांजलि अर्पित की। सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर की अगुवाई वाली एक टीम ने स्थानीय निगरानी समितियों के साथ गांवों में सुबह खुले मे शौच की स्थिति का आकलन किया। उन लोगों के साथ गहन पारस्परिक संपर्क किया गया जो खुले में शौच के लिए आए थे। टीम ने लोगों को अपने शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए घरों का भी दौरा किया। गांव की महिलाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक बातचीत में भाग लिया। तुरकोलिया स्कूल में क्षेत्र की छात्राओं के साथ एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया।

विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर की गई इस पहल से चंपारण में स्वच्छ भारत कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। बिहार में मंत्रालय अपने स्वच्छता कार्यक्रमों को गति देने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। ग्रामीणों के साथ बातचीत में, सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर और उनकी टीम ने शौचालय के उपयोग को लेकर समुदाय के व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। उत्साहपूर्वक ग्रामीणों ने अपने गांव को जल्द ही ओडीएफ बनाने का वायदा किया।

एक नजर आंकड़ों पर

- **अक्तूबर 2014 से अब तक बने कुल शौचालय (27 नवंबर, 2017) तक**
- घरों में बने शौचालय–5,47,25,200
- खुले में शौचमुक्त गांव –2,77,912
- नमामि गंगे के तहत खुले मे शौचमुक्त गांव–4464
- खुले में शौचमुक्त जिले –238
- खुले में शौचमुक्त राज्य–7

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का एक वर्ष

सरकार ग्रामीण आवास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर

माननीय प्रधानमंत्री ने एक साल पहले 20 नवंबर, 2016 को आगरा से 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' का शुभारंभ किया था। लाभार्थियों के पंजीकरण, भू–टैगिंग और खाता सत्यापन के बाद एक करोड़ नए मकानों का निर्माण कार्य 31 मार्च, 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 51 लाख मकानों का निर्माण कार्य 31 मार्च, 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया।

इस योजना के शुभारंभ के बाद लाभार्थियों के पंजीकरण, भू–टैगिंग, खाता सत्यापन, इत्यादि की प्रक्रिया पूरी करने में कुछ महीने लग गए। 55.85 लाख मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और इस दिशा में कार्य प्रगति पर है। इनमें से लगभग 30 लाख मकानों का निर्माण कार्य छत तक पूरा हो चुका है, जबकि 15 लाख मकानों का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। 20 नवम्बर, 2017 तक 9.03 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 10 लाख मकानों का निर्माण कार्य 30 नवम्बर, 2017 तक, 15 लाख मकानों का निर्माण कार्य 31 दिसम्बर, 2017 तक, 25 लाख मकानों का निर्माण कार्य 31 जनवरी, 2018 तक, 35 लाख मकानों का निर्माण कार्य 28 फरवरी, 2018 तक और 51 लाख मकानों का निर्माण कार्य 31 मार्च, 2018 तक पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

नए डिजाइनों, स्थानीय भवन निर्माण सामग्री, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण, परिसम्पत्तियों की भू–टैगिंग और आईटी–डीबीटी प्लेटफॉर्म के जरिए लाभार्थियों के खातों में भुगतान सीधे भेजने से पारदर्शितापूर्ण, बाधामुक्त और गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। सभी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश संबंधित लाभार्थियों की सहूलियत के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनके मकानों का निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके। सामाजिक–आर्थिक जनगणना (एसईसीसी 2011) के उपयोग, ग्रामसभा द्वारा सत्यापन और भू–टैगिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से इसमें न्यूनतम समावेशी त्रुटियां सुनिश्चित हुई हैं। इस गरीब हितैषी कार्यक्रम के तहत केवल वही लोग लाभार्थी हैं, जो बेघर हैं अथवा कच्ची छत एवं एक कमरे वाले कच्चे घरों में या कच्ची छत एवं दो कमरों वाले कच्चे घरों में रहते हैं। गरीबों को सशक्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। सामान्य मौजूदा स्थानीय डिजाइनों का अध्ययन करने के बाद सर्वश्रेष्ठ संस्थानों द्वारा इन घरों के डिजाइन तैयार किए गए हैं। इन मकानों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा अपनी जरुरतों के अनुसार किया जाता है। इन मकानों से न केवल ग्रामीण परिदृश्य बदल रहा है, बल्कि देशभर के गांवों में सामाजिक बदलाव भी सुनिश्चित हो रहा है। गरीबों को सुरक्षित घर मिल रहे हैं और अब वे शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पेयजल सुविधा इत्यादि के साथ सम्मान से जीवनयापन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गवर्नेंस संबंधी सुधारों और विकास पर इस्पात एवं सीमेंट की बढ़ती मांग के असर का अध्ययन नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

सामाजिक बदलाव पर अलग से अध्ययन कराया जा रहा है, ताकि एक 'बढ़िया आवास' कार्यक्रम के असर को सही ढंग से समझा जा सके। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति के बारे में जानकारी Awaassoft.nic.in पर जाकर प्राप्त कर सकता है, जिस पर भू–टैग की गई फोटो और लाभार्थियों के साथ–साथ उन्हें किए गए भुगतान का पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध है। ❑

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2015-17
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2015-17
1 दिसंबर, 2017 को प्रकाशित एवं 5-6 दिसंबर, 2017 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2015-17
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2015-17
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

Think IAS... | दृष्टि The Vision | Think Drishti

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ☑ आगामी मुख्य परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण सामग्री।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिये प्रत्येक महीने सामान्य अध्ययन के विभिन्न खण्डों के रिवीज़न के लिये 'टू द पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली, द हिन्दू आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ☑ मुख्य परीक्षा 2017 के सॉल्व्ड पेपर्स।
- ☑ तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिये प्रेरणादायक कॉलम।
- ☑ इंटरव्यू की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल नि:शुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट: www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 8130392359

For business/advertising enquiry, Call - 8130392355

Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

प्रकाशक और मुद्रक: डॉ. साधना राउत, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, संपादक: ललिता खुराना